राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 7 अंक 322

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, मंगलवार, 30 अप्रैल, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

अंकगणित से नहीं सरकार के प्रयास से तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत

>> 6

जागरण विशेष

बढ़ेगी क्षमता तो ज्यादा चलेंगे इलेक्ट्रानिक डिवाइस

गोरखपुर: इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी फुल चार्ज होने के बाद अब 25 से 50 प्रतिशत अधिक चलेगी। यह संभव होगा गैलियम आक्साइड मोस्फेट ट्रांजिस्टर से, जिसे तैयार किया है शोधार्थी डा. नरेंद्र यादव ने। ● पेज-7

संपादकीय

आंकड़ों के अभाव में असंतुलित विमर्श: कई मुद्दे चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में होते हैं, लेकिन प्रामाणिक आंकड़े न होने से उन पर सार्थक बहस नहीं हो पाती। **शिवकांत शर्मा** का दृष्टिकोण।

न्यायपालिका की गरिमा पर आघात: नेताओं एवं वकीलों को यह समझना होगा कि अदालत का हर फैसला उनके मन मुताबिक नहीं हो सकता। **सीबीपी श्रीवास्तव** का आलेख। ● पेज-8

विमर्श

सब्सिडी के वितरण से जुड़ी विसंगतियां: अधिकांश राजनीतिक दलों ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का जीवन स्तर उन्नत करने की दिशा में कार्य किए जाने के वादे किए हैं। परंतु दीर्घकालिक विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिले इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। **डा. विकास सिंह** का आलेख।

पीएचडी से संबंधित बदलाव: यूजीसी द्वारा इस वर्ष से नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। पीएचडी में नामांकन के लिए भी यह एक आवश्यक पात्रता होती है। संबंधित बदलाव को दर्शा रहे हैं, **सुधीर कुमार**। ● पेज-9

आइपीएल
आज का मैच
लखनऊ सुपरजायंट्स
vs मुंबई इंडियंस
शाम 7:30 बजे | स्थान: लखनऊ
प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स/जियो सिनेमा

सप्तरंग
अंतस और अध्यात्म का
आत्म-परमात्म योग
पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य
● पेज-13

शाह के फेक वीडियो मामले में तेलंगाना के सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया

कार्रवाई ▶ रेवंत रेड्डी समेत छह लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भेजा नोटिस

जेएनएन, नई दिल्ली

- रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री के फेक वीडियो को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किया था पोस्ट
- रेड्डी को एक मई को दिल्ली बुलाया, अपना मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट भी लेकर आने को कहा
- दिल्ली पुलिस ने हैदराबाद में एक शख्स को हिरासत में लिया, असम पुलिस ने भी एक को किया गिरफ्तार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिट किए गए वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक आपरेशंस (आइएफएसओ) यूनिट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए एक मई को दिल्ली बुलाया है। पुलिस ने उन्हें स्वयं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रानिक गैजेट भी साथ लेकर आने को कहा है, क्योंकि रेड्डी ने भी एक एडिट वीडियो 'एक्स' पर पोस्ट किया था। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना कांग्रेस के छह लोगों को नोटिस भेजा है। मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम हैदराबाद पहुंच चुकी है। वहां भी पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, इस मामले में असम पुलिस ने एक व्यक्ति रीतम सिंह को गिरफ्तार किया है। रीतम सिंह की एक्स की प्रोफाइल के अनुसार, वह कांग्रेस से जुड़ा है और पार्टी के वार रूम कोआर्डिनेटर के रूप में काम करता है।

तीसरे चरण के चुनाव के पहले फेक वीडियो के माध्यम से भाजपा को एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का विरोधी साबित करने की कोशिश की गई है। फेक वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह को आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए उसे खत्म करने का एलान करते हुए दिखाया गया था, जबकि असली वीडियो में शाह एसटी, एससी और ओबीसी आरक्षण को बनाए रखने की बात कहते हैं।

गृह मंत्रालय ने दो दिन पहले दिल्ली पुलिस को दी थी शिकायत पेज>>6

रेवंत रेड्डी। फाइल/एएनआइ

दिल्ली पुलिस के नोटिस से डरेंगे नहीं : रेवंत रेड्डी

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छेड़छाड़ किए गए वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस के नोटिस से डरेंगे नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभी तक चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ईडी और सीबीआइ का ही दुरुपयोग कर रहे थे। मगर अब वह दिल्ली पुलिस का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर कुछ पोस्ट डाले गए थे, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस के अफसर तेलंगाना गांधी भवन (प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय) पहुंच गए। उनके पास नोटिस था, जिसमें बताया गया था कि वह तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेंगे। इसका मतलब है कि मोदी जी चुनाव जीतने के लिए अब दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं।

सच और मुद्दों पर नहीं लड़ पा रहे तो फैला रहे झूठे वीडियो : मोदी

मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में टेक्नोलाजी का बड़ा उपयोग और महत्व है। मैं खुद भी इसका बड़ा समर्थक हूं। मैंने इंटरनेट मीडिया का उपयोग हमेशा जनता-जनार्दन से जुड़ने के लिए किया है। मगर आजकल एक बात परेशान करनेवाली है। लोकतंत्र प्रेमी हर व्यक्ति को शर्मसार करनेवाली है। जो लोग भाजपा और राजग से सच्चाई, मुद्दों और अपने काम के आधार पर आमने-सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वे अब इंटरनेट मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। वे हमारे पार्टी के अलग-अलग नेताओं की आवाज में फर्जी वीडियो बनाकर गलत संदेश फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि उन्हें जब भी कोई फेक वीडियो मिले, वे तुरंत पुलिस को सूचित करें।

'सीएम की गिरफ्तारी के बाद ठप हो गई है दिल्ली सरकार'

विनीत त्रिपाठी ● जागरण

- एमसीडी आयुक्त को पांच करोड़ की व्यय सीमा से मुक्त कर दिया शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश
- दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की स्वीकारोक्ति को हाई कोर्ट ने बनाया फैसले का आधार

नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) स्कूलों के छात्रों को वर्दी व शैक्षिक सामग्री नहीं देने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सख्त आदेश पारित किया है। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के निर्देश पर अदालत में दिए गए बयान को रिकार्ड करते हुए अदालत ने माना है कि सौरभ भारद्वाज ने स्वीकार किया है कि एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्ति में किसी भी वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंजूरी की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि मंत्री की यह स्वीकारोक्ति इस तथ्य के समान है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ठप हो गई है। अदालत ने कहा कि दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक नहीं है और यह ऐसा पद है जहां पदाधिकारी को 24 घंटे उपलब्ध रहना होता है। इन तल्ख टिप्पणियों के साथ ही अदालत ने एमसीडी आयुक्त को पांच करोड़ की व्यय सीमा से मुक्त करते हुए छात्रों को पाठ्यपुस्तकें और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

जेल जाने के बावजूद पद पर बने रहने के निर्णय पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री बने रहने का निर्णय केजरीवाल का निजी फैसला है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि सीएम के उपलब्ध नहीं होने के कारण छोटे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा और वे स्कूल का पहला सत्र पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री व वर्दी के बिना गुजारेंगे। अदालत ने एमसीडी स्कूलों में वर्दी व शैक्षिक सामग्री नहीं उपलब्ध कराने के विरुद्ध गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की याचिका पर दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए अदालत ने कहा कि मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए तत्परता से काम करने में असमर्थता एमसीडी स्कूलों में नामांकित छात्रों की दुर्दशा के प्रति उसकी उदासीनता को दर्शाती है। अदालत ने कहा कि यह एमसीडी छात्रों के मौलिक अधिकारों का जानबूझकर किया गया हनन है।

पीएम बोले, जब तक मोदी जिंदा है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा

ओमप्रकाश तिवारी ● जागरण

- ऐसे मंसूबे रखने वालों को यह देश हमेशा के लिए राजनीति के नक्शे से मिटा देगा
- जो लोग भारत में आतंकवादियों को भेजते थे, उनको पड़ रहे आज आटे के लाले

पुणे : कांग्रेस इन दिनों भाजपा पर तीसरी बार सत्ता मिलने पर संविधान बदलने की आशंका व्यक्त कर रही है। लेकिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को उसी के बिछाए जाल में फंसा दिया। कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में डालकर आरक्षण देने के माडल का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। उसकी इस कोशिश को मोदी जीते जी पूरा नहीं होने देगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र में तीन रैलियों को संबोधित किया। पहले सोलापुर, फिर सतारा और उसके बाद पुणे में भाजपा एवं राजग प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले लोग अब धर्म के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी को संसद और संविधान द्वारा मिले हुए आरक्षण पर डाका डालकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में ऐसा करने की शुरुआत भी कर दी है। अब वह संविधान बदलकर यही फार्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस और आइएनडीआइए को चेतावनी देते हुए कहा, 'मोदी जब तक जिंदा है, जब तक जनता-जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने की कोशिश और संविधान बदलने की कोशिश आप पूरी नहीं कर पाएंगे। मोदी ऐसा कभी नहीं होने देगा। लिख के रखना। और जो लोग ये मंसूबे रखते हैं, उन्हें यह देश हमेशा के लिए राजनीति के नक्शे से मिटा देगा।' मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है, लेकिन उसके लिए दलितों, आदिवासियों या ओबीसी के अधिकार नहीं छीने।

कांग्रेस के शासनकाल में ही भगवा आतंकवाद की गढ़ी गई थ्योरी पेज>>4

कर्नाटक के बागलकोट में सोमवार को चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत प्रभु रामलला का चित्र भेंट कर किया गया। प्रेट्र >>

कांग्रेस को इंदौर में भी सूरत जैसा झटका, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी विहीन हुई पार्टी

नईदुनिया, इंदौर

- नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे और ली सदस्यता
- कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के गृहनगर में चौंकाने वाला राजनीतिक घटनाक्रम
- कांग्रेस के डमी उम्मीदवार का नामांकन पहले ही हो चुका है निरस्त

कांग्रेस को इंदौर में सूरत जैसा झटका लगा है। सोमवार को चौथे चरण के चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन चौंकाने वाले राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस उम्मीदवार विहीन हो गई। इंदौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया। भाजपा के लिए चुनाव मैदान यहां लगभग साफ हो गया है। कांग्रेस के लिए यह आघात इसलिए भी अधिक पीड़ादायी है, क्योंकि इंदौर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृहनगर है। गुजरात के सूरत में कांग्रेस को इसी तरह का झटका लग चुका है। वहां नामांकन रद होने से कांग्रेस चुनाव से पहले ही मैदान से बाहर हो चुकी है।

इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार की नाम वापसी के बाद इस सीट पर मतदान की अब औपचारिकता ही शेष है। नाम वापस लेने के बाद निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से अक्षय बम कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के साथ बाहर निकले। सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे और भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इंदौर लोकसभा क्षेत्र से डमी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारे गए कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार मोती सिंह पटेल का नामांकन फार्म पहले ही निरस्त हो चुका है।

अक्षय ने असहयोग का आरोप लगाया : अक्षय कांति बम ने कांग्रेस से किनारा करने के पीछे किसी तरह के दबाव या प्रभाव से इन्कार किया है। कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव में असहयोग कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने नाम वापस ले लिया। चौथे चरण में 13 मई को इंदौर में मतदान होगा। नाम वापसी के अंतिम दिन सोमवार को नौ उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, तीन के नामांकन निरस्त हो चुके हैं। अब चुनाव मैदान में 14 प्रत्याशी हैं, जिनमें प्रमुख दलों में सिर्फ भाजपा और बसपा के प्रत्याशी हैं।

आइएनडीआइए को दूसरा झटका पेज>>5

इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम (लाल घेरे में) ने सोमवार को अपना नाम वापस ले लिया और भाजपा के नेता एवं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। एएनआइ

बाबा रामदेव की फार्मेसी की 14 औषधियों के लाइसेंस निलंबित

जागरण संवाददाता, देहरादून

- सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग की कार्रवाई

इन दवाइयों के हुए लाइसेंस निलंबित

श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, ब्रोन्कोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्त वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लीवोरिट, पतंजलि दृष्टि आई ड्राप, आइग्रिट गोल्ड।

दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग ने योगगुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी ने दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की 14 औषधियों के लाइसेंस निलंबित करते हुए उनके निर्माण पर रोक लगा दी है। उक्त दवाओं में ब्लड प्रेशर, मधुमेह, ग्लूकोमा, उच्च कोलेस्ट्राल आदि की दवाएं शामिल हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरिद्वार ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में वाद भी दायर किया है, जिसकी सुनवाई दस मई को होनी है।

दरअसल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की हुई है, जिसपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आइएमए का तर्क है कि पतंजलि ने आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का भ्रामक दावा किया है। कोर्ट ने इस मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था। वहीं, राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी को भी कड़ी फटकार लगाई थी। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है।

महासमर 2024

विमर्श ही नहीं, रुख भी बदला, अब चुनाव मोदी बनाम जनता पेज>>3

सत्ता में आए तो जातिवार गणना और आर्थिक सर्वे कराएंगे : राहुल पेज>>4

नामांकन वापसी के बाद चौथे चरण के मुकाबले की तस्वीर साफ पेज>>5

'बंगाल सरकार कैसे बनी पक्षकार'

नई दिल्ली: संदेशखाली मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि निजी व्यक्ति के लिए वह कैसे पक्षकार बनी। (पेज-6)

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
Scan QR CODE to get UPSC Preparation Insights from VisionIAS Topper's Talk
8468022022 www.visionias.in

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

16 in Top 20 Selections in CSE 2023
Across various programs of VISIONIAS

हिन्दी माध्यम टॉपर

1 AIR ADITYA SRIVASTAVA
2 AIR ANIMESH PRADHAN
5 AIR RUHANI
53 AIR मोहन लाल

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन 2025

प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

दिल्ली: 10 अप्रैल, 9 AM | 14 मई, 9 AM

अधिक जानकारी, रजिस्टर या फ्री काउंसलिंग के लिए हमारे एक्सपर्ट से बात करें

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रारंभिक ✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट
मुख्य ✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

ENGLISH 2024: 5 MAY दिल्ली 2024: 5 मई
ENGLISH 2025: 5 MAY दिल्ली 2025: 5 मई

DELHI • 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, Delhi | CONTACT: 8468022022, 9019066066
• GTB Nagar Enquiry and Classroom Centre, Above GTB Nagar Metro Station Gate No. 2, Delhi - 110009
AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

जूना अखाड़ा की पहल

मतांतरण रोकने के लिए अखाड़े ने बढ़ाई सक्रियता, 52 संन्यासी महामंडलेश्वर बनाने के लिए हुए चयनित

वंचित समाज के संन्यासियों को महामंडलेश्वर बनाने की मुहिम तेज

शरद द्विवेदी ● जागरण

प्रयागराज : प्रभु श्रीराम व भगवान दत्तात्रेय की भक्ति में लीन महेंद्रानंद गिरि को जूना अखाड़ा ने जगदगुरु की उपाधि प्रदान की। महेंद्रानंद वंचित समाज से आते हैं, लेकिन धर्म के प्रति उनका समर्पण देखते हुए अखाड़े ने जगदगुरु बना दिया। अब महेंद्रानंद वंचित समाज के दूसरे लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने की मुहिम में जुटे हैं। वर्ष 2018 में महामंडलेश्वर बनने वाले वंचित समाज के कन्हैया प्रभुनंद गिरि कहते हैं धर्मगुरु बनने के बाद उनका जीवन बदल गया। जो हेय दृष्टि से देखते थे, वे सम्मान करने लगे। कुछ ऐसे ही भाव इसी समाज के कैलाशानंद गिरि के हैं। जूना अखाड़ा ने इन्हें भी महामंडलेश्वर बनाया है। इधर, अखाड़े ने आदिवासियों व वंचित समाज के संन्यासियों को महामंडलेश्वर बनाने की मुहिम तेज कर दी है। अभी तक 52 वंचितों और आदिवासियों का चयन महामंडलेश्वर बनाने के लिए किया है।

लोभ-भय, समाज से उपेक्षित व सरकारी सुविधाओं से वंचित लोग मतांतरण करते हैं। इनके घनत्व वाले क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियां सक्रिय हैं। इसे देखते हुए जूना अखाड़ा के संन्यासी इनके बीच समय व्यतीत करके उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में जुटे हैं। कर्मकांड व सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को महाकुंभ-2025 में महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की जाएगी। अभी तक मध्य प्रदेश से पांच, छत्तीसगढ़ से 12, झारखंड से आठ, गुजरात से 15 और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों से 12 लोगों को महामंडलेश्वर बनाने के लिए चुना गया है। वहीं, जूना अखाड़ा ने पिछले 10 वर्षों में 5,150 से अधिक वंचित समाज के संन्यासियों को सनातन धर्म से जोड़ा है। इनके बीच से योग्य लोग महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। जूना अखाड़ा में महामंडलेश्वर पद के लिए संबंधित को परीक्षा देनी पड़ती है।

आज चार लोग बनेंगे महामंडलेश्वर : जूना अखाड़ा ने 30 अप्रैल को गुजरात के सायंस सिटी सोला अहमदाबाद में पट्टाभिषेक समारोह का आयोजन किया है। इसमें वंचित समाज के संन्यासियों का महामंडलेश्वर पद का पट्टाभिषेक होगा। इसमें मंगल दास, प्रेम दास, हरि प्रसाद व मोहन दास बापू को महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। इनके साथ लगभग पांच हजार लोग सनातन धर्म से जुड़ेंगे।

> मतांतरण के पीछे वंचित समाज के लोगों की उपेक्षा है। कभी मेरी भी उपेक्षा व प्रताड़ना हुई थी। महामंडलेश्वर बनने के बाद मैं शिक्षा, सेवा का प्रकल्प चलाकर मतांतरण रोकने की मुहिम में जुटा हूं।
>
> –महामंडलेश्वर कन्हैया प्रभुनंद गिरि, जूना अखाड़ा

> जगदगुरु की उपाधि मिलने के बाद सनातन धर्म के प्रति मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मेरा लक्ष्य उन भटके हुए लोगों को सनातन धर्म से जोड़ना है जो दूसरे पंथों से जुड़ गए हैं।
>
> –महेंद्रानंद गिरि, जगदगुरु, जूना अखाड़ा

****

आज का मौसम

मंगलवार को आसमान साफ रहेगा। 25 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलेंगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
30 अप्रैल	37.0	22.0
1 मई	35.0	21.0
नोएडा		
30 अप्रैल	36.0	21.0
1 मई	35.0	20.0
गुरुग्राम		
30 अप्रैल	38.0	23.0
1 मई	38.0	23.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

विरोध के बाद अमेरिकी राजदूत का कार्यक्रम टला

नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सोमवार को प्रस्तावित भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी का कार्यक्रम टल गया है। जेएनयू छात्र संघ कार्यक्रम का विरोध कर रहा था और सोमवार को उन्होंने परिसर में प्रदर्शन भी किया। गार्सेटी को स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा शाम चार बजे "सदी का सबसे महत्वपूर्ण संबंध : अमेरिका-भारत संबंध" विषय पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। जेएनयू ने कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए गार्सेटी को निमंत्रण दिए जाने का विरोध किया। गार्सेटी के खिलाफ एक विरोध पोस्टर में लिखा था, नरसंहार करने वालों का स्वागत नहीं है। (जासं)

रूसी यूट्यूबर का दावा, अफसर ने दिया मोबाइल नंबर

नई दिल्ली : रूस की रहने वाली महिला यूट्यूबर दिनारा ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर दावा किया है कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक पासपोर्ट अधिकारी ने मोबाइल नंबर उन्हें दिया और भविष्य में भारत आने पर संपर्क करने को कहा। यह वीडियो प्रसारित हो रहा है। इस अधिकारी की निंदा की जा रही है। (जासं)

स्टोर खरीद के प्रभारी फार्मासिस्ट निलंबित

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने स्टोर व खरीद के प्रभारी एक फार्मासिस्ट को निलंबित किया है। डीजीएचएस डा. वंदना बग्गा ने सोमवार को निलंबन का यह आदेश जारी किया। आदेश में निलंबन का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन अनियमितता से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। (राब्यू)

केजरीवाल पेश ही नहीं हुए, तो बयान दर्ज न किए जाने की कैसे दे सकते हैं दलील

दिल्ली आबकारी घोटाला ▶ सुप्रीम कोर्ट ने समन के बावजूद सीएम के पेश न होने पर किया सवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री के वकील ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अरविंद केजरीवाल। फाइल

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बार-बार समन के बावजूद पेश नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल उठाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब वह समन के बावजूद पेश नहीं हुए तो अब धारा 50 के तहत बयान दर्ज न किए जाने को आधार बनाकर दलील कैसे दे सकते हैं? कोर्ट ने केजरीवाल से यह भी पूछा कि उन्होंने जमानत अर्जी क्यों नहीं दाखिल की?

केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उनके वकील ने कहा कि समन पर पेश न होने या जांच में सहयोग न करने के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धारा 19 पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके मुताबिक आरोपित के दोषी होने के कारण और उसके समर्थन में सामग्री होने पर ही गिरफ्तारी हो सकती है। चुनाव घोषित होने और आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तार किए जाने पर कहा कि इस समय गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, वे बयान ईडी के पास नौ महीने से थे। मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।

ईडी ने आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है। केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या केजरीवाल ने जमानत अर्जी दाखिल की है। सिंघवी ने जब इन्कार किया तो कोर्ट ने पूछा कि जमानत अर्जी क्यों नहीं दाखिल की। सिंघवी ने कहा, क्योंकि गिरफ्तारी गैरकानूनी है। तभी ईडी की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल ने बाद में उन्हें हिरासत में भेजे जाने का विरोध नहीं किया था। यह तथ्य भी गौर करने लायक है। सिंघवी ने कहा कि वह शुरुआती गिरफ्तारी को ही गैरकानूनी मानते हैं, इसलिए विरोध नहीं किया। पीठ ने कहा कि किसी सामान्य केस में अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। रिमांड मांगे जाने पर कोर्ट विचार करता है कि रिमांड देनी है कि नहीं। अगर कोर्ट रिमांड नहीं देता है तो जमानत अर्जी दी जाती है और अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो जमानत दे देता है। नहीं तो अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज देता है। सिंघवी ने कहा यह सामान्य आपराधिक मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। पीएमएलए इससे ऊपर है। उसकी धारा 19 कहती है कि गिरफ्तारी का कारण और आधार ज्यादा पुख्ता होना चाहिए।

सिंघवी ने कहा कि उन्होंने रिट याचिका दाखिल कर गैरकानूनी गिरफ्तारी के व्यापक मुद्दे को उठाया है। पीएमएलए की धारा 19 के तहत किसी की गिरफ्तारी तभी हो सकती है जबकि इस विश्वास का कारण और सामग्री हो कि आरोपित दोषी है। सिंघवी ने कहा कि करीब 10 दस्तावेज हैं, जिनमें केजरीवाल का नाम नहीं लिया गया है। इसमें तीन आरोपपत्र और गवाहों के बयान शामिल हैं। जब सिंघवी ने कहा कि धारा 50 में दर्ज उनका बयान कहां है। तो पीठ ने कहा कि आप नौ समन पर पेश नहीं हुए। जांच में सहयोग नहीं किया। जब आप बयान दर्ज कराने के लिए पेश ही नहीं हुए तो आप धारा 50 में बयान दर्ज न किए जाने की दलील कैसे दे सकते हैं। सिंघवी ने कहा कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर आई थी। वह ईडी के पास नहीं गए थे। जब ईडी गिरफ्तारी के लिए घर आ सकती है तो बयान दर्ज कराने भी आ सकती है। सिंघवी ने कहा, समन पर पेश न होना और जांच में सहयोग न करना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने इस संबंध में कोर्ट के एक पूर्व फैसले का हवाला दिया।

छात्रों के मौलिक अधिकारों का जानबूझकर हुआ उल्लंघन

विनीत त्रिपाठी ● जागरण

- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, सीएम बने रहने के केजरीवाल के निर्णय से नहीं होने देंगे छोटे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन
- प्रविधानों के अनुपालन से लेकर कोई भी प्रशासनिक अड़चन नहीं बन सकती बच्चों को मुफ्त शैक्षिक सामग्री तुरंत प्राप्त करने में बाधा

नई दिल्ली: हाई कोर्ट की मुख्य पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी स्कूलों के छात्रों को वर्दी व शैक्षिक सामग्री नहीं मिलने के मामले पर दिल्ली सरकार के विरुद्ध गंभीर टिप्पणियां करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की अनुपलब्धता, स्थायी समिति का गठन न होना, उपराज्यपाल द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति से संबंधित विवाद, सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय न देना या दिल्ली नगर निगम अधिनियम के कुछ प्रविधानों का अनुपालन न हो पाना स्कूल जाने वाले बच्चों को उनकी मुफ्त शैक्षिक सामग्री तुरंत प्राप्त करने में बाधा नहीं बन सकता है।

अदालत ने दिल्ली सरकार की भी आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए तत्परता से काम करने में असमर्थता एमसीडी स्कूलों में नामांकित छात्रों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता को दर्शाती है और यह इन छात्रों के मौलिक अधिकारों का जानबूझकर किया उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि अदालत का मानना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री व वर्दी प्राप्त करना न केवल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम व आरटीई नियमों के तहत कानूनी अधिकार है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। अदालत ने एमसीडी आयुक्त को पांच करोड़ रुपये की व्यय सीमा से मुक्त करने साथ ही स्पष्ट किया कि एमसीडी आयुक्त द्वारा किया गया व्यय वैधानिक आडिट के अधीन होगा। अदालत ने आयुक्त को मामले पर 14 मई तक ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 15 मई तय की है। याचिकाकर्ता संगठन सोशल जूरिस्ट की तरफ से पेश हुए अशोक अग्रवाल ने कहा था कि एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले सात लाख छात्रों को किताबें, लेखन सामग्री या वर्दी नहीं दी गई। यह भी कहा था कि एक स्कूल टिन शेड में भी चल रहा था।

26 अप्रैल को सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए अदालत ने टिप्पणी की थी कि आबकारी घोटाले में गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा न देकर केजरीवाल ने व्यक्तिगत हित को राष्ट्रहित ऊपर रखा है। अदालत ने कहा था कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता अपने पास रखने में है और जमीनी स्तर पर हालात खराब हैं। पीठ ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार चाहती है कि अदालत इस पर टिप्पणी करें, तो हम सोमवार को पूरी सख्ती के साथ आदेश पारित करेंगे।

असल मुद्दा यह है कि श्रेय कौन लेता है : अदालत ने कहा कि दिल्ली की सत्ता में मौजूद पार्टी (आप) को एमसीडी आयुक्त को पाठ्य पुस्तकों व वर्दी के लिए भुगतान करने के लिए अधिकृत करने के संबंध में एमसीडी सदन में स्वतः संज्ञान प्रस्ताव लाने से किसी ने नहीं रोका था। ऐसे में दिल्ली सरकार के वकील का अन्य संस्थानों पर दोषारोपण करना मगरमच्छी आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं है। असल मुद्दा शक्ति, नियंत्रण, क्षेत्र और प्रभुत्व के साथ इसका है कि श्रेय कौन लेता है।

एमसीडी में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर है पूरी तरह ठप

अदालत ने कहा कि रिजाल्यूशन नंबर-182 को पारित करने से संबंधित महापौर की याचिका पर कोई आदेश नहीं पारित किया गया है। वहीं, पांच करोड़ रुपये के संबंध में न तो आज की तारीख तक एमसीडी सदन में कोई प्रस्ताव लाया गया और न ही पास किया गया। अदालत ने नोट किया कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी आयुक्त पर आरोप लगाए हैं। हालांकि, एमसीडी आयुक्त का 18 सितंबर 2023 का पत्र व एमसीडी का 15 जनवरी 2024 का प्रस्ताव, संदेह से परे यह साबित करता है कि एमसीडी में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर पूरी तरह से ताला लगा है।

आचार संहिता के दौरान भी निभानी पड़ती हैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

अदालत ने कहा कि यह कहना गलत है कि आचार संहिता के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता। निश्चित तौर पर चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हर रोज महत्वपूर्ण व अत्यावश्यक निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। अदालत ने कहा कि छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जारी करना और वर्दी के साथ-साथ टूटी कुर्सियों और मेजों को एमसीडी स्कूलों को बदले जाने के मामले में तत्काल निर्णय में कोई देरी नहीं होती और इस पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान रोक नहीं है।

आप ने कहा, निगम की स्थायी समिति न बन पाने के लिए एलजी जिम्मेदार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति का गठन नहीं होने या कार्य बाधित होने के लिए केवल भाजपा और एलजी जिम्मेदार हैं। एलजी ने न केवल मनमाने ढंग से भाजपा के नेताओं को एल्डरमैन नामित किया, बल्कि उन्हें वोट का भी अधिकार दे दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एल्डरमैन को मिले वोट के अधिकार पर रोक लगा दी, जबकि उनके मनोनयन का मामला विचाराधीन है। स्थायी समिति गठित न होने से प्रभावित हो रहे काम लेकर सोमवार को आए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद संजय सिंह ने पार्टी का पक्ष रखते हुए ये बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक के लिए निगम ने सदन को विकास संबंधित फैसला लेने का अधिकार दिया था, लेकिन अधिकारी इसे नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि हमने पूरी दिल्ली में सर्वेक्षण कराकर राय मांगी थी और जनता ने एकमत से कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे।

महिलाओं को एक हजार रुपये महीना जरूर मिलेंगे : आतिशी

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली

- तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलीं उनकी पत्नी सुनीता और कैबिनेट मंत्री आतिशी
- जेल में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आतिशी ने उनसे हुई बातों की दी जानकारी

तिहाड़ जेल के बाहर आकर जानकारी देती मंत्री आतिशी। जागरण

तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए सोमवार को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल व कैबिनेट मंत्री आतिशी तिहाड़ पहुंची। जेल से बाहर आकर आतिशी ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को एक हजार रुपये की सम्मान राशि जरूर मिलेगी।

आतिशी सुनीता केजरीवाल के साथ करीब 12:30 बजे अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल पहुंची। पहले सुनीता को अरविंद से मिलने से मना कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें मिलने दिया गया। जेल से बाहर आकर आतिशी ने ने बताया कि जब उन्होंने केजरीवाल का हालचाल पूछा, तो उन्होंने अपनी चिंता न करने की बात कही। उन्होंने दिल्ली के कामकाज की जानकारी ली। पूछा कि बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मोहल्ला क्लीनिक में दवा की जो समस्या चल रही थी, क्या वो हल हुई या नहीं? बढ़ती गर्मी में पानी की समस्या न होने देने की बात भी कही। केजरीवाल ने वादा किया कि महिलाओं को एक हजार रुपये की सम्मान राशि देनी है, उसका पूरा प्लान बना रहे हैं। सम्मान राशि जरूर दी जाएगी।

भाजपा प्रवक्ता ने केजरीवाल और मंत्री के खिलाफ दायर की मानहानि याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके दावों को लेकर आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की है, जिसमें उन पर भाजपा व उसके सदस्यों को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। आतिशी ने दावा किया था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से 20-30 करोड़ रुपये के बदले में उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने मामले की सुनवाई की और चार मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

शिकायत में प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि यह जानते हुए कि सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ऐसी खबरें चलाएंगे क्योंकि बयान किसी विधायक ने नहीं बल्कि दिल्ली सरकार की मंत्री ने दिए। कपूर ने कहा कि इस तरह के झूठे बयान देने के लिए प्रेस कान्फ्रेंस के मंच का उपयोग करके राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश की गई है।

दिल्ली में पहले दिन 13 उम्मीदवारों ने किया नामांकन

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

- भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चांदोलिया ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भरा पर्चा
- पहले दिन कांग्रेस व आप के किसी उम्मीदवार ने नहीं किया नामांकन

नई दिल्ली के कंझावला स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय से बाहर आते उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चांदोलिया। जागरण

चुनाव आयोग ने सोमवार को दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चांदोलिया सहित 13 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। जिसमें तीन महिला उम्मीदवार व 13 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। लेकिन आइएनडीआइ गठबंधन के कांग्रेस या आम आदमी पार्टी (आप) के किसी प्रत्याशी ने पहले दिन पर्चा नहीं भरा। आठ पंजीकृत (गैर मान्यता प्राप्त) दलों के 12 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अनुसार पहले दिन पहले दिन कुल 15 नामांकन पत्र आए। योगेंद्र चांदोलिया ने दो सेट पर्चे भरे। इसके अलावा चांदनी चौक से एक पंजीकृत (गैर मान्यता प्राप्त) दल के एक उम्मीदवार ने भी दो सेट पर्चे भरे। योगेंद्र चांदोलिया ने पुत्र चित्रेश चांदोलिया को कवरिंग उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरवाया है। सीईओ कार्यालय के अनुसार पहले दिन चांदनी चौकी लोकसभा सीट से सबसे अधिक चार उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली से तीन, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली व पश्चिमी दिल्ली सीट से दो-दो उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से पहले दिन किसी उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा।

दिल्ली में नामांकन की अंतिम तिथि छह मई है। उस दिन तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। सात मई को नामांकन की जांच होगी और नौ मई को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। सातों सीटों पर 25 मई को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा।

चार के खिलाफ है दर्ज है आपराधिक मामले, पांच प्रत्याशी हैं दसवीं से कम पढ़े लिखे : प्रत्याशियों के शपथ पत्र के अनुसार पहले दिन नामांकन करने वाले 13 में से चार प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं सात ने स्नातक या उससे अधिक पढ़ाई की है। इनमें से चार के पास स्नातकोत्तर की डिग्री है। एक प्रत्याशी 12वीं पास और पांच प्रत्याशियों ने दसवीं से कम पढ़ाई की है। चांदनी चौक से एक ऐसे प्रत्याशी ने नामांकन किया है जिसने भारतीय प्रबंधन संस्थान, मुंबई से पढ़ाई की है।

इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी में मची कलह

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली: वरिष्ठ पार्टी नेता अरविंदर सिंह लवली के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद कांग्रेस में मची कलह पर आरोप-प्रत्यारोप सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहे।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने लवली पर आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले यह साजिश रची है। चौधरी ने कहा कि लवली ने इस्तीफे का जो वक्त चुना, वो गलत रहा। चौधरी ने कहा, 'मुझे लगता है कि लवली ने पार्टी को ऐसे मोड़ पर ला कर खड़ा कर दिया कि उनका इस्तीफा मंजूर होना ही था। उन्होंने अनुशासनहीनता की हद पार कर दी है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खरगे से लवली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, उदित राज ने भी कहा कि किसी के जाने आने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी बड़ी होती है व्यक्ति बड़ा नहीं होता। पार्टी में केवल गुटबाजी, फ्रैंचाइजी सिस्टम, मेरा पार्षद, मेरा ब्लाक अध्यक्ष, मेरा पदाधिकारी हो उससे क्या होता है। इससे आम कार्यकर्ता त्रस्त हो गया है।

आप-कांग्रेस गठबंधन का श्रेय लवली को : संजय

राज्य ब्यूरो . जागरण ● नई दिल्ली

- नाराज लवली ने किया पलटवार, बोले- जेल से बाहर आने के बाद भी संजय सिंह सदमे में
- लवली मेरी याददाश्त पर सवाल उठा रहे, जबकि प्रधानमंत्री को भी संदेह नहीं : संजय

अरविंदर सिंह लवली। संजय सिंह। जागरण

दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की आलोचना कर अरविंदर सिंह लवली के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद आप की ओर से सोमवार को इस गठबंधन का श्रेय लवली को देने पर नया विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद आप नेता संजय सिंह और लवली के बीच बयानबाजी हो गई। लवली ने यहां तक कह दिया कि जेल से बाहर आने के बाद भी संजय सिंह सदमे में हैं। अभी सामान्य नहीं हो सके हैं। उधर, संजय सिंह ने टिप्पणी की कि लवली मेरी याददाश्त पर सवाल उठा रहे, जबकि प्रधानमंत्री को भी मेरी याददाश्त पर संदेह नहीं है।

पूरा विवाद आप नेता संजय सिंह के बयान से शुरू हुआ। प्रेसवार्ता में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी के गठबंधन का श्रेय लवली को जाता है। लवली के इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, मैं यह जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि लवली ने कांग्रेस के साथ हमारे गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे अब उनके विपरीत विचारों के कारणों की जानकारी नहीं है। उन्होंने लवली को इस बात पर भी धन्यवाद दिया कि जब ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, तब वह उनके आवास पर पहुंचने वाले पहले कांग्रेस नेता थे। सिंह ने कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया।

संजय ने कहा कि लवली का इस्तीफा कांग्रेस का आंतरिक मामला है। बता दें कि संजय सिंह का बयान इसलिए चर्चा में आ गया, क्योंकि लवली ने 28 अप्रैल को त्यागपत्र में 'आप' के साथ पार्टी के गठबंधन पर भी विरोध जताया था।

दिल्ली कांग्रेस को आज मिल सकता है कार्यवाहक अध्यक्ष : प्रदेश कांग्रेस को कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नया सिरमौर मंगलवार को मिल सकता है। दरअसल, नामांकन के लिए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह देना होता है। इसलिए किसी नेता को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाना जरूरी है। पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति में समय लग सकता है। इसीलिए पार्टी फिलहाल कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में ही विचार कर रही है। इसके लिए पूर्व मंत्री डा नरेन्द्र नाथ और हारून यूसुफ के नाम चल रहे हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो चार पांच वरिष्ठ नेताओं की एक समिति भी बनाई जा सकती है। इस निमित्त पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से भी सलाह मशविरा किया जा रहा है। संभावना है कि मंगलवार को सारी स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए।

अध्ययन

आइआइटी कानपुर में हुआ शोध, उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के स्रोतों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा गया

प्रदूषण बढ़ाने में स्थानीय स्रोतों की मुख्य भूमिका

संजीव गुप्ता, जागरण

दिल्ली में प्रदूषण के कारण हो रहा पानी का छिड़काव। फाइल

नई दिल्ली : स्थानीय स्रोत वायु प्रदूषण बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मुख्य कारक हैं। दिल्ली में यातायात, आवासीय गर्मी और औद्योगिक गतिविधियों से अमोनियम क्लोराइड और कार्बनिक एरोसोल प्रमुख योगदानकर्ता हैं। दिल्ली के बाहर, कृषि अपशिष्ट जलाने से होने वाला उत्सर्जन और इस उत्सर्जन से बनने वाले द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल अधिक प्रचलित हैं। इस में लकड़ी, गोबर, कोयला व पेट्रोल जैसे ईंधन का दहन भी शामिल है। इससे हानिकारक कण बनते हैं, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी कानपुर) के सिविल इंजीनियरिंग और सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एसएन त्रिपाठी के इस नए शोध ने उत्तर भारत में हानिकारक वायु प्रदूषकों के प्रमुख स्रोतों के साथ ही मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का भी पता लगाया है। ''नेचर कम्युनिकेशंस'' में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चलता है कि स्थानीय उत्सर्ज, विभिन्न ईंधनों के अधूरे दहन से क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रो. त्रिपाठी की टीम ने दिल्ली और उसके आस- पास की जगहों सहित भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में पांच स्थानों से वायु गुणवत्ता डेटा का विश्लेषण किया है। इस अध्ययन ने वायु प्रदूषण की आक्सीडेटिव क्षमता को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक के रूप में बायोमास और जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से कार्बनिक एरोसोल की पहचान की है, जो प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव पैदा करने की इसकी क्षमता का एक प्रमुख संकेतक है। प्रो. त्रिपाठी ने बताया, ''आक्सीडेटिव क्षमता उन मुक्त कणों को संदर्भित करती है जो तब उत्पन्न होते हैं जब प्रदूषक पर्यावरण या हमारे शरीर में कुछ पदार्थों के साथ संपर्क करते हैं। ये मुक्त कण कोशिकाओं, प्रोटीन और डीएनए के साथ प्रतिक्रिया करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। आक्सीडेटिव क्षमता मापती है कि वायु प्रदूषण के कारण इस प्रतिक्रिया की कितनी संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वसन संबंधी रोग, हृदय रोग और तेजी से उम्र बढ़ने जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

आइआइटी कानपुर के निदेशक प्रो. मनिन्द्र अग्रवाल ने कहा कि ''यह अध्ययन उन रणनीतियों पर जोर देता है जो स्थानीय उत्सर्जन स्रोतों को संबोधित करती हैं। सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने से स्वच्छ हवा और स्वस्थ भविष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

****

पीएमएलए की धारा 66 की व्याख्या की मांग की याचिका हाई कोर्ट ने ठुकराई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 66 की आधिकारिक व्याख्या करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं अशोक कुमार सिंह समेत अन्य को उचित अदालतों के समक्ष व्याख्या के मुद्दे को उठाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

याचिका में कहा गया कि ईडी पुलिस व सीबीआइ के साथ साझा की गई जानकारी के आधार पर अपराध के तहत प्राथमिकी करने के लिए दबाव डाल रही है। ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा कि यह जनहित नहीं निजी हित याचिका है। याचिका एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास है।

कह कर रहेंगे — माधव जोशी

123 महिला प्रत्याशी ही तीसरे चरण के चुनाव मैदान में हैं। इनकी यह संख्या तीसरे चरण के कुल उम्मीदवारों 1,352 के मुकाबले केवल नौ प्रतिशत है। उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता सात मई को मतदान कर तय करेगी।

विमर्श ही नहीं, रुख भी बदला, अब चुनाव मोदी बनाम जनता

कांग्रेस के सबसे गहरे राजनीतिक संक्रमण के दौर में पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले मल्लिकार्जुन खरगे 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान में ऊर्जा और उत्साह के नए रंग में दिख रहे हैं। चुनाव के इस मोड़ पर वह अपनी पार्टी के साथ आइएनडीआइए को सत्ता की दौड़ में शामिल होने का भरोसा दिला रहे हैं। कांग्रेस घोषणापत्र के वादों के साथ दो चरणों के मतदान पैटर्न को इस उम्मीद का आधार मानते हुए वह दावा करते हैं कि चुनाव में लड़ाई जनता बनाम मोदी हो गई है, जिससे पनपी निराशा में पीएम मुसलमान, मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग जैसे प्रचार से ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे। विपक्ष के चुनावी चेहरे के सवाल पर कहते हैं कि गठबंधन चुनाव बाद चेहरा तय करेगा। नई दिल्ली के राजाजी मार्ग स्थित अपने आवास पर कांग्रेस अध्यक्ष **मल्लिकार्जुन खरगे** के साथ दैनिक जागरण के सहायक संपादक **संजय मिश्र** ने लंबी बातचीत की। प्रस्तुत हैं मुख्य अंश:

● आरोप-प्रत्यारोप की झड़ी लगी है। क्या जनता के वास्तविक मुद्दों पर राजनीतिक दलों को भरोसा नहीं है?

-हम कांग्रेस के पांच न्याय और 25 गारंटियों के जरिये जनता से संवाद कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की मुसीबतें, नारी न्याय, दलित-पिछड़े वर्ग के लिए योजनाओं से लेकर लोकतंत्र-संविधान बचाने व हिस्सेदारी न्याय की आवाज उठा रहे। आरोपों की राजनीति तो भाजपा और मोदी साहब कर रहे हैं। लगता है कि चुनाव का रुख भांप वह निराश हो गए हैं। उनकी बातों से लगता है कि देश को आजादी 2014 में ही मिली। पहले 60 वर्ष की सरकारों की उपलब्धियां उनके लिए देश की विरासत नहीं।

● क्या न्याय पत्र को कार्यान्वयन की कसौटी पर परखा गया है?

-हमने वही वादे किए हैं, जो पूरा कर सकते हैं। कुछ मुद्दों पर तो घंटों चर्चा हुई। तमाम विशेषज्ञों, आर्थिक मामलों के जानकारों से मशविरा किया गया। जनता को भी मालूम है कि नीतियां बनाने और कार्यान्वित करने में कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं।

● आपका घोषणापत्र विवादों में है। क्या पार्टी की चिंता नहीं बढ़ रही?

-हमारे न्याय पत्र में देश की गंभीर चुनौतियों और असल मुद्दों के समाधान का स्पष्ट विजन है। जनता इस पर गंभीरता से गौर कर रही तो हम क्यों परेशान होंगे। भाजपा के पास अपने मैनिफेस्टो में बताने के लिए कुछ नहीं है। तभी हमारे घोषणापत्र में कमी निकालने के लिए झूठ फैलाया जा रहा। भाजपा के पास मोदी की गारंटी बोलने के अलावा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति उनके लिए देश से ऊपर है।

● प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भटकने-परेशान होने के आपके दावे का आधार क्या है?

-उनकी पहली परेशानी हमारा घोषणापत्र है, जिसने चुनाव के विमर्श को बदला है। पहले व दूसरे चरण के मतदान के पैटर्न की रिपोर्ट दूसरी वजह है, क्योंकि अगले चरणों में भी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। इसीलिए उन्होंने भाषा बदली है। पहले फेज की वोटिंग से पूर्व कहते थे कि कांग्रेस खत्म हो गई है। जब ऐसी बात है तो फिर आप हम पर इतने जहरीले हमले क्यों कर रहे हैं?

● विपक्ष के चुनावी तेवर में अचानक आया बदलाव क्या इसका संकेत नहीं कि आपने जागने में देरी की है?

-हम हमेशा नरमी से देश के सेवक के रूप में लोगों से रूबरू होते हैं। घमंड और तेवर तो भाजपा के चुनाव अभियान में है। चुनाव में लड़ाई मोदी बनाम जनता है। उन्हें लग रहा कि सत्ता जाने वाली है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो वे गालियां देते ही थे, अब प्रियंका गांधी को भी नहीं छोड़ रहे।

● मुस्लिम लीग, मुसलमान, मंगलसूत्र पर आपके स्पष्टीकरणों के बाद भी पीएम का कांग्रेस पर प्रहार जारी है। क्या यह पार्टी की विफलता नहीं कि अपना पक्ष लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही?

-पीएम-भाजपा के पास हर तरीके के संसाधन हैं, इसलिए वे कहीं भी कुछ भी बोलते हैं। हमारे घोषणापत्र को कम से कम देख-पढ़ कर तो बोलते ताकि पीएम की ओर से निराधार टिप्पणियां नहीं होतीं। तभी हमने पीएम को पत्र लिख घोषणापत्र समझाने का समय मांगा है।

● कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर पीएम-भाजपा कांग्रेस की घेरेबंदी कर रहे। आखिर इस पर आपकी नीति क्या है?

-शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लिस्ट में उन्हें रखा गया। पिछड़े वर्ग की इसी लिस्ट का दुष्प्रचार किया जा रहा है। मोदी साहब कहते हैं कि पसमांदा को कोई नहीं देख रहा तो उन्हें कहना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं। क्या संविधान बदला है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाएगा?

● राष्ट्रवाद या मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे भाजपा के विमर्श का आप मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में आपके नहीं जाने को पीएम ने इसी से जोड़ा है?

-कांग्रेस के लोगों-नेताओं ने फांसी पर चढ़ने तक कुर्बानियां देकर देश को आजादी दिलाई। अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में उतरे और कितनों के मंगलसूत्र की आहुति हुई। हमें देशद्रोही कहा जाए, इससे हास्यास्पद बात क्या होगी। आरएसएस-जनसंघ के लोगों ने क्या कोई कुर्बानी दी? मुस्लिम वोट के डर से प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का बयान झूठ है। मुझे नेता विपक्ष तो सोनिया गांधी को यूपीए अध्यक्ष के नाते आमंत्रण दिया गया। हमने अपनी पार्टी के लोगों को बोला कि जिनकी आस्था है, वे सभी जाएं। हमारी भी आस्था है। समय आएगा तो हम जाएंगे, लेकिन धार्मिक आस्था और राजनीति अलग-अलग है। प्राण प्रतिष्ठा में आदिवासी समाज की हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को क्यों नहीं बुलाया गया? संसद भवन के शिलान्यास में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और उद्घाटन पर राष्ट्रपति मुर्मु को नहीं बुलाया गया।

● चुनावी बांड से चंदा भाजपा के अलावा तमाम पार्टियों को भी मिला, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ हमलावर है। राजनीतिक फंडिंग की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए?

-जो नई सरकार आएगी, वह इसका फैसला करेगी, लेकिन इसे कोई नकार नहीं सकता कि चुनावी बांड से भाजपा ने लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दी। सत्ताधारी दल ने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआइ में फंसे लोगों को डरा कर चंदा जुटाया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। घाटे में चलने वाली कंपनियों से 100 करोड़ चंदा लेना क्या भ्रष्टाचार नहीं है?

● आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं और भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होने का डर व भ्रम फैला रही?

-ईडी, सीबीआइ, इनकम टैक्स विभाग का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, मुख्य विपक्षी पार्टी का बैंक खाता चुनाव से पहले फ्रीज करना, विपक्ष के करीब डेढ़ सौ सांसदों का निलंबन, मीडिया का अपनी प्रशंसा तथा विपक्ष को बदनाम करने के लिए प्रयोग, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर प्रहार... इन सबको क्या माना जाए। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय गिरफ्तार किया जाता है। हेमंत सोरेन से कहा गया कि आप कांग्रेस के साथ जाएंगे तो गिरफ्तार होंगे। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो छोड़ देंगे। संस्थाओं पर कब्जे से लेकर डराने-धमकाने की यह राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं तो और क्या है।

● विपक्ष का चुनावी चेहरा नहीं होना भाजपा का बड़ा मुद्दा है। आइएनडीआइए की दिसंबर में दिल्ली में हुई बैठक में ममता बनर्जी ने आपको पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा, फिर विपक्ष क्यों हिचक गया?

-यह उनका प्रस्ताव था। हमारा प्रस्ताव हमारी पार्टी से आएगा। गठबंधन को बहुमत मिला तो सभी घटक दल मिलकर चेहरा सामने लाएंगे।

● आइएनडीआइए नेताओं में एक-एक वर्ष के पीएम फार्मूले पर सहमति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमलावर हैं, विपक्ष ने आखिर यह कैसा फार्मूला तय किया है?

-क्या यह कोई मेयर का चुनाव है कि एक-एक वर्ष के लिए होगा। ऐसी बातों पर सिर्फ हंसा जा सकता है।

पूरा साक्षात्कार पढ़ने के लिए स्कैन करें।

खाता खोलने की कोशिश में जुटी कांग्रेस

2019 के लोस चुनाव में उत्तरी कर्नाटक में कांग्रेस को नहीं मिली थी एक भी सीट, सभी भाजपा ने जीतीं थीं

अरविंद पांडेय ● जागरण

हुबली (कर्नाटक): भाजपा के अभेद्य दुर्ग उत्तरी कर्नाटक को इस बार भेदने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से जुटी है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसकी कमान संभाल रखी है। 2019 के लोस चुनाव में इस क्षेत्र से कांग्रेस को भारी निराशा हाथ लगी थी। वह एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस क्षेत्र की सभी 14 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। हालांकि, इस बार स्थिति बदली हुई है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जो अपनी गारंटी स्कीमों से सभी को अपनी ओर लुभा रही है। भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता व विकास कार्यों के सहारे है। उत्तरी कर्नाटक की 14 सीटों पर तीसरे चरण में सात मई को मतदान होना है।

उत्तरी कर्नाटक के इस गढ़ को बचाने के लिए भाजपा भी ताकत लगाए हुए है। वह हिंदुत्व, हुबली के नेहा हत्याकांड, महिला सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण व विकसित भारत जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार तेज किए हुए है। यही नहीं अपनी सभाओं में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान का जरूर जिक्र करती है, जिसमें संपत्तियों के सर्वे की बात कही जा रही है। लोगों को वह बताती है कि कांग्रेस को जिताया तो आपकी संपत्ति छीन लेगी। कांग्रेस संविधान बदलने, लोकतंत्र पर खतरा व संवैधनिक संस्थाओं को कमजोर करने जैसे मुद्दों को लेकर हमलावर है। दक्षिण कर्नाटक की तरह उत्तरी कर्नाटक में पानी या सूखा मुद्दा नहीं है।

महासमर से जुड़ी खबरों और सामग्री को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

इन दिग्गजों का गढ़ है यह

सियासी लिहाज से देखें तो उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों का क्षेत्र है। यहां से भाजपा के दिग्गज नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा, बासवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जगदीश शेट्टार जैसे बड़े नाम आते हैं। इनमें से येदियुरप्पा को छोड़कर सभी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी इसी क्षेत्र से आते हैं।

वीएस येदियुरप्पा

बासवराज बोम्मई

प्रहलाद जोशी

जगदीश शेट्टार

● भाजपा के सामने पिछली जीत को दोहराने की चुनौती, गुलबर्गा, चिक्कोडी, बिदर, बेल्लारी, रायचूर में पेंच फंसा

● इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जो गारंटी स्कीमों से लुभा रही मतदाताओं को

नरेन्द्र मोदी

राहुल गांधी

नाराजगी के चलते भाजपा ने नए चेहरे उतारे मैदान में

मौजूदा सांसदों के खिलाफ लोगों की नाखुशी और बदले समीकरणों को देखते हुए भाजपा ने क्षेत्र की 14 सीटों में से छह लोकसभा सीटों पर नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। इनमें कोप्पल, बेलगाम, हावेरी, दावनगिरी, बेल्लारी और रायचूर की सीटें शामिल हैं। हालांकि, इसके बाद भी भाजपा को बेल्लारी, रायचूर, चिक्कोडी, गुलबर्गा और बीदर में कांग्रेस से तगड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस इन्हीं पांच सीटों को लेकर आशान्वित है। जिन 14 सीटों पर सात मई को मतदान होना है, वहां राहुल गांधी व खरगे की दो मई के आसपास कई सभाएं प्रस्तावित हैं। पीएम मोदी की भी इन क्षेत्रों में कई सभाएं और रोड शो प्रस्तावित हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी इस क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं।

आंतरिक कलह से भी जूझ रही है भाजपा

भाजपा की चिंता कांग्रेस को लेकर कम बल्कि पार्टी से नाराज चल रहे अपने स्थानीय से ज्यादा है। पार्टी इन सभी को मनाने और साथ लाने की कोशिश में जुटी है। धारवाड़- हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने चुनाव मैदान में उतरे सिरेट्टी मठ के प्रमुख और लिंगायत समाज के बड़े धर्मगुरु दिंगालेश्वर स्वामी को हाल ही में पार्टी ने समझा-बुझाकर नाम वापस कराया है। हालांकि, अब भी वह नाराज है। उन्होंने जोशी के पक्ष में प्रचार करने से इन्कार कर दिया है। शिमोगा में भी पार्टी बागी नेता ईश्वरप्पा का समर्थन करने वाले पांच कार्पोरेटरों में से तीन को अपने पक्ष में फिर लाई है। पार्टी ऐसी ही कोशिश बाकी सीटों पर भी कर रही है। वोटबैंक के लिहाज से देखें तो इस क्षेत्र में लिंगायत समाज का बोलबाला है। इसके साथ ही कुर्वा, वोक्कालिगा, अल्पसंख्यक और दूसरे समाज की भी हिस्सेदारी है।

दिंगालेश्वर स्वामी

उत्तरी कर्नाटक की इन 14 सीटें पर सात मई को होगा मतदान

उत्तरी कर्नाटक में सात मई को जिन सीटों पर मतदान होना है, उनमें शिमोगा, दावनगिरी, उत्तर कन्नड़, धारवाड़-हुबली, हावेरी, बेल्लारी, कोप्पल, बीदर, रायचूर, गुलबर्गा, बीजापुर, बागलकोट, बेलगाम और चिक्कोड़ी शामिल हैं।

किस दल को कितने प्रतिशत मत मिले थे पिछले चुनाव में

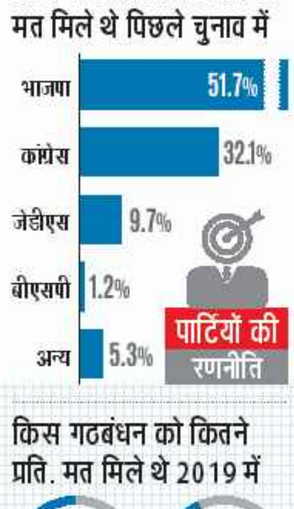

किस गठबंधन को कितने प्रति. मत मिले थे 2019 में

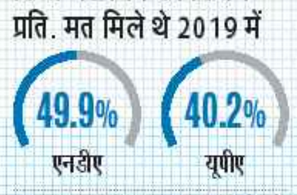

25 सीटें भाजपा ने जीती थीं पिछले चुनाव में राज्य में, कांग्रेस को मिली थी एक सीट

3.51 करोड़ मतदाताओं ने राज्य में पिछली बार किया था मदतान

मतों से भाजपा प्रत्याशी ने सबसे बड़ी जीत प्राप्त की थी उत्तर कन्नड़ से पिछले चुनाव में

27 वर्षीय प्रियंका जारकीहोली हैं चर्चा में

कांग्रेस ने भी नए व युवा चेहरों को इस क्षेत्र से टिकट देकर यहां की लड़ाई को दिलचस्प रूप दे दिया है। इनमें सबसे अधिक चर्चा चिक्कोड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी 27 वर्षीय प्रियंका जारकीहोली की है, जिन्होंने एमबीए की पढ़ाई की है। वह राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली की बेटी हैं। उनके सामने भाजपा के 60 वर्षीय अन्नासाहेब जोले मैदान में हैं, अन्नासाहेब की पत्नी शशिकला राज्य की पूर्व मंत्री रही हैं। यहां की लड़ाई में युवा बनाम बुजुर्ग का मुद्दा छाया हुआ है।

प्रियंका जारकीहोली

लद्दाख में सिर्फ पांच मतदाताओं के लिए 10 हजार फीट ऊंचाई पर बनेगा केंद्र

नवीन नवाज ● जागरण

श्रीनगर: पृथ्वी पर चांद की धरती की उपमा पाने वाला लद्दाख बड़े ही उत्साह से लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव में भागीदारी के लतए तैयार है। कोई मतदाता वोट से वंचित न रहे, इसलिए प्रशासन ने अनेक तरह के प्रयास किए हैं। लेह जिले में समुद्र तल से करीब 10 हजार फीट की ऊंचाई पर बसे वारशी गांव में सिर्फ पांच मतदाताओं के लिए उनके घर के सामने मतदान केंद्र बनाया जाएगा।

लद्दाख प्रदेश में दो जिलों और चार विधानसभा क्षेत्रों में 1,82,571 मतदाताओं पर आधारित एक ही लोकसभा सीट है। इस सीट के लिए पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होगा। पूरे प्रदेश में 577 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं और इनमें सिर्फ 33 ही शहरी इलाकों में हैं। बाकी 544 मतदान केंद्र ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में हैं।

● लेह जिले के वारशी में एक ही परिवार के हैं सभी मतदाता

● घर के सामने ही चुनाव आयोग की ओर से स्थापित किया जाएगा केंद्र

● कारगिल जिले के फेमा गांव में भी 14 मतदाताओं के लिए बनेगा केंद्र

चुनाव की तैयारी

वहीं, 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पेंजि ला में बर्फ से ढकी चोटियों पर पिछले दिनों छात्रों ने मानव शृंखला और बर्फ से विभिन्न आकृतियां बनाकर मतदाताओं को वोट का महत्व बताया। इस दौरान उन्होंने मानव शृंखला के माध्यम से स्वीप भी लिखा।

ये है स्वीप: स्वीप (एसवीईईपी- सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) देश में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता फैलाने और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग की ओर से संचालित किया जा रहा प्रमुख कार्यक्रम है।

हमारा प्रयास है कि प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इसलिए हमने वारशी जैसे दुर्गम इलाके में सिर्फ पांच मतदाताओं के लिए भी मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। हम मतदाताओं में जागरूकता के लिए विभिन्न गांवों और शहरों में निरंतर मतदाता जागरूकता शिविर लगाने के साथ ही कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहे हैं।

यर्तीद एम मरलकार, लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

कारगिल जिले के फेमा में हमने 14 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाना तय किया है। यह तंबू में होगा। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जंस्कार घाटी में पेंजि ला, दारदुंग ग्लेशियर में छात्रों ने मानव शृंखला बनाई। वहां हमने बर्फ से आकृतियां बनाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए। राष्ट्रध्वज के नीचे खड़े होकर लोगों ने मताधिकार का प्रयोग करने और भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की शपथ ली है।

श्रीकांत सूसे, जिला उपायुक्त, कारगिल

पेंजि ला में बर्फ से ढकी चोटियों पर पिछले दिनों छात्रों ने स्वीप लिखकर मतदाताओं को वोट का महत्व बताने वाला संदेश दिया ● जागरण

चुनावी कानाफूसी

नेता दौड़ लगाते हैं, लेकिन इनके पास तो दौड़कर आया टिकट

राजनीति भी कई रंग दिखाती है। पार्टी का टिकट लेने के लिए नेताओं की एड़ियां घिस जाती हैं। कई तरह के प्रयास किए जाते हैं फिर भी टिकट मिलना तय नहीं होता। हिमाचल प्रदेश में संसदीय चुनाव के लिए भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां पर जो नेता टिकट के लिए जोर लगा रहे थे, उन्हें तो टिकट मिला नहीं और जो मना कर रहे थे, उन्हें टिकट दे दिया गया। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह पहले ही टिकट के लिए मना करती रहीं। पार्टी के जोर देने पर तैयार हो गईं। इस बीच, भाजपा ने कंगना रनौत को प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने रणनीति बदली और प्रतिभा के बेटे व प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को टिकट दे दिया। उधर, शिमला संसदीय क्षेत्र में भी रोचक स्थिति बनी है। यहां पर कांग्रेस ने कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी को प्रत्याशी बनाया है। विस चुनाव के समय लगातार दो बार हारने के कारण 2022 के विस चुनाव में उनके टिकट पर संकट था। इसके लिए उन्हें कई प्रयास करने पड़े और अंतत: टिकट लेकर चुनाव जीत गए। संसदीय चुनाव में उन्होंने न तो आवेदन किया, न ही वह चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि टिकट उनके पास दौड़कर आया। लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि विनोद के पिता कैडी सुल्तानपुरी लगातार छह बार यहां से सांसद रहे हैं। उनके बाद ही यहां से विपक्षी पार्टी के सांसद चुने जा रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस को सुल्तानपुरी के परिवार से ही अब आस दिख रही है।

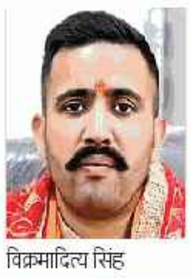
विक्रमादित्य सिंह

विनोद सुल्तानपुरी

बंगाल में चल रही है जुबानी जंग : बाप-बेटा बनाम मां-बेटा

लोकसभा चुनाव में बंगाल में जुबानी जंग बाप-बेटा और मां-बेटा तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व मेदिनीपुर में अपने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि नंदीग्राम आंदोलन के दौरान बाप-बेटा कहां थे? उन्हें तो चुनावी अखाड़े में मैं लाई थी। यहां बाप-बेटा का मतलब नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और उनके पिता शिशिर अधिकारी से था। हालांकि, ममता ने नाम नहीं लिया। सुवेंदु भी कहां पीछे रहने वाले थे उन्होंने भी चुनाव प्रचार करते हुए अपने गृह जिला पूर्व मेदिनीपुर में नाम लिए बिना कहा कि नंदीग्राम आंदोलन के दौरान मां-बेटा कहां थे? अब लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई है कि मां-बेटा कौन है? वैसे तो सुवेंदु ममता और अभिषेक के लिए पीसी (बुआ) और भाइपो (भतीजा) शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर मां-बेटा क्यों कहा इसे लेकर कानाफूसी तेज हो गई है।

जमीन पर साथ-साथ नहीं दिख रहीं कांग्रेस व आप

वीके शुक्ला ● जागरण

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में दिल्ली सहित पांच राज्यों में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ रही है, लेकिन दोनों दल जमीन पर साथ नहीं दिख रहे हैं। संयुक्त चुनाव प्रचार को लेकर अन्य राज्यों में तो दोनों की स्थिति खराब है ही, दिल्ली में भी गठबंधन इस मामले में अलग-थलग दिखाई पड़ रहा है। यहां तक कि चुनाव प्रचार को लेकर बड़े आयोजनों में भी दोनों दल साथ-साथ नहीं आ रहे हैं। रोड-शो से लेकर सभाओं तक में दोनों दल अपने-अपने दम पर भीड़ जुटा रहे हैं।

आप के अब तक के सबसे बड़े प्रचार अभियान में शनिवार को पूर्वी दिल्ली और रविवार को पश्चिमी दिल्ली सीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के रोड-शो में भी कांग्रेस की उपस्थिति लगभग शून्य रही है। यह इस बात की ओर इशारा कर रही है कि गठबंधन भले ही दोनों दलों में हुआ है, मगर भविष्य के अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए दोनों दल आपस में दूरी भी बनाए हुए हैं। यहां तक कि दोनों दलों के आयोजनों में बड़े नेता भी एक मंच पर नहीं आए हैं।

आप और कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो दोनों में उतनी ही दूरी है, जितनी आप और भाजपा में है। पार्टी के दिल्ली में सफाये के लिए भी कांग्रेस आप को ही जिम्मेदार मानती है। कांग्रेस यह बात साफ तौर पर कहती रही है कि कांग्रेस का जनाधार ही आप के पास गया है, इसे वापस लाने की कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। यहां यह भी गौरतलब है कि केजरीवाल की परेशानियों में कांग्रेस उनके साथ खानापूर्ति के लिए कुछ मामलों में साथ दिखी है। गठबंधन के बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी ईडी से अकेले ही जूझ रही है। जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो 31 मार्च को आइएनडीआइ की रामलीला मैदान में हुई महारैली के लिए आप और कांग्रेस के नेता इसकी घोषणा के लिए ही केवल एक मंच पर आए। इसके बाद महारैली की आप तैयारी तो करती रही, मगर तैयारियों के दौरान दोनों दल साथ नहीं आए। 31 मार्च से एक दिन पहले कांग्रेस ने इस आयोजन को लेकर प्रेसवार्ता की तो भी आप को अपने मंच पर नहीं बुलाया। महारैली में सभी दल जरूर साथ आए, मगर उसके बाद से दूरी बनी हुई है।

पूर्वी दिल्ली में गत शनिवार को रोड शो करतीं सुनीता ● जागरण आर्काइव

चुनावी परिदृश्य

राजनीति

● भविष्य के हित प्रभावित न हों, इसे देखते हुए भी दोनों पार्टियां हैं बेहद सतर्क

● रोड-शो से लेकर सभाओं तक में दोनों पार्टियां अपने-अपने दम पर जुटा रहीं हैं भीड़

सिर्फ कागजों में गठबंधन: जहां तक संयुक्त चुनाव प्रचार की बात है तो इन दलों ने इस बारे में घोषणा तो की थी और एक संयुक्त समन्वय समिति बनाने की बात भी की थी, मगर अभी तक यह सब कागजों में ही है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मंच पर जिन-जिन दलों के नेता आते हैं, उनके कार्यकर्ताओं में एक साथ होने का संदेश जाता है, जो उनसे संबंधित दलों के प्रत्याशियों की राह आसान बनाता है, लेकिन आप और कांग्रेस में ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा है।

इन राज्यों में है गठबंधन: आप-कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में गठबंधन में नहीं हैं, जबकि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात, गोवा में गठबंधन में है। आप दिल्ली में चार, गुजरात की दो लोकसभा सीट भरूच और भावनगर पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में एक सीट कुरुक्षेत्र से पार्टी लड़ रही है।

****

40 दिन में 45 जनसभाएं की हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। वह अपने राज्य में भाजपा के प्रचार के अलावा पड़ोसी राज्यों के मतदाताओं को भी साधने में जुटे हैं। इसमें मध्यप्रदेश और ओडिशा में छह आमसभाएं और रोड शो शामिल हैं।

आइएनडीआइए जीता तो क्या एक-एक साल के लिए बनेंगे पीएम : अमित शाह

बोले-शरद पवार, लालू, स्टालिन व ममता के बाद क्या बचे समय के लिए राहुल बनेंगे प्रधानमंत्री

गृहमंत्री ने कहा- देश को मजबूर नहीं, मजबूत नेतृत्व चाहिए

जागरण टीम, पटना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बिहार की चुनावी सभाओं में विपक्षियों के परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार पर हमला बोला। आइएनडीआइए की हकीकत बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आइएनडीआइए जीते ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर वे जीतते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या एक-एक साल के प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक साल शरद पवार, एक साल लालू, एक साल स्टालिन, एक साल ममता बनर्जी और जो कुछ समय बचेगा, उसके लिए राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्या ऐसा नेतृत्व देश को मजबूत कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जीत निश्चित है। उनको तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब है बिहार को खत्म करना और योग्यता के आधार पर राजनीति की शुरुआत करना। शाह सोमवार को मधुबनी जिले के झंझारपुर से एनडीए के जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल व बेगूसराय से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित

लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को बिहार के बेगूसराय में भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

में जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार कर रहे थे।

मोदी का नेतृत्व ही आतंकवाद से बचा सकता है : शाह ने कहा कि मोदी का नेतृत्व ही आतंकवाद से बचा सकता है, कश्मीर में शासन व सुशासन स्थापित कर सकता है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। लालू भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। मंडल कमीशन के कारण जो आरक्षण मिला, वह 1957 में ही मिल जाता। लेकिन काका साहब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस ने रोककर रखा। उसने मंडल कमीशन का विरोध किया। लालू के जीवन का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना और सोनिया गांधी का राहुल को प्रधानमंत्री बनाना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना में 130 करोड़ टीके लगवाकर भारत को सुरक्षित बनाया। राहुल गांधी इसका मजाक बनाते थे। कहते थे, यह मोदी जी का टीका है। एक दिन अंधेरे में वह भी टीका लगाकर आ गए।

गरीबों की गाढ़ी कमाई डकारने वालों पर होगी कार्रवाई : अमित शाह ने लालू पर हमला करते हुए कहा कि ये घोटालेबाज हैं। कभी चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन का घोटाला और कई घोटाले किए। मिथिलांचल को भाजपा आधुनिक युग में ले जाना चाहती है और लालू लालटेन युग में। जनता इसके लिए तैयार नहीं है।

मोदी बोले, कांग्रेस के शासनकाल में ही भगवा आतंकवाद की गढ़ी गई थ्योरी

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधानमंत्री ने संप्रग कार्यकाल में हुए आतंकी हमलों की भी याद दिलाते हुए कहा कि आतंकी हमलों ने मुंबई और पुणे को लहूलुहान कर दिया था। लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे, तो उन्हें नहीं पता होता था कि वे अपने घर लौट भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले देश में आतंकी हमले होते थे। लेकिन अब नहीं होते। उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग यहां आतंकी भेजते थे, उनको आज आटे के लाले पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुस्लिम संगठन पीएफआइ पर अपनी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की याद दिलाते हुए कहा कि ये कांग्रेस वाले वोट के लिए उनका सहयोग लेने केरल पहुंच गए। कांग्रेस की इसी तुष्टीकरण नीति के कारण देश में आतंकवाद का हाहाकार मचा रहता था। मोदी ने कहा कि पुणे की धरती साक्षी है कि कांग्रेस के शासनकाल में ही निर्दोष हिंदुओं पर सारा दोष डालने के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी। प्रधानमंत्री ने पुणे की सभा में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार पर भी बिना उनका नाम लिए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष पहले यहां के एक बड़े नेता ने राज्य में अस्थिरता का जो खेल खेलना शुरू किया, उसके कारण आज तक महाराष्ट्र की राजनीति में अस्थिरता ही बनी हुई है। बता दें कि पुणे जिले की संसदीय सीट बारामती से शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले एवं उनके भतीजे की पत्नी सुनेत्रा पवार में चुनावी मुकाबला हो रहा है।

इससे पहले मोदी ने सतारा में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले के समर्थन में भी एक रैली को संबोधित किया। सतारा में छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2013 में जब उन्हें पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तो उन्होंने महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठकर उनसे प्रेरणा ली थी। इसी रैली में उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर को भी याद करते हुए कहा कि वह आज बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के कारण ही प्रधानमंत्री बन सके हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल के दौरान बाबा साहेब का संविधान जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। जिसके कारण वहां के दलितों-आदिवासियों को अब तक आरक्षण के हक से वंचित रहना पड़ा। यह हक हमारी सरकार ने उन्हें जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटवाकर दिलवाया।

कर्नाटक में बोले- यह नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा : प्रेट्र के मुताबिक, कर्नाटक के बागलकोट में आयोजित चुनावी रैली में भी पीएम ने कहा ''यह नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा।'' मोदी ने दावा किया कि वह पीछे से हमला करने में विश्वास नहीं करते और खुलकर आमने-सामने लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बालाकोट हवाई हमलों के बारे में जानकारी नहीं छिपाई और इसके बारे में जानकारी व हमलों के बाद दुश्मन को हुए नुकसान को उजागर किया।

फल विक्रेता मोहिनी गौड़ा से की मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के सिरसी की अपनी यात्रा के दौरान अंकोला की एक फल विक्रेता मोहिनी गौड़ा से मुलाकात की। हेलीपैड पर पहुंचने पर सबसे पहले उनकी मुलाकात मोहिनी गौड़ा से हुई। मोहिनी गौड़ा एक फल विक्रेता हैं और वह अंकोला बस स्टैंड पर पत्तों में लिपटे फल बेचती हैं। उसकी एक अनोखी विशेषता है कि यदि कुछ लोग फल खाकर पत्ते फेंक देते हैं तो वह पत्ते उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। उन्होंने सराहना की।

सत्ता में आए तो जातिवार गणना और आर्थिक सर्वे कराएंगे : राहुल

राज्य ब्यूरो, पाटण (गुजरात)

- कहा-भाजपा, संघ ने संविधान बदलने की बनाई है योजना
- टीवी पर किसान, बेरोजगार नहीं बालीवुड नाचता दिखता है

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह प्राथमिकता के आधार पर पूरे देश में जातिवार गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीबों की भागीदारी बढ़ाना है। पाटण में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और आरएसएस ने चुनाव जीतने पर संविधान बदलने की योजना बनाई है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, देश की 90 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की है। लेकिन आपको कारपोरेट, मीडिया, निजी अस्पतालों, निजी विश्वविद्यालयों या सरकार की नौकरशाही में उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। हम सत्ता में आने के बाद सबसे पहले जातिवार गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ भाजपा और आरएसएस पर संविधान को बदलने की योजना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार आरक्षण व्यवस्था के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा, भाजपा नेता कह रहे हैं कि वे संविधान को बदल देंगे। हमारा संविधान गरीबों और वंचितों की रक्षा करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि केवल 22-25 लोग सभी संपत्ति, ताकत और प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करें। उनके 10 साल के शासन में यही हुआ है।

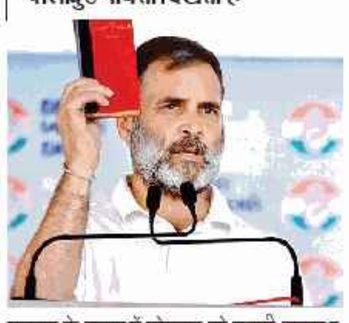

गुजरात के पाटण में सोमवार को चुनावी जनसभा के दौरान भारतीय संविधान की एक प्रति के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी। एएनआइ

कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ उद्योगपति गौतम अदाणी और अंबानी परिवार पर भी सवाल उठाए। कहा कि जो गुजरात में हुआ आजकल वही देश में हो रहा है। गौतम अदाणी की जिस पर नजर पड़ती है, उसी को उठा लेते हैं। जंगल, जमीन, एयरपोर्ट, बंदरगाह हो या कोई टीवी चैनल सब अपने कब्जे में कर लेते हैं। अदाणी मोदी के मित्र हैं इसलिए उनको यह मिलता है। टीवी पर किसान, दलित, युवा, महंगाई, बेरोजगारी कहीं नजर नहीं आती। बस मोदीजी का चेहरा नजर आता है या फिर नाचता हुआ बालीवुड और अरब तियों की शादियां नजर आती हैं।

शाह की टिप्पणी पर कांग्रेस का तंज, मोदी सत्ता में नहीं आ रहे

- गृह मंत्री ने कहा था, पीएम पद के लिए आइएनडीआइए में होगा संघर्ष
- कहा-संप्रग सरकार के दौरान मनरेगा लेकर आई

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्री अमित शाह की ''पीएम पद के लिए संघर्ष'' वाली टिप्पणी पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि यह एक स्वीकारोक्ति है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापस नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि लोगों ने संविधान को बदलने और आरक्षण समाप्त करने की भाजपा की साजिश को समझ लिया है। अमित शाह ने सोमवार को चेतावनी दी कि गलती से भी आइएनडीआइए जीत गया, तो विपक्षी गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच पीएम पद के लिए संघर्ष होने लगेगा।

शाह की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि गृह मंत्री इस बारे में बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार कौन होंगे। कम से कम यह स्वीकारोक्ति है कि मोदी सत्ता में नहीं आ रहे हैं। 400 सीटों की बातें करने वाले अब मान रहे हैं कि अगली सरकार आइएनडीआइए की होगी। संवाददाताओं से बात करते हुए श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा और कौन नहीं होगा, यह निर्णय हम लेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने (हमारी जीत को) स्वीकार कर लिया है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देती हूं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि संविधान बदलना और आरक्षण खत्म करना आरएसएस का मूल दर्शन रहा है। उसने लगातार आरक्षण का विरोध किया है। यहां तक कि भाजपा में भी यह कोई संयोग नहीं है कि ज्योति मिर्धा से लेकर अनंतकुमार हेगड़े जैसे नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है लोगों को आरक्षण के अधिकार से वंचित करना।

आयोग से शिकायत

डीप फेक वीडियो के खिलाफ भाजपा पहुंची चुनाव आयोग

- कांग्रेस की ओर से प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल को लेकर भी दर्ज कराई शिकायत
- कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
- प्रचार को धार्मिक रंग देने व घोषणा पत्र पर झूठ फैलाने को लेकर की शिकायत

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अनिल बलूनी, ओम पाठक सहित भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर बाहर आता हुआ। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राजनीतिक दलों के बीच चुनावी तल्खी बढ़ने के साथ ही शिकायतों का दौर भी तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सोमवार को चुनाव आयोग पहुंचकर एक-दूसरे के खिलाफ झूठ फैलाने और गलत तथ्य पेश करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच, आयोग पहुंचे भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो को लेकर आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही चुनाव प्रचार में डीफ फेक से जुड़े कई मामले भी आयोग के सामने पेश किए हैं।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव व भाजपा मीडिया विभाग के प्रमुख अनिल बलूनी के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस पर अपने चुनाव प्रचार में बच्चों की वीडियो व तस्वीरों का इस्तेमाल करने की शिकायत की है। भाजपा ने इस दौरान बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल उठाया है और चुनाव आयोग से राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आयोग से मिलने के बाद बताया कि कांग्रेस पार्टी डीप फेक, मार्फ और नकली वीडियो के जरिये चुनाव की पूरी प्रक्रिया को भटकना चाहती है। भाजपा ने बताया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने आफिशियल हैंडल से डीप फेक मैसेज डालकर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। उन्होंने चुनाव आयोग से कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की।

इस बीच, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला और सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग पहुंचकर भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि आयोग को इस दौरान 20 शिकायतें दी गई हैं। इसमें पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा की ओर फैलाने जा रहे दुष्प्रचार की भी शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है।

जवाब देने के लिए भाजपा-कांग्रेस ने मांगा समय

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में दोनों दलों के पार्टी अध्यक्षों को दिए गए चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए दोनों दलों ने और समय मांगा है। चुनाव आयोग से भाजपा ने एक हफ्ते से अधिक का समय और कांग्रेस ने 14 दिन से अधिक का समय मांगा है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से गुरुवार को चुनाव आयोग ने नोटिस का जवाब सोमवार को सुबह 11 बजे तक देने को कहा था। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार जवाब देने के लिए भाजपा ने एक हफ्ते की छूट मांगी है जबकि कांग्रेस ने पहले सोमवार को ही शाम पांच बजे तक का समय मांगा था, लेकिन बाद में उसने नोटिस का जवाब 14 दिनों के बाद देने को कहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग ने कांग्रेस और भाजपा की इस अपील को स्वीकार किया है या नहीं।

ये जनता की भलाई नहीं, अपनी सत्ता देखते हैं : प्रियंका गांधी

- कर्नाटक में कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना
- कहा, पिछले 10 वर्षों में राजनीति से गायब हो गई सच्चाई

कलबुर्गी में सोमवार को चुनावी रैली के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। एएनआइ

कलबुर्गी, एएनआइ : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को कहा कि वे जनता के कल्याण को नहीं, बल्कि केवल अपनी राजनीति को देखते हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश की राजनीति से 'सच्चाई' गायब हो गई है। उन्होंने कहा, ''आज देश की हकीकत बदल रही है। पिछले 10 वर्षों में जो राजनीति हुई है वह घमंड, शान, स्वाभिमान और सत्ता की राजनीति है। इसमें सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर सांसद तक यह भूल गए हैं कि उन्हें जनता का सामना करना पड़ता है। आपके सांसद कभी भी आपसे मिलने नहीं आते हैं। उन्होंने पिछले पांच वर्षों में आपके लिए कुछ नहीं किया है। दूसरी ओर आपके संघर्षों का बोझ आपके ऊपर है। महिलाएं पूरे समाज का बोझ उठाती हैं, लेकिन यह सरकार आपकी (महिलाओं) की बात नहीं सुनती। केंद्र में सरकार होने के बावजूद यहां के सांसदों ने नारे लगाए कि घरों में नल से पानी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जनता की भलाई नहीं, अपनी सत्ता देखते हैं।''

मोदी गांधी परिवार को गाली दे रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई उपलब्धि नहीं : खरगे

- खरगे ने दावा किया कि दो चरणों के चुनाव में कांग्रेस को मिली है बढ़त

राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, कांग्रेस कभी भी हिंदू-मुस्लिम के बारे में बात नहीं की

यादगिर, प्रेट्र : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गांधी परिवार को गाली दे रहे हैं क्योंकि उनके पास श्रेय लेने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। यादगिर जिले के गुर्मत्कल कस्बे में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खरगे ने दावा किया कि शुरुआती दो चरणों के चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली है जिससे मोदी चिंतित हैं। खरगे के दामाद राधाकृष्णा डोड्डामणि कलबुर्गी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर सात मई को मतदान होगा और गुर्मत्कल इस निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि इस देश में मोदी के जन्म से पहले और बाद में क्या था, लेकिन वह अभी तक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लालबहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुझे गाली देते हैं क्योंकि उनके पास श्रेय के लिए कुछ भी नहीं है। खरगे ने कहा कि मोदी हताशा में कहते हैं कि कांग्रेस हर किसी की संपत्ति छीनकर उसे मुसलमानों के बीच बांट देगी। यह न तो संविधान में लिखा है और न ही हमारे घोषणापत्र में इसका कहीं उल्लेख है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने केवल यह कहा है कि वह गरीबों को उनका वाजिब हक देगी लेकिन कभी भी हिंदू-मुस्लिम के बारे में बात नहीं की। खरगे ने कहा कि उनकी पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भूमि सुधार, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और जीवन बीमा निगम के माध्यम से ऐसा किया था। यह गरीबों के लिए किया गया था।

प्रधानमंत्री हमारे न्याय पत्र के बारे में गोएबल्स से प्रेरणा ले कर करते हैं बात : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उसके चुनावी घोषणा पत्र के बारे में जर्मनी के पूर्ववर्ती नाजी प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स से प्रेरणा ले कर बात करते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि राजनीति विज्ञान में एमए के लिए नरेन्द्र मोदी ने निश्चित रूप से प्रचार के संबंध में जोसेफ गोएबल्स को पढ़ा होगा और उनसे प्रेरणा ली होगी। उन्होंने उल्लेख किया कि गोएबल्स ने कहा था कि यदि आप बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं और उसे दोहराते रहते हैं, तो लोग अंततः उस पर विश्वास करने लगेंगे।

आरक्षण खत्म करने के कांग्रेस के हमले की काट में जुटी भाजपा, झोंकी पूरी ताकत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कांग्रेस को बताया एससी, एसटी और ओबीसी का असली विरोधी

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद संविधान बदलने और एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के कांग्रेस के हमले की काट के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आरक्षण को लेकर भाजपा की स्थिति स्पष्ट करने के बाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और दलित सांसद बृजलाल को मैदान में उतारा। बृजलाल ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को दलित, आरक्षण, बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान का विरोधी बताया। उन्होंने 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सभी मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस को शुरू से ही आरक्षण पसंद नहीं है।

बृजलाल। फाइल

इन समुदायों के कोटे का आरक्षण मुसलमानों को देने का लगाया आरोप

बृजलाल ने भाजपा के खिलाफ संविधान बदलने के आरोप को झूठी अफवाह बताते हुए कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने संविधान में सबसे ज्यादा बदलाव किया है। उनके अनुसार, कांग्रेस सिर्फ भीम-मीम का ढोंग करती है, जबकि उसके दिल में सिर्फ मीम-मीम है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रविधान नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में ओबीसी कोटा कम कर मुसलमानों को आरक्षण दिया। उसी तरह से कर्नाटक में भी ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार द्वारा गठित रंगनाथ मिश्रा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में दलित कोटे में से एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने का सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का धार्मिक आधार पर आरक्षण देना पूरी तरह से संविधान विरोधी है। बृजलाल ने कांग्रेस व विपक्षी दलों पर जम्मू-कश्मीर में दलितों और पिछड़ों को 70 साल तक आरक्षण से वंचित रखने का आरोप भी लगाया। कहा कि मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 खत्म करने का सबसे अधिक फायदा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को मिला है। इन्हें पहली बार संविधान प्रदत आरक्षण के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी मिली हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किए जाने के बाद एससी, एसटी और ओबीसी को यहां मिल रहा आरक्षण खत्म हो जाने का मुद्दा भी उठाया।

सलमान खुर्शीद की सभा में भतीजी ने की 'वोट जिहाद' की अपील

जासं, फर्रुखाबाद : यूपी के कायमगंज के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में आइएनडीआइ प्रत्याशी डा. नवल किशोर शाक्य के समर्थन में कांग्रेस व सपा के स्थानीय दिग्गजों की जनसभा में 'वोट जिहाद' का नया मुद्दा उठा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के मुख्य आतिथ्य में हुई सभा में उनकी भतीजी सपा नेता मारिया आलम खां ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामने मौजूदा हालत में वोट जिहाद जरूरी है। एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा ने बताया कि अगर कोई शिकायत आती है तो जांच कराई जाएगी। मारिया आलम खां ने कहा कि हर महिला और हर पुरुष वोट जिहाद से संविधान बचाने को इस जंग को लड़ेगा। मारिया के इस वक्तव्य पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि जिहाद का मतलब किसी परिस्थिति से संघर्ष करने के लिए होता है। उनका यही मंतव्य रहा होगा कि संविधान की रक्षा के लिए वोट जिहाद किया जाए।

****

लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण

18% उम्मीदवारों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले

राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या को कम करने को लेकर दलों द्वारा किए जा रहे तमाम दावे निरर्थक साबित हो रहे हैं। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) के अनुसार लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे 1,352 उम्मीदवारों में से 18 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एडीआर ने द नेशनल इलेक्शन वाच के साथ मिलकर चुनाव पूर्व उम्मीदवारों द्वारा दिए गए हलफनामों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है। इनमें से सात उम्मीदवारों ने पहले की दोषसिद्धि का भी विवरण दिया है। उल्लेखनीय हैं तीसरे चरण के लिए सात मई को मतदान होगा।

5 पर हत्या से संबंधित आरोप हैं आपराधिक रिकार्ड वाले 244 उम्मीदवारों में से

24 पर दर्ज किए गए हैं हत्या के प्रयास के मामले

38 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं

17 पर नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित मामले घोषित किए गए हैं

29% उम्मीदवार करोड़पति

रिपोर्ट में उम्मीदवारों की वित्तीय पृष्ठभूमि में असमानता पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार कुल उम्मीदवारों में 392 उम्मीदवार (29 प्रतिशत) करोड़पति हैं एवं प्रति उम्मीदवार औसत संपत्ति 5.66 करोड़ रुपये है। घोषित संपत्ति के मामले में शीर्ष तीन उम्मीदवारों के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है, जिसमें सबसे अधिक घोषित संपत्ति 1,361 करोड़ रुपये से अधिक है।

सुधार की आवश्यकता

रिपोर्ट में राजनीतिक परिदृश्य में जवाबदेही और पारदर्शिता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हुए चुनाव सुधारों के महत्व पर जोर दिया गया है। विश्लेषकों के अनुसार जघन्य अपराधों के दोषी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर एवं इन्हें मैदान में उतारने वाले दलों को मिलने वाले कर छूट को रद कर इस दिशा में सुधार लाया जा सकता है।

(स्रोत: प्रेट्र)

202.52 करोड़ की नकदी, शराब, सोना और अन्य सामान जब्त किया जा चुका है तेलंगाना में। यह राशि और सामान मुफ्त बांटी जाने वाली थी। कुल जब्त राशि में से 76.65 करोड़ की नकदी, 29.62 करोड़ मूल्य का सोना, चांदी और कीमती बहुमूल्य धातुएं है।

कांग्रेस ने पंजाब की चार लोकसभा सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सोमवार को पंजाब में चार सीटों पर अपने प्रत्याशी के नामों की तीसरी सूची जारी की। इसके तहत गुरदासपुर से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, खडूर साहिब से कुलबीर सिंह जीरा, श्रीआनंदपुर साहिब से विजय इंदर सिंगला और लुधियाना से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को टिकट दिया गया है। कांग्रेस पंजाब में लोकसभा की 13 में 12 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। पंजाब में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, जहां उसका मुकाबला आम आदमी पार्टी (आप), भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) से होगा। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर सातवें और आखिरी फेज में एक जून को मतदान होना है।

पंजाब

अपने बेटे को तीसरी बार पीएम बनते देखना चाहता है वडनगर

शत्रुघ्न शर्मा, वडनगर

नाटक में जोगीदास खुमाण के पात्र ने जिस अंदाज में तलवार खींची थी, वो लोगों को आज भी है याद

प्रधानमंत्री के शिक्षक हरगोविंद पटेल। जागरण

बीएन हाईस्कूल में लगभग 60 वर्ष पहले एक नाटक का मंचन किया गया था। इसमें जोगीदास खुमाण के पात्र ने मंच पर जिस अंदाज में तलवार खींची थी, वो दृश्य शिक्षकों व लोगों को आज भी याद है। जोगीदास का पात्र निभाने वाला बालक कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही थे। उन्हें बचपन में नाटक, परंपरागत खेल का बहुत शौक था। वडनगर अपने बेटे को तीसरी बार पीएम बनते देखना चाहता है। यहां के लोग कहते हैं कि मोदी ने 10 साल में वह कर दिखाया जो 70 साल में नहीं हो सका। दूसरों के काम के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं।

ऐतिहासिक शहर वडनगर में जहां एक ओर पुरातत्व महत्व का वडनगर का तोरण, सात प्राचीन दरवाजे, 5वीं सदी के बौद्ध स्तूप, प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर दिखता है तो दूसरी ओर लाल पत्थर से दमकता शर्मिष्ठा तालाब, टावर बिल्डिंग में चलता शेठ पुस्तकालय, प्राचीनता और आधुनिकता की गवाही देता वडनगर रेलवे स्टेशन नजर आता है।

पीएम मोदी का जन्म इसी कस्बे के कालावासुदेव नुं चाचरु (मोदीवास) के एक मकान में हुआ। अब यह मकान इनके चाचा के हिस्से में चला गया है। मोदी का बचपन इन्हीं गलियों में बीता। जिस घर में मोदी रहे, अब वहां कोई दूसरा परिवार रहता है। लेकिन, यहां के लोगों के चेहरे पर अपने नरेन्द्र के प्रधानमंत्री बनने की खुशी साफ झलकती है। वडनगर चाहता है कि उसका बेटा तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने। दिलीप मोदी बताते हैं कि मोदी ने पीएम रहते जो किया, वह कोई दूसरा नहीं कर सकता था। मोदी ने हर वर्ग का ध्यान रखा और देश का विकास किया। राममंदिर कोई दूसरा नेता नहीं बनावा सकता था। अनुच्छेद-370 हटाना भी किसी और के बस की बात नहीं थी।

स्कूल के दिनों से ही आरएसएस से हो गया था जुड़ाव : मोदी को पढ़ाने वाले हरगोविंद चेलदास पटेल बताते हैं कि नरेन्द्र कहते थे कि उन्हें स्कूल की हर गतिविधि में रखें। लेकिन, उनकी शर्त होती थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का यदि कोई काम होगा तो वे इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। स्कूल के दिनों से ही उनका लगाव आरएसएस से था। मोदी एनसीसी के कैडेट भी रहे। नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उनके गांव में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके शिक्षक और गांव वाले बताते हैं कि कई लोग अपने काम कराने के लिए उनसे मिलते थे। लेकिन, मोदी ने अपने शिक्षक, गांव व समाज के नेताओं से कह रखा था कि किसी के निजी काम के लिए सिफारिश मत करना। हां, यदि गांव और समाज का कार्य होगा तो दरवाजे हमेशा खुले हैं।

मां से था गहरा लगाव : हरगोविंद पटेल बताते हैं कि मोदी को बचपन से ही अध्यात्म में रुचि थी। समय मिलता तो स्कूल के पास में ही रेलवे स्टेशन पर अपने पिता दामोदर दास मोदी की चाय की दुकान पर जाकर काम करते। मां हीराबा के साथ उनका गहरा लगाव था। लेकिन, मोदी जब कोई गलती करते तो हीराबा उन्हें डांट भी लगाती थीं।

तालाब से पकड़ लिया था मगरमच्छ का बच्चा : शर्मिष्ठा तालाब में तैरने का मोदी को बहुत शौक था। एक बार वह तालाब से मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर ले आए तो मां ने डांटा और कहा कि बच्चे की मां उसे तलाश रही होगी। नरेन्द्र ने तत्काल उस मगरमच्छ के बच्चे को तालाब में छोड़ दिया।

वडनगर स्थित वह घर, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्म हुआ। जागरण

नामांकन वापसी के बाद चौथे चरण के मुकाबले की तस्वीर साफ

यूपी की 13 सीटों के लिए 130, बिहार में पांच सीटों के लिए 55 तो बंगाल में आठ सीटों पर 75 प्रत्याशी मैदान में

जागरण टीम, नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए 13 मई को 90 संसदीय सीटों के लिए मतदान होगा। सोमवार को नामांकन वापसी का अंतिम दिन होने से मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। चौथे चरण में तेलंगाना की सभी 17, आंध्र प्रदेश की सभी 25, बिहार की पांच, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, जम्मू-कश्मीर की एक, बंगाल व मध्य प्रदेश की आठ-आठ और ओडिशा व झारखंड की चार-चार संसदीय सीटों के लिए मतदान होगा।

उत्तर प्रदेश में 13 सीटों के लिए 130 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई मिश्रिख, उन्नाव, फर्रूखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर व बहराइच में मतदान होगा। प्रदेश में छठे चरण में 14 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी सोमवार शुरू हो गई। इस चरण में सुलतानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोही के लिए वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की आठ सीटों के लिए 82 उम्मीदवार मैदान में हैं।

बिहार में चौथे चरण में पांच लोकसभा सीटों दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर के लिए मतदान होना है। नामांकन वापसी के बाद 55 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। छठे चरण की आठ सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम आरंभ हो गया है। छठे चरण में वाल्मीकिनगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान एवं महाराजगंज लोकसभा की सीटें शामिल हैं। पांचवें चरण के नामांकन के दूसरे दिन पांच लोकसभा क्षेत्रों में मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर (अजा) लोकसभा क्षेत्रों में कुल 15 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इसमें सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी आचार्य रोहिणी और हाजीपुर (अजा) लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी शिवचंद्र राम शामिल हैं।

बंगाल में चौथे चरण में कुल 75 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 22 निर्दलीय हैं। बहरमपुर, कृष्णानगर, रणाघाट, बर्द्धमान पूर्व, बर्द्धमान-दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर व बीरभूम में मतदान होंगे। छठे चरण के लिए भी नामांकन शुरू हो गया।

राजनाथ सिंह ने लखनऊ तो स्मृति ने अमेठी से किया नामांकन

लखनऊ में नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले रोड शो के दौरान भाजपा प्रत्याशी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ में उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे।

लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को अमेठी में भाजपा प्रत्याशी स्मृति इरानी के नामांकन पत्र दाखिल करने के अवसर पर रैली के दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। प्रेट्र

जागरण टीम, लखनऊ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लखनऊ में नामांकन किया तो अमेठी में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने लगातार तीसरी बार अपनी दावेदारी पुख्ता की। नामांकन करने निकले राजनाथ के रथ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी भी सवार थे। उनके नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सड़कें भगवा रंग में रंगी दिखी। सुबह करीब सवा दस बजे राजनाथ नामांकन जुलूस में शामिल होने के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे और खास तरह से बने रथ में सवार हुए तो हर तरफ नारों की गूंज सुनाई दी।

अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने दो सेट में अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी निशा अनंत को सौंपा।

अमेठी में रोड शो के दौरान भिड़े भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता: केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी के नामांकन के पहले से गौरीगंज में कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय के सामने भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस ने तत्काल लोगों को अलग किया।

पति हेमंत से अमीर हैं कल्पना सोरेन

जागरण संवाददाता, गिरिडीह: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अमीर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हैं। सोमवार को गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान शपथ पत्र में कल्पना सोरेन ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी। कल्पना के पास 27,28,481 रुपये नकद हैं, जबकि हेमंत के पास 6,64,000 रुपये। कल्पना के बैंक खातों में करीब 85 लाख रुपये जमा हैं, जबकि हेमंत के बैंक खातों में 62 लाख रुपये से अधिक हैं। शपथ पत्र में बताया गया कि कल्पना ने शेयर बाजार में भी 61 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया है। उनके नाम पर तीन गाड़ियां हैं। कल्पना ने सिंबियोसिस सेंटर फार डिस्टेंस लर्निंग से वर्ष 2012 में एमबीए किया है। व्यवसाय और सामाजिक कार्यों से उन्हें वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 81 लाख रुपये से अधिक की आय हुई। उनके पास 91 लाख से अधिक के गहने और हरियाणा में प्रापर्टी भी है।

कल्पना सोरेन।

आतंकी फंडिंग के आरोपित व तिहाड़ में बंद इंजीनियर रशीद ने भरा नामांकन

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर : आतंकी फंडिंग का आरोपित व अवामी इत्तेहाद पार्टी का चेयरमैन इंजीनियर रशीद बारामुला संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है। सोमवार को समर्थकों ने रशीद का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी मिंगा शेरपा को सौंपा। पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद के अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार मुदस्सिर अहमद तांत्रे ने भी अपना नामांकन जमा कराया है। बारामुला सीट के लिए अब तक एक कवरिंग उम्मीदवार समेत कुल तीन उम्मीदवारों ने नामांकन जमा कराए हैं। नेशनल कान्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स कान्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन भी बारामुला सीट से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पीडीपी ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य मीर फैयाज को अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। इंजीनियर रशीद का वास्तविक नाम शेख रशीद है और वह जिला कुपवाड़ा में लंगेट से वर्ष 2009 और 2014 में विधायक भी रह चुका है। आतंकी अफजल व बुरहान समेत आतंकियों की तुलना महान क्रांतिकारी भगत सिंह से करने वाला रशीद अक्सर विवादित बयानबाजी के कारण सुर्खियों में रहा है। उसे अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया गया था।

बुलडोजर लेकर पहुंचा प्रत्याशी

नई दिल्ली के मंगोलपुरी में सोमवार को उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी योगेंद्र चांदोलिया के समर्थन में रोड शो में बुलडोजर लेकर पहुंचा कार्यकर्ता। हरीश कुमार

गठबंधन को लगा दूसरा झटका

प्रथम पृष्ठ से आगे

मध्य प्रदेश में विपक्षी दलों के गठबंधन आइएनडीआइए को यह दूसरा झटका है। गठबंधन में सपा को खजुराहो सीट मिली थी। यहां सपा प्रत्याशी का नामांकन रद हो चुका है। कांग्रेस व सपा ने खजुराहो सीट पर फारवर्ड ब्लाक के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है।

प्रचार के दौरान लगाया था जय श्रीराम का नारा : अक्षय ने कांग्रेस का साथ छोड़ने की भनक कांग्रेस नेतृत्व व स्थानीय नेताओं को भी नहीं लगने दी। रविवार शाम तक वह जनसंपर्क करते रहे। इंदौर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र चंदन नगर व आसपास क्षेत्र में प्रचार के दौरान उनके जय श्रीराम के नारे लगाने पर वार्ड के स्थानीय नेताओं ने पार्टी नेताओं से शिकायत की थी कि बम अल्पसंख्यक क्षेत्र में जय श्रीराम के नारे लगाकर पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं।

चार दिन पहले लिखी गई पटकथा : कांग्रेस को चुनावी मैदान से बाहर करने की पटकथा चार दिन पहले लिखी जा चुकी थी। अक्षय के खिलाफ 2007 में दर्ज एक प्रकरण में धारा 307 बढ़ाकर अधिरोपित किया गया। न्यायालय ने इस मामले में 10 मई को

> अक्षय कांति बम पर पुराने मामले में धारा 307 बढ़ाकर न सिर्फ दबाव बनाया गया, बल्कि उन्हें डराया-धमकाया गया और आज ले जाकर नामांकन वापस करा दिया गया। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले इंदौरवासियों को भाजपा की इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा होना होगा।
>
> -जीतू पटवारी, कांग्रेस अध्यक्ष, मध्य प्रदेश

> कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अपने घर में ही कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन वापस ले रहा है। कांग्रेस की हालत बदतर हो चुकी है। प्रदेश में हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे।
>
> -वीडी शर्मा, भाजपा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश

> कांग्रेस के उम्मीदवार पार्टी छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। उनके उम्मीदवारों का ही भरोसा अपनी पार्टी पर नहीं है। -शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री

आरोपित अक्षय बम को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। इसके बाद भाजपा के स्थानीय नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस प्रकरण के चलते उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उधर, कांग्रेसी नेता आरोप लगा रहे हैं कि अक्षय बम द्वारा संचालित कालेजों व जमीन से जुड़े कारोबार को लेकर सत्ताधारी दल के नेता कार्रवाई का दबाव बना रहे थे।

आइएनडीआइए का पीएम उम्मीदवार कौन : नड्डा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा और एनडीए लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या कोई यह जानता है कि विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने ही एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की योजना बनाई है।

जेपी नड्डा सोमवार को तेलंगाना के कोठागुडेम और महबूबाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए को अहंकारी बताते हुए कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि विपक्षी गठबंधन से कौन प्रधानमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि भगवान न करें राहुल गांधी को कोई प्रधानमंत्री बना दे। आपको क्या लगता है कि वे कोरोना जैसे महामारी से लड़ने में सक्षम हैं। क्या राहुल गांधी महंगाई से लड़ सकते हैं। क्या वे विकास में योगदान दे सकते है। क्या वे वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

भाजपा अध्यक्ष बोले-कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को देगी

तेलंगाना में जेपी नड्डा ने कहा-विपक्षी गठबंधन के सभी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त

तेलंगाना के महबूबाबाद में सोमवार को आयोजित चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत एक माला पहनाकर किया गया। एएनआइ >>

रैली में नड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अहंकारी गठबंधन के नेताओं को सिर्फ सत्ता से प्यार है। उन्हें जनता की सेवा में बिल्कुल भी रुचि नहीं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ लेकिन गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टों को बचाओ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस घबरा गई है। इसलिए वे गृहमंत्री शाह का फर्जी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं।

कांग्रेस की सरकार ने ही एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की योजना बनाई है। संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर ने साफ कहा था कि आरक्षण कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होगा। आरक्षण सिर्फ जाति और पिछड़ेपन के आधार पर ही दिया जाएगा।

चुनावी हलचल

नामांकन रद होने पर सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीरभूम लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार देबाशीष धर ने अपना नामांकन पत्र रद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। देबाशीष धर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील निधेश गुप्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। धर के वकील ने कोर्ट को बताया कि आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। अदालत ने कहा कि वह सूचीबद्ध करने की धर की याचिका पर गौर करेगी। पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर पश्चिम बंगाल की बीरभूम संसदीय सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। बंगाल की शेष सीटों के लिए मतदान चार मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को होंगे। वोटों की गिनती चार जून को निर्धारित की गई है। बीरभूम में 13 मई को चुनाव होना है।

देवाशीष धर। फाइल

सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट स्लिप के मिलान की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिये मतदान के साथ वीवीपैट की पर्ची को जांचने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को बताया कि पिछले हफ्ते सर्वोच्च अदालत की एक पीठ ने इस पर फैसला भी सुनाया था। खंडपीठ ने याचिका को ठुकराते हुए कहा कि एक खंडपीठ ने पहले ही इस पर अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि यह पारदर्शिता का मुद्दा है तो कोर्ट ने कहा कि दो दिन पहले एक अन्य खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश पारित कर दिया है।

तमिलनाडु में अब तक 1309 करोड़ की नकदी व सोना जब्त

चेन्नई, प्रेट्र : तमिलनाडु में चुनाव आयोग और आयकर विभाग के अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1309.52 करोड़ की नकदी, शराब, बहुमूल्य धातुएं एवं अन्य मुफ्त में वितरित किए जाने वाला सामान जब्त किया है। तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यव्रत साहू ने बताया कि कुल राशि में से 179.91 करोड़ की नकदी और 1083.78 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं जब्त की गई हैं। इसके साथ ही 35.8 करोड़ रुपये की मुफ्त में बांटी जाने वाले सामग्री भी जब्त की गई है।

'अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूसीसी का इस्तेमाल कर रही भाजपा'

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। साथ ही ममता ने कांग्रेस व माकपा को भाजपा की एजेंट करार देते हुए मतदाताओं से दोनों दलों का समर्थन नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व माकपा बंगाल में भाजपा की दो आंखें हैं। मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र में सोमवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि आरंभिक दो चरणों के मतदान से भाजपा को पता चल गया है कि वह हारने वाली है इसलिए विभाजनकारी राजनीति में जुट गई है। जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा एक के बाद एक मुद्दा खड़ा कर तनाव पैदा करने में जुट जाती है।

ममता बनर्जी। फाइल

'यह चुनाव संविधान बदलने और बचाने वालों के बीच...संविधान बदलने वालों को बदल दो'

जागरण टीम, आगरा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा, एटा और हाथरस में जनसभा को किया संबोधित

हाथरस में जनसभा को संबोधित करते अखिलेश यादव। जागरण

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को आगरा, एटा और हाथरस की जनसभाओं में भाजपा की संविधान बदलने की मंशा पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, यह चुनाव संविधान बचाने और उसे बदलने वालों के बीच है। संविधान बदलने वालों को बदल दो। यह अमित शाह के राम मंदिर बनाने और गोली चलाने वालों के बीच चुनाव के बयान पर उनका जवाब था। परिवारवाद के आरोप पर कहा, हमारा परिवार संघर्ष करने वालों का है। आगरा में अपनी पहली जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा एक बार फिर सत्ता में आई तो वह डा. भीमराव आंबेडकर के संविधान को बदल देगी। 2024 का चुनाव संविधान बचाने का है। एक तरफ संविधान के भक्षक हैं तो दूसरी तरफ रक्षक। भाजपा सरकार में कोई भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं हुई, जिसका पेपर लीक न हुआ हो। एटा में सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य के समर्थन में उन्होंने कहा, यह चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का है। भाजपा ने किसान आंदोलन को रोकने के लिए बड़ी-बड़ी दीवार लगा दी। सड़कों पर कीलें ठोंक दीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपराधी बनाकर जेल भेज दिया। यह कानून का दावा करते हैं। उत्तर प्रदेश के आंकड़े देख लें। हाथरस में कहा कि खाकी वर्दी वाले अन्याय कर रहे हैं।

भाजपा हिंदुत्व की आड़ में कर रही जुल्म, सपा टिकट में पक्षपात : मायावती

जागरण संवाददाता, बदायूं : बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि भाजपा हिंदुत्व की आड़ में जुल्म कर रही है। अल्पसंख्यकों का विकास नहीं हो सका। सपा टिकट वितरण में पक्षपात करती है। हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हिंदू को टिकट दिया जाता है। हिंदुओं के टिकट चयन में भी जाति और परिवार को वरीयता दी जाती है। यही कारण है कि सपा ने बदायूं में परिवार के सदस्य को प्रत्याशी बना दिया। संभल में मुस्लिमों में ऊंची जाति को अवसर नहीं मिल रहा था, हमारी पार्टी ने दिया। आंवला और बदायूं में भी मुस्लिम प्रत्याशी का संदर्भ देकर कहा कि हम सर्वसमाज को भागीदारी देते हैं। जनसभा में मायावती ने कहा कि गलत नीतियों के कारण केंद्र और कई प्रदेशों से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई।

अब आप नेता मकवाणा ने राजा-महाराजा पर साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, जागरण, अहमदाबाद: गुजरात की राजनीति में राजा-महाराजाओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आदमी पार्टी (आप) के भावनगर से प्रत्याशी ने आग में घी डालने का काम किया है। आप नेता उमेश मकवाणा ने कहा है कि राजा-महाराजा नशा कर पड़े रहते थे।

भावनगर सीट पर आइएनडीआइए के उम्मीदवार उमेश मकवाणा ने कहा कि राजा और महाराजा नशा कर पड़े रहते थे। इसीलिए, उनका राज चला गया और अंग्रेजों का शासन आ गया। इससे पहले राजकोट से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला ने कहा था कि राजे-रजवाड़ों ने मुगलों से रोटी-बेटी का संबंध बना लिया था। इसे लेकर राजपूत समाज के विभिन्न संगठन बीते एक माह से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। रुपाला का विरोध करने के बाद उनका टिकट न कटने पर संगठनों ने अब भाजपा का विरोध करना शुरू कर दिया है।

45 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुंच गया है, जिससे बिजली ग्रिडों पर दबाव पड़ रहा है। भीषण गर्मी के कारण झारखंड में आठवीं तक के स्कूल और केरल में स्कूल कालेज बंद कर दिए गए है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 30 अप्रैल, 2024

'बंगाल सरकार व्यक्ति की ओर से कैसे बनी पक्षकार'

संदेशखाली मामले में राज्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हड़पने की सीबीआइ जांच का हाई कोर्ट ने दिया था आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हड़पने के मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य सरकार ने किसी निजी व्यक्ति का हित संरक्षित करने के लिए याचिका क्यों दाखिल की? जब राज्य सरकार के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, तो शीर्ष अदालत का कहना था कि टिप्पणियां हटवाने के लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट जा सकती थी।

ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश के खिलाफ दाखिल बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को कीं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हड़पने के मामले की सीबीआइ जांच के

सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई।

आदेश दिए हैं। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख मुख्य आरोपित है। काफी समय तक फरार रहने के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल जेल में है।

सोमवार को राज्य के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश में राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, जबकि राज्य सरकार मामले में पूरी सक्रियता से काम कर रही थी। इसलिए याचिका दाखिल की गई है। इस पर पीठ का कहना था कि अगर टिप्पणियों से शिकायत थी तो राज्य सरकार उन्हें हटवाने के लिए हाई कोर्ट जा सकती थी। तभी बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें पता चली हैं। उस सामग्री को वह दाखिल करना चाहते हैं। यह भी कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में जो निष्कर्ष दिए गए हैं, उन्हें चुनौती देने की जरूरत थी। दूसरी ओर सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि कोर्ट आदेश दे कि मामला यहां लंबित रहने को किसी जगह आधार नहीं बनाया जाएगा। इस पर सिंघवी ने कहा कि वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने तो विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की है। सिंघवी की दलीलों पर पीठ की टिप्पणी थी कि अगर किसी ने हाई कोर्ट के आदेश को आधार बना कर अवमानना याचिका दाखिल की तो राज्य सरकार हाई कोर्ट जाकर कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। कोर्ट ने कहा कि वह आदेश में स्पष्ट कर रहा है कि मामले की सुनवाई राज्य सरकार के कहने पर स्थगित की जा रही है। इसलिए एसएलपी के लंबित रहने को हाई कोर्ट में सुनवाई लटकाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने सुनवाई जुलाई तक टालते हुए कहा कि मामले पर सुनवाई का माहौल तभी होगा। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ जमीन हड़पने के मामले की जांच का ही है।

25,753 नौकरियां रद करने का फैसला बरकरार

शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआइ जांच पर रोक

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआइ जांच कराने संबंधी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद करने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट राज्य संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद करने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने नियुक्तियों को रद करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया और कहा कि वह इस मामले पर छह मई को सुनवाई करेगी।

यह देखते हुए कि 25 हजार से अधिक लोगों की नौकरियां छीनना एक गंभीर मामला है, शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या उपलब्ध सामग्री के आधार पर वैध और अवैध नियुक्तियों को अलग करना संभव है? क्या यह पता लगाया जा सकता है कि धोखाधड़ी का लाभ किन लोगों को मिला? पीठ ने कहा, हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे, जिसमें कहा गया है कि सीबीआइ राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआइ अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों के निर्माण को मंजूरी देने में शामिल व्यक्तियों के संबंध में आगे की जांच करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो सीबीआइ इसमें शामिल लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी।

आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में कहा कि हाई कोर्ट ने मनमाने ढंग से नियुक्तियों को रद कर दिया। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट पूरी चयन प्रक्रिया को रद करने के प्रभाव को समझने में विफल रहा। राज्य सरकार को ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना तत्काल प्रभाव से शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सीधे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके चलते शिक्षा प्रणाली ठप हो गई है।

अंकगणित से नहीं सरकार के प्रयास से तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत

कांग्रेस नेता चिदंबरम के अर्थव्यवस्था के बयान पर बरसीं सीतारमण

कहा-कुछ भी अपने आप नहीं हो जाता, प्रयास से ही विकास होता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की पर हाल ही में दिए गए कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बयान पर सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जमकर बरसीं। विशाखापत्तनम में आयोजित एक कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि अंकगणितीय अनिवार्यता से नहीं बल्कि सरकार के प्रयास से भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।

कांग्रेस नेता चिदंबरम ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री कोई भी बने इस समय जहां अर्थव्यवस्था है, उसके बाद भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा ही। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के दौरान कई बार यह कह चुके हैं कि पिछले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने पांचवें स्थान पर ला दिया और अब यह मोदी की गारंटी है कि तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले का दस साल पूर्ण रूप से खोया हुआ दशक था। तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए भारत को स्थिर सरकार की जरूरत है। कुछ भी अपने आप नहीं हो जाता है, प्रयास से ही विकास होता है। सीतारमण ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री विकास को लेकर ऐसी

निर्मला सीतारमण। फाइल

धारण बनाना चाहते हैं जो पूरी तरह से असत्य है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले के दस सालों में खराब नीति, व्यापक रूप से फैले हुए भ्रष्टाचार से अर्थव्यवस्था असल में वर्ष 2004 की स्थिति से भी नीचे चली गई थी। उन्होंने कहा कि जीडीपी रैंकिंग और प्रति व्यक्ति आय के साथ देश की छवि भी बहुत मायने रखती है। अगर किसी परिवार की आय ठीक-ठाक नहीं है तो उस परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतें पूरी नहीं की जा सकतीं। वैसे ही, देश का जीडीपी अधिक नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था की मांग पूरी नहीं की जा सकती है।

यूजीसी-नेट की तिथि बदली, परीक्षा अब 18 जून को होगी

पहले 16 जून को होनी थी परीक्षा, इस बार पीएचडी दाखिले की भी जारी होगी रैंकिंग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख के साथ टकराव को देखते हुए यूजीसी-नेट (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 18 जून को होगी। पहले यह परीक्षा 16 जून को प्रस्तावित थी। छात्रों की ओर से परीक्षा की तारीख में बदलाव को लेकर लगातार की जा रही मांग के बाद यह फैसला लिया गया है।

यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने सोमवार को परीक्षा की तारीख में बदलाव की यह जानकारी दी। साथ ही बताया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी-नेट की पूरी परीक्षा एक दिन में ओएमआर मोड से आयोजित करने का फैसला किया है। यूजीसी चेयरमैन के मुताबिक 'एनटीए और यूजीसी ने आवेदकों की ओर से मिल रहे अनुरोध के आधार पर यूजीसी-नेट परीक्षा की तारीख को 16 जून रविवार से बदलकर 18 जून, 2024 मंगलवार

प्रतीकात्मक

करने का फैसला किया है। एनटीए की ओर से जल्द ही इसे लेकर औपचारिक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।' खास बात यह है कि इस बार यूजीसी-नेट की परीक्षा का परिणाम तीन श्रेणियों में जारी किया जाएगा। इनमें एक श्रेणी पीएचडी दाखिले की भी होगी। इसके आधार पर छात्रों को विश्वविद्यालयों में पीएचडी में दाखिला मिलेगा। इससे पहले यूजीसी नेट परीक्षा के जरिये दो श्रेणियां ही जारी की जाती थीं।

एनसीईआरटी को पाठ्यपुस्तकें अपडेट करने का निर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र : शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) से अपनी पाठ्यपुस्तकों की सालाना आधार पर समीक्षा करने और नया अकादमिक सत्र शुरू होने से पहले इन्हें अपडेट करने को कहा है। अब तक, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को अपडेट करने पर कोई दिशानिर्देश नहीं था।

सूत्र ने कहा कि एनसीईआरटी की किताबें एक बार प्रकाशित होने के बाद कई वर्षों तक वैसी ही नहीं रहनी चाहिए। मुद्रण से पूर्व हर वर्ष उनकी समीक्षा की जानी चाहिए और यदि कोई परिवर्तन करना हो या कुछ नए तथ्य जोड़ने हों तो उन्हें पुस्तकों में शामिल कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय बहुत विकसित हो रहे हैं। इसे पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए।

वर्तमान में, एनसीईआरटी पिछले साल घोषित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) के अनुसार पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की प्रक्रिया में जुटी है। सूत्रों ने बताया कि नये पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तकें सभी कक्षाओं के लिए 2026 तक तैयार हो जाएंगी।

जदएस से निलंबित होंगे सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपित प्रज्वल रेवन्ना

जदएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने किया एलान

बेंगलुरु, प्रेट्र : जदएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पौत्र और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सेक्स स्कैंडल के आरोपों में पार्टी से निलंबित करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा और जदएस के साथ उसके गठबंधन पर हमलावर है।

पुलिस ने रविवार को प्रज्वल और उनके विधायक पिता व पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के विरुद्ध उनके घर में काम करने वाली महिला की शिकायत पर यौन उत्पीड़न और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। राज्य सरकार ने एक एसआइटी का गठन किया है और एचडी रेवन्ना व प्रज्वल के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी उसे संदर्भित कर दी है। 33 वर्षीय प्रज्वल हासन से राजग प्रत्याशी हैं, इस सीट पर शुक्रवार को मतदान हुआ था।

कुमारस्वामी ने दावा किया, 'निर्णय पहले ही हो चुका है। मंगलवार को हुबली में कोर कमेटी की बैठक में इसकी अनुशंसा की जानी है क्योंकि वह (प्रज्वल) सांसद हैं इसलिए यह दिल्ली से विद्वानों की कड़ी जुड़ गई तो बड़ी सफलता मिलेगी और कई रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा।

केमिकल से किया जाएगा साफ : सील को सबसे पहले बड़ी बारीकी से एसीटोन केमिकल से साफ किया जाएगा। यह सील करीब दो इंच लंबी और दो इंच चौड़ी हैं। इसको बनाने के लिए चूना व पत्थर का प्रयोग किया गया है। सील पर जो पशु का चित्र बनाया गया है उसके काफी लंबे सींग हैं।

****

प्रज्वल रेवन्ना (फाइल)। इंटरनेट मीडिया

के विरुद्ध अत्याचार करने के बाद देश छोड़ने में कैसे सक्षम हो गए। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के कार्यालय ने एक बयान में कहा था, प्रज्वल (मतदान खत्म होने के बाद) देश छोड़कर चले गए हैं। कलबुर्गी में एक रैली में प्रियंका ने कहा, "जिस व्यक्ति (प्रज्वल) ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया और जिसके लिए मोदी ने वोट मांगे, उसने हजारों महिलाओं पर अत्याचार किया। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहती हूं कि वे इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं।" उन्होंने कहा, "उन्हें पता चल जाता है कि मैं या विपक्षी नेता कहां गए हैं, लेकिन ऐसे अपराधी व इस तरह का राक्षस देश छोड़कर चला जाता है और उन्हें पता नहीं चलता।"

कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने जदएस नेता देवराज गौड़ा द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र को पिछले वर्ष आठ दिसंबर लिखा पत्र एक्स पर साझा किया, जिसमें प्रज्वल के अश्लील वीडियो की पेनड्राइव की जानकारी दी गई थी।

गृह मंत्रालय ने दो दिन पहले दिल्ली पुलिस को दी थी शिकायत

प्रथम पृष्ठ से आगे

इंटरनेट मीडिया पर शाह का फेक वीडियो प्रसारित होने के संज्ञान में आने के बाद गृह मंत्रालय ने दो दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को शिकायत दी। आयुक्त के निर्देश पर आइएसएफओ यूनिट ने भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ ही कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष से भी पूछताछ की जाएगी। मुख्यमंत्री के अलावा जिन अन्य लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनमें तेलंगाना कांग्रेस के नेता माने सतीश, नवीन, शिवाशंकर, अस्मा तस्लीम आदि शामिल हैं। इनमें कांग्रेस के कुछ नेता और कुछ अन्य लोग हैं। आरोप है कि इन्होंने एडिट वीडियो इंटरनेट प्लेटफार्मों पर साझा किया था। पुलिस इनसे पूछताछ कर वीडियो बनाने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगी।

झारखंड के पूर्व सीएम सोरेन की अंतरिम जमानत पर ईडी से जवाब तलब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर छह मई तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट इस बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुना सकता है। ये आदेश सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। मामला 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लांड्रिंग का है।

सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी करके 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसला न सुनाने का मुद्दा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत देने की मांग की है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सोरेन के खिलाफ कोई तथ्य नहीं है फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

नीट-पीजी अभ्यर्थियों के इंटर्नशिप कटआफ संबंधी याचिका खारिज

कहा- पूरी तरह से नीतिगत दायरे में आते हैं ये मामले

15 अगस्त है नीट-पीजी इंटर्नशिप की कट-आफ तारीख

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी के उम्मीदवारों के लिए इंटर्नशिप कट-आफ को बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इन्कार कर दिया। यह परीक्षा इस साल इस साल 23 जून को होने वाली है। राष्ट्रीय पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) में उपस्थित होने के लिए इंटर्नशिप की कट-आफ तिथि 15 अगस्त है।

दलीलें सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कहा कि ये मुद्दे पूरी तरह से नीतिगत दायरे में आते हैं। हालांकि पीठ ने स मामले में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर निवासी याचिकाकर्ता रिद्धेश को उन अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दे दी, जिनसे इस संबंध में पहले अनुरोध किया गया था।

सीए परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इन्कार कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि आठ मई और 14 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए क्योंकि सात मई और 13 मई को कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सीए परीक्षाएं दो मई से 17 मई तक चलने वाली हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मतदान की तारीखों पर कोई परीक्षा नहीं है। परीक्षा की तारीख में बदलाव से छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। परीक्षा शेड्यूल नीतिगत निर्णय है।

केंद्र ने सूखा प्रबंधन के लिए कर्नाटक को जारी किए 3,400 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में सूखा प्रबंधन के लिए कर्नाटक को लगभग 3,400 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ कर्नाटक सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

कर्नाटक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 3,450 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, लेकिन राज्य का अनुरोध 18,000 करोड़ रुपये की सहायता के लिए था। सूखे के कारण जिन परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है, उन्हें राहत के लिए मांगी गई राशि 12,577 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि जो राशि दी गई है, उसके लिए हम आभारी हैं। सिब्बल ने कहा कि एक अंतर-मंत्रालयी टीम ने राज्य का दौरा किया था और उप-समिति को रिपोर्ट दी थी, जिसने फिर इसे निर्णय लेने के लिए उचित प्राधिकारी को भेजा था।

अटार्नी जनरल ने कहा कि अंतर-मंत्रालयी टीम ने जो भी सिफारिश की थीं, उप-समिति ने उसे ध्यान में रखा है। पीठ ने उनसे अंतर-मंत्रालयी टीम की सिफारिश पेश करने को कहा।

बाबा रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा को बदनाम किया : आइएमए अध्यक्ष

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबा रामदेव को फटकार लगाने के बाद आइएमए की पहली टिप्पणी

आइएमए अध्यक्ष ने कहा, बाबा रामदेव ने कोविड के उपचार के नाम पर हद पार की

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के अध्यक्ष डा.आरवी अशोकन ने सोमवार को कहा कि बाबा रामदेव ने उस समय हद पार कर दी जब उन्होंने दावा किया कि उनके पास कोविड-19 का उपचार है। उन्होंने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को मूर्खतापूर्ण एवं दिवालिया विज्ञान कहकर बदनाम किया। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामदेव और उनकी औषधि कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाए जाने के बाद आइएमए की यह पहली टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट में 30 अप्रैल को मामले की सुनवाई होने वाली है।

सुप्रीम कोर्ट आइएमए की 2022 की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कोविड रोधी टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक पद्धतियों को बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने पिछले महीने रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से भ्रामक विज्ञापनों पर उसके आदेशों का

डा. आरवी अशोकन। बाबा रामदेव। फाइल

पालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था।

प्रेट्र से बातचीत में अशोकन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइएमए और प्राइवेट डाक्टरों के तौर तरीकों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अस्पष्ट और अति सामान्य बयानों ने प्राइवेट डाक्टरों को हतोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी से मानते हैं कि उन्हें यह देखने की जरूरत है कि उनके सामने क्या सामग्री रखी गई है। अशोकन ने कहा कि आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर डाक्टर कर्तव्यनिष्ठ हैं, नैतिकता और सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं।

आइएमए प्रमुख ने कहा कि जब सरकार टीकाकरण कार्यक्रम चला रही थी तो रामदेव राष्ट्रीय हित के खिलाफ बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड रोधी टीके की दो खुराक लेने के बाद 20 हजार डाक्टरों की मृत्यु हो गई। उनका कद इतना ऊंचा है कि आप जानते हैं कि लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। आइएमए प्रमुख ने कहा कि उन्होंने हद पार कर दी जब उन्होंने कोरोनिल के बारे में विज्ञापन दिया और कहा कि डब्ल्यूएचओ ने इसे मंजूरी दे दी है जो कि एक गलत बयान था। आईएमए प्रमुख ने कहा, 'अदालत ने अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। हमें इंतजार करने की जरूरत है। हम संतुष्ट हैं या नहीं, यह फैसले पर निर्भर करेगा।'

इतिहास

सील पर अंकित लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे विशेषज्ञ, इस पर एक पशु का चित्र भी बना है, जिसके लंबे सींग हैं

राखीगढ़ी में खोदाई में टीले पर मिली सील

सुनील मान ● जागरण

हिसार : हरियाणा के राखीगढ़ी में हो रही खोदाई से आठ हजार वर्ष पुरानी हड़प्पाकालीन सभ्यता के रहस्य उजागर हो रहे हैं। अब खोदाई के दौरान टीले पर एक सील मिली है। सील पर मौजूद लिपि को विद्वान पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें इससे काफी मदद मिलेगी। क्योंकि सील पर जो लिपि अंकित है वह स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। इस पर एक पशु का चित्र भी उकेरा गया है। उस समय इस सील का प्रयोग व्यापारिक गतिविधियों के लिए करते थे।

राखीगढ़ी के टीला-एक पर खोदाई के दौरान सील पाई गई है। वैसे तो अलग-अलग सीजन के दौरान दर्जनों सील मिल चुकी है, लेकिन काफी सारी सील टूटी हुई पाई गई थी। जिनकी कड़ी जोड़ने के लिए काफी प्रयास किया जा रहे हैं। इस बार मिली ये सील पूरी तरह से ठीक है। सील के सभी किनारे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस पर एक हुक भी लगा हुआ है। शायद उस समय की यह एक महत्वपूर्ण सील हो।

टीलें तीन पर खोदाई में मिली सील। जागरण

राखी गढ़ी में खोदाई के दौरान मिली हुई सील। जागरण

हुक में कोई चीज डालकर इसको गले में डाला जाता होगा, ताकि इसको संभाल कर रखा जा सके। पहले जो सील अब तक मिल चुकी है उन पर भी अलग-अलग प्रकार के पशु व मानव के चित्र अंकित हैं। खोदाई के दौरान मिली सील, पाटरी, बड़े बर्तन, मिट्टी पर छाप इत्यादि काफी जगह पर उसे समय की लिपि लिखी हुई मिली है, लेकिन अब तक उसको पढ़ा नहीं जा सका। इस सील पर लिखी लिपि

व्यापारिक गतिविधियों के लिए होता था सील का प्रयोग

सील का प्रयोग वो लोग व्यापारिक गतिविधियों के लिए करते थे, क्योंकि टीलों पर मिले मनके इसका पुख्ता प्रमाण है। यहां पर पत्थर होने का अब तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। खोदाई के दौरान यहां पर काफी मनके मिल चुके हैं। यहां पर खेतीबाड़ी बड़े पैमाने पर होती थी और वह लोग इसका भी दूसरी जगह व्यापार करते थे। जिसमें सील का इस्तेमाल किया जाता होगा।

वह लोग सील का प्रयोग व्यापारिक गतिविधियों के लिए करते थे इसके प्रमाण मिल चुके हैं। जो सील मिली है इस पर लिखी लिपि से विद्वानों को पढ़ने में काफी सहायता मिल सकती है। अब तक उस समय की लिपि को कोई भी विद्वान नहीं पढ़ पाया है।

- संजय कुमार मंजुल, अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली

केंद्रीय कर्मियों के बच्चों का शिक्षा भत्ता, हास्टल सब्सिडी 25% बढ़ी

केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, एक जनवरी से है प्रभावी

50 प्रतिशत डीए बढ़ने से स्वत: बढ़ा 25 प्रतिशत शिक्षा भत्ता

नई दिल्ली, प्रेट्र : कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा भत्ते (सीईए) और हास्टल सब्सिडी की सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार ने यह कदम एक जनवरी, 2024 से प्रभावी हुए महंगाई भत्ते को बढ़ाने की घोषणा के बाद उठाया है।

वर्ष 2018 के दिशा-निर्देशों को देखते हुए जब भी महंगाई भत्ते (डीए) में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी, हर बार स्वतः ही बच्चों के शिक्षा भत्ते और हास्टल सब्सिडी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार वित्त मंत्रालय ने विगत 12 मार्च, 2024 को इसी साल एक जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत का इजाफा प्रभावी हो जाएगा। लिहाजा, विभिन्न क्षेत्रों से बच्चों के शैक्षणिक भत्ते (सीईए) और हास्टल सब्सिडी के बढ़ाए जाने को लेकर संज्ञान लिया गया है। बच्चे का शिक्षा भत्ता प्रति माह 2,812.5 रुपये (फिक्सड) और हास्टल सब्सिडी प्रति माह 8,437.5 रुपये (फिक्सड) होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता सामान्य से दोगुना होगा। मौजूदा समय में सामान्य दर 5,625 रुपये प्रति माह (फिक्सड) है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों को जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि दिव्यांग महिलाओं के चाइल्ड केयर के लिए विशेष भत्ता है। यह प्रति माह 3,750 रुपये प्रति माह (फिक्सड) है। यह सभी बढ़ोतरी एक जनवरी, 2024 से लागू हैं।

29 जून से इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और यह 19 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान देशभर से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।

भारत के विभाजन ने पूर्वोत्तर के प्राकृतिक संपर्क को तोड़ दिया : एस जयशंकर

'दक्षिण पूर्व एशिया और जापान के साथ पूर्वोत्तर भारत का एकीकरण ' विषय पर संबोधन

कहा- बांग्लादेश संबंधों में नाटकीय सुधार का बड़ा लाभार्थी रहा पूर्वोत्तर भारत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार में सेना के सत्ता में आने के बाद कई अन्य गंभीर समस्याएं

भारत के विभाजन ने कई तरह से पूर्वोत्तर राज्यों का प्राकृतिक संपर्क तोड़ दिया, लेकिन पिछले एक दशक में केंद्र सरकार के प्रयासों से क्षेत्र में संसाधनों में सुधार हुआ है। यह बात विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने कही। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कालेज में 'दक्षिण पूर्व एशिया और जापान के साथ पूर्वोत्तर भारत का एकीकरणः आर्थिक संबंधों और पारिस्थितिक संरक्षण को संतुलित करना' विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

जयशंकर ने कहा कि पिछले दशक में म्यांमार और ताइवान जैसे पड़ोसी देशों के अलावा पूर्वी एशिया के अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों में सुधार हुआ है और यह इसे बाकी दुनिया से जोड़ता है। पूर्वोत्तर में मौजूदा आर्थिक स्थिरता मजबूत मोर्चे की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विभाजन के प्रभाव ने शुरू में राजनीतिक बाधाओं के साथ-

दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कालेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते विदेश मंत्री एस जयशंकर। सौजन्य कालेज

साथ प्रशासनिक मुद्दों के कारण पूर्वोत्तर में विकास को प्रभावित किया था। इसके परिणामस्वरूप, पूर्वोत्तर में विकास का जो स्तर देखा जाना चाहिए था वह धीमा हो गया। इसके बाद पहले कुछ दशकों में विभाजन के बाद, राजनीतिक बाधाओं और प्रशासनिक मुद्दों के कारण पूर्वोत्तर को वह लाभ नहीं मिला जो देश के अन्य हिस्सों को मिला।

उन्होंने कहा, अगर हम पिछले दशक को देखें, तो पूर्वोत्तर भारत-बांग्लादेश संबंधों में नाटकीय सुधार का बड़ा लाभार्थी रहा है। जब हमने 2015 में भूमि सीमा समझौता किया, तो एक बार चीजें शांत हो गईं, भारत और बांग्लादेश के बीच विश्वास का एक नया स्तर था। हमने देखा कि कई अन्य समस्याओं का समाधान हो रहा है, विशेष रूप से आतंकवाद और अस्थिरता से निपटने वाली समस्याएं। म्यांमार के मामले में, जयशंकर ने कहा कि भारत वहां चुनौतियों से निपटते हुए विकास के रास्ते बनाने की कोशिश कर रहा है।

म्यांमार एक बड़ी चुनौती रही है, जब तक वहां लोकतंत्र की बहाली नहीं हुई थी तब तक हमारे पास अत्यधिक समस्याएं थीं। पिछले कुछ वर्षों में सेना के सत्ता में आने के बाद अन्य गंभीर समस्याएं भी हैं। जबकि हम अपनी सीमा पर इसके परिणामों को कम कर रहे हैं। म्यांमार के माध्यम से कनेक्टिविटी को लेकर हमारी बड़ी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा, अगर यह सब काम हो जाता है और पूर्वोत्तर को म्यांमार के माध्यम से पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर बांग्लादेश की ओर कनेक्टिविटी मिलती है, तो भारत के समुद्री तट सहित पूरे पूर्वी भारत को और अधिक गहनता से विकसित किया जाएगा जो कि मोदी सरकार का उद्देश्य है। जापान और भारत के संबंधों के बारे में बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2017 में जापान के साथ एक विशेष मंच स्थापित करने के लिए कहा था।

उन्होंने कहा कि यह भारत का एकमात्र मंच है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास और उन्हें अन्य देशों के साथ जोड़ने के लिए समर्पित है। इन संबंधों के परिणामस्वरूप, कई भारतीय संस्थानों में जापानी भाषा के विस्तार सहित कई द्विपक्षीय विकास हुए हैं। उन्होंने कहा, हम एक ऐसा देश हैं जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं जिन्हें साकार नहीं किया जा सका। आंशिक रूप से हमने पूरे एक साल के लिए जी20 का आयोजन क्यों किया। पीएम का निर्देश था कि हम नहीं चाहते कि कोई भी राज्य राजनयिक ध्यान पाने से छूट जाए। इसे सिर्फ दिल्ली पर केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए या तीन या चार अन्य महानगरीय शहरों तक।

बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले पांच सालों में जापान व दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंध बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे है, जिससे संबंध बेहतर हुए हैं।

भारत बायोटेक के प्रमोटर कृष्णा एला बने नए आइवीएमए अध्यक्ष

हैदराबाद, प्रेट्र: भारत बायोटेक के सह-संस्थापक व कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एम. एला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (आइवीएमए) का नया अध्यक्ष घोषित किया गया। वह अप्रैल 2024 से अगले दो साल तक पदभार संभालेंगे। वह 2019 से मार्च 2024 तक अध्यक्ष पद पर रहे अदार सी. पूनावाला का स्थान लेंगे। आगामी दो साल के लिए बायोजिकल ई की प्रबंध निदेशक महिमा दातला आइवीएमए में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगी। भारत बायोटेक के सीएफओ टी. श्रीनिवास कोषाध्यक्ष और डा. हर्षवर्द्धन आइवीएमए के महानिदेशक के रूप में बने रहेंगे।

इस मौके पर एला ने कहा कि वैक्सीन वैश्विक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और आइवीएमए को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति तक जीवन रक्षक वैक्सीन पहुंच सकें।

उन्होंने कहा कि नवाचार, स्थिरता और समानता हमारी सामूहिक दृष्टि की नींव हैं और मुझे आइवीएमए के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ सेवा करने और भारत व विकासशील दुनिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और वृद्धि के लिए संस्था के दृष्टिकोण में योगदान करने में खुशी हो रही है। डा. हर्षवर्द्धन ने कहा कि डा. एला की विशेषज्ञता और उद्यमशीलता भावना से 21वीं सदी में वैक्सीन उद्योग की जटिल चुनौतियों से निपटा जा सकता है। इससे आम लोगों को काफी लाभ होगा।

'प्रेमी जोड़ा विवाह योग्य नहीं तो भी नहीं कर सकते अधिकारों से वंचित'

दयानंद शर्मा ● जागरण

- लिव इन में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश
- दोनों ने मांगी थी सुरक्षा, लड़की ने कहा, माता-पिता के साथ जाना नहीं चाहती
- लड़की को बालिग होने तक बाल गृह भेजने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल यह देखकर की याचिकाकर्ता विवाह योग्य आयु के नहीं हैं, उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की जो 19 वर्षीय लिव इन पार्टनर के साथ रह रही थी की सुरक्षा की मांग पर यह टिप्पणी की। सिरसा निवासी लड़की ने अपने परिवार व रिश्तेदारों से सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने लड़की को बाल गृह भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि चूंकि वह नाबालिग है, अदालत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह माता-पिता की तरह नाबालिग के हित में क्या सर्वोत्तम है, उसके अनुसार फैसला ले। जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा चंडीगढ़ पुलिस को नाबालिग लड़की को हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर-16 स्थित आशियाना बाल गृह ले जाने का निर्देश दिया जाता है। जहां उसे तब तक रखा जाएगा, जब तक कि पुलिस अधीक्षक, सिरसा आकर उसे बाल गृह, सिरसा में ले जाकर वयस्क होने तक रखें। वयस्क होने पर वह यह चुनने के लिए स्वतंत्र होगी कि कहां रहना चाहती है।

कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद-21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। संवैधानिक जनादेश के अनुसार प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की

रक्षा करना राज्य का बाध्यकारी कर्तव्य है। हाई कोर्ट 17 वर्षीय लड़की और 19 वर्षीय लड़के द्वारा दायर सुरक्षा याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और वह अपने रिश्तेदारों से खतरा बता रहे थे। दोनों पक्ष एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए उच्च न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र के समक्ष उपस्थित हुए। हालांकि, लड़की ने कहा कि वह माता-पिता के साथ नहीं जाना चाहती। हाई कोर्ट ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना विशेष रूप से रिश्ते की वैधता पर, एसपी सिरसा को याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए मांग पत्र पर विचार करने का निर्देश देता है। यदि रिश्तेदारों से उनको कोई खतरा है, एसपी कानून के अनुसार कार्य करें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान करें।

फर्जी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र मिला तो नहीं कर पाएंगे अमरनाथ यात्रा

रोहित जंडियाल, जागरण ● जम्मू

- इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की होगी आकस्मिक जांच
- अधिकृत डाक्टरों से ही बनाएं प्रमाणपत्र, यात्रा के दौरान मौतों को रोकने की तैयारी

श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान होने वाली मौतों को रोकने के लिए इस बार श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की आकस्मिक जांच की जाएगी। अगर किसी का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र फर्जी मिला तो उसे यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमरनाथ यात्रा में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हमेशा से ही एक अहम मुद्दा रहा है। यात्रा के दौरान होने वाली मौतों के पीछे फर्जी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को बड़ा कारण माना जाता है।

इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और यह 19 अगस्त तक चलेगी। हर बार की तरह इस बार भी यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य है। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बनाने के लिए जिला अस्पतालों से लेकर सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों और कुछ प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तक में व्यवस्था की गई है। इस बार ब्लाक मेडिकल आफिसर को भी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

इसी तरह हर राज्य ने अधिकृत डाक्टरों की सूची भी अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी है। सिर्फ अरुणाचल ने ही अभी तक डाक्टरों की सूची नहीं दी है। कई बार यह भी शिकायतें आती हैं कि श्रद्धालु का स्वास्थ ठीक न होने पर भी प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है। जब श्रद्धालु यात्रा पर आते हैं तो ऊंचाई व कठिन रास्तों में दिक्कत बढ़ जाती है। इससे कइयों की मौत हो जाती है। फर्जी प्रमाणपत्र को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। इसमें तय हुआ कि किन्हीं दो स्थानों पर श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की आकस्मिक जांच की जाए।

तमिलनाडु में दोहरे हत्याकांड मामले में राजस्थान का व्यक्ति गिरफ्तार

चेन्नई, आइएनएस : तमिलनाडु में ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने केरल की दंपती की हत्या से संबंधित मामले में सोमवार को राजस्थान निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। केरल निवासी पति-पत्नी चेन्नई में रह रहे थे। राजस्थान के उदयपुर का निवासी आरोपित 29 वर्षीय महेश चेन्नई में एक हार्डवेयर शाप में सेल्समैन का काम करता था।

केरल के एरुमेली निवासी 68 वर्षीय सिवन नायर और 62 वर्षीय उनकी पत्नी प्रसन्नाकुमारी के शव अवाड में मुतापुतुपेट्टिटल स्थित आवास में रविवार रात मिले। सिवन सिद्धा डाक्टर थे और उनकी पत्नी प्रसन्नाकुमारी केंद्रीय विद्यालय की सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं। उनके संबंधियों ने 800 ग्राम सोना लापता होने की जानकारी दी है। आवास में मिले फोन के आधार पर जांच शुरू की गई और महेश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस हत्याकांड की जांच में जुट गई है। पिछले कुछ दिनों में चेन्नई एवं आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट की कई घटनाएं हो चुकी हैं।

भोजशाला सर्वे पर रोक की मांग निरस्त, आठ सप्ताह का और समय दिया गया

नईदुनिया, इंदौर

- चार जुलाई से पहले पेश करनी होगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वे के लिए हाई कोर्ट ने एएसआइ को आठ सप्ताह का और समय दे दिया है। भोजशाला मामले को लेकर हाई कोर्ट में चार अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को एक साथ सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रस्तुत उस आवेदन को निरस्त कर दिया, जिसमें सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान स्थिति में आवेदन का मतलब नहीं है। कोर्ट ने एएसआइ को निर्देश दिया कि चार जुलाई से पहले सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाए।

बता दें, हाई कोर्ट के 11 मार्च के आदेश के तहत छह सप्ताह यानी 42 दिन के सर्वे में से अब तक 38 दिन का सर्वे रविवार को पूरा हो चुका है। हिंदू पक्ष सर्वे का समय बढ़ाने की मांग कर रहा था।

धार की भोजशाला का भीतरी भाग। नईदुनिया

इसके बाद एएसआइ ने कोर्ट में आवेदन देकर सर्वे के लिए आठ सप्ताह का और समय मांगा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसआइ के वकील हिमांशु जोशी से पूछा कि सर्वे अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ और आपको सर्वे के लिए आठ सप्ताह का समय और क्यों चाहिए ? इस पर जोशी ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार वर्तमान ढांचे को सुरक्षित रखते हुए सर्वे किया जा रहा है। यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। सर्वे में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) इस्तेमाल की जानी है। इसके लिए नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (एनजीआरआइ) से संपर्क किया गया है। जीपीआर मशीन 26 अप्रैल को ही पहुंची है। इसके बाद अब सर्वे आगे बढ़ेगा। कोर्ट ने एएसआइ के आवेदन को स्वीकारते हुए सर्वे पूरा करने के लिए आठ सप्ताह का समय दे दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हम इसके आगे सर्वे के लिए अतिरिक्त समय नहीं देंगे। तीन माह का समय किसी भी सर्वे को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है।

नई जानकारियां सामने आ रहीं : एएसआइ की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सर्वे जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं। सर्वे का लगभग 50 प्रतिशत काम हो चुका है। जीपीआर आने के बाद खोदाई के काम में तेजी आएगी। सोमवार को 39वें दिन भी एएसआइ की टीम ने पश्चिम दिशा में खोदाई कार्य किया। जबकि अन्य दिशा में समतल करने और मिट्टी हटाने का कार्य हुआ।

छत्तीसगढ़ में खड़े ट्रक से पिकअप की टक्कर, नौ लोगों की मौत

नईदुनिया, बेमेतरा : छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में रविवार रात लगभग 11 बजे पिकअप वाहन की सड़क किनारे खड़े रखड़ भरे ट्रक से टक्कर हो गई। इसमें नौ लोगों की मौत गई। जिनमें पांच महिलाएं और तीन बच्चे भी थे। मृतकों में महिला और उसके जुड़वा बच्चों की भी जान चली गई। 23 लोग घायल हो गए। घटना बेमेतरा-सिमगा सीमा क्षेत्र के पास कठिया गांव में पेट्रोल पंप के पास हुई। पिकअप चालक प्रेम साहू ने बताया कि विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक की रोशनी से आंखें बंद हो गई थी। इसीलिए पिकअप की ट्रक से टक्कर हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से मृतकों के स्वजनों को 25 हजार की मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश जिला प्रशासन को दिए।

पुलिस ने बताया कि संतोष साहू का परिवार छठी के निमंत्रण में गया था। सभी पिकअप वाहन से लौट रहे थे कि रास्ते में खड़े ट्रक से टकरा गई।

भाजपा सांसद श्रीनिवास प्रसाद का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

बेंगलुरु, प्रेट्र: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद श्रीनिवास प्रसाद का सोमवार सुबह निधन हो गया। वह बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर पीएम ने शोक जताया और उन्हें सामाजिक न्याय का चैंपियन करार दिया।

श्रीनिवास प्रसाद। फाइल

1974 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार चुनाव लड़ने वाले प्रसाद चामराजनगर से छह बार सांसद व मैसुरु के नंजनगुड से दो बार विधायक रहे। वह 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेई सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। गत 18 मार्च को उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताते हुए एक्स पोस्ट में कहा कि उन्होंने पूरा जीवन गरीबों व बंचितों के लिए समर्पित कर दिया था।

रथ उत्सव

चेन्नई में सोमवार को श्री पार्थसारथी स्वामी मंदिर के रथ उत्सव पर शहर में शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में शामिल पुजारियों के समूह के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेती महिला श्रद्धालु। एएफपी

मनी लांड्रिंग केस में निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड कैडर की निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की मनी लांड्रिंग के मामले में जमानत याचिका सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह एक असाधारण मामला है। जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने निलंबित आइएएस को जमानत देने से इन्कार करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के 17 गवाहों में से ईडी ने 12 से जिरह की है। उम्मीद है कि सुनवाई जल्द पूरी की जाएगी। उसने कहा कि आप जमानत के लिए थोड़ा और इंतजार किजिए। यह कोई सामान्य मामला नहीं बल्कि एक असाधारण मामला है। इस मामले में कुछ तो बहुत गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि मुकदमे की सुनवाई जल्द ही पूरी होगी। बहरहाल, उच्चतम न्यायालय ने सिंघल को मुकदमा लंबा चलने या परिस्थितियों में कोई बदलाव होने पर फिर से जमानत याचिका दायर करने की छूट दे दी।

अरब सागर में नौका से 173 किग्रा ड्रग्स बरामद, दो गिरफ्तार

- एक अन्य अभियान में पाकिस्तानी नौका को पकड़कर जब्त की थी 86 किलोग्राम हेरोइन, 14 तस्करों को किया गिरफ्तार
- तटरक्षक बल ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर पिछले तीन साल में इस तरह के 12 सफल अभियान चलाए

गुजरात एटीएस व भारतीय तटरक्षक बल की कार्रवाई में ड्रग्स बरामद करने के साथ दो लोगों को पकड़ा गया। प्रेट्र

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय तटरक्षक बल ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ दो दिनों तक चले संयुक्त अभियान में रविवार को अरब सागर में एक मछली पकड़ने वाली नाव से 173 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया। रविवार को तटरक्षक बल का यह दूसरा अभियान था।

तटरक्षक बल ने गुजरात एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड (एटीएस) से विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए अपने जहाजों और विमानों को समुद्र में तैनात किया। संदिग्ध नौका की पहचान करने के बाद उसे तुरंत रोका गया। जांच में मछली पकड़ने वाली नाव लगभग 173 किलोग्राम ड्रग्स की तस्करी में शामिल पाई गई। नौका के चालक दल की जांच जारी है। तटरक्षक बल ने कहा कि गुजरात एटीएस के साथ मिलकर पिछले तीन साल में इस तरह के 12 सफल अभियान चलाए हैं।

इससे पहले भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट के नजदीक पाकिस्तानी नौका 'अल रजा' को पकड़कर उससे 86 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और नाव पर सवार सभी 14 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी बरामद ड्रग्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में करीब 600 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

जागरण विशेष

इलेक्ट्रानिक डिवाइस की क्षमता बढ़ा देगा गैलियम ट्रांजिस्टर

मदनमोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नवोन्मेष, ऊंचे तापमान व हाईपावर फ्रीक्वेंसी पर भी कर सकेगा कार्य

डा. राकेश राय ● जागरण

गोरखपुर: इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी फुल चार्ज होने के बाद अब 25 से 50 प्रतिशत अधिक चलेगी। 5जी नेटवर्क से अपेक्षाकृत उच्च गति, डेटा ट्रांसफर और बेहतर नेटवर्क का परिणाम भी प्राप्त हो सकेगा। यह संभव होगा गैलियम आक्साइड मोस्फेट ट्रांजिस्टर से, जिसे तैयार करने में मदनमोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधार्थी डा. नरेंद्र यादव को सफलता मिली है। दुनिया के चार प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल ने इस शोध को प्रकाशित कर डा. नरेंद्र की सफलता पर तो मुहर लगाई ही है। पेटेंट प्रमाणपत्र मिलने से भारत सरकार ने भी मान्यता मिल गई है। डा. नरेंद्र ने बताया कि इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों में वर्तमान समय में सिलिकान ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, लेकिन इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग ऊंचे तापमान या उच्च वोल्टेज वाले इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रानिक डिवाइस में नहीं किया जा सकता। इसलिए कि उच्च तापमान वाले उपकरणों में सिलिकान ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने पर सिलिकान के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। साथ ही लीकेज करंट में वृद्धि होने के कारण बिजली की हानि भी बढ़ सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए ट्रांजिस्टर निर्माण में गैलियम आक्साइड तकनीक के इस्तेमाल की जरूरत पड़ी, जो ऊंचे तापमान, हाईपावर इलेक्ट्रानिक उपकरण और रेडियो-फ्रीक्वेंसी एंप्लीफायर में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

ऐसे काम करता है गैलियम ट्रांजिस्टर : डा. नरेंद्र ने बताया कि गैलियम ट्रांजिस्टर चार टर्मिनल इलेक्ट्रानिक डिवाइस है, जिसमें ग्रेफीन की परत लगाई जाएगी। इससे ताप नियंत्रित होता है और कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ऊर्जा का ह्रास भी पांच प्रतिशत कम होगा। इस ट्रांजिस्टर में पी-टाइप व हल्वो-डोप्ड रीजन का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे इलेक्ट्रानिक डिवाइस का लीकेज नियंत्रित हो जाएगा। इससे ऊर्जा का नुकसान पांच प्रतिशत तक कम हो जाएगा। इसकी वजह से जिस बैटरी में इस ट्रांजिस्टर कर प्रयोग किया जाएगा, उसका जीवन-चक्र बढ़ जाएगा। ऐसे में जिस इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिक डिवाइस में गैलियम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होगा, उसका भी जीवन-चक्र तो बढ़ेगा ही, साथ ही रफ्तार भी अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी।

ट्रांजिस्टर क्षेत्र में क्रांति है यह शोध

प्रो. आरके चौहान

शोध निर्देशक और इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के आचार्य प्रो. आरके चौहान इस शोध को ट्रांजिस्टर क्षेत्र में क्रांति बता रहे हैं। उनका कहना है कि आज जब लोग इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक डिवाइस पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, ऐसे में गैलियम ट्रांजिस्टर की डिजाइन एक इलेक्ट्रानिक क्रांति है। इसका सर्वाधिक फायदा इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करने वाले लोगों को मिलेगा। गैलियम ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल वाली बैटरी के प्रयोग के साथ तैयार की गई इलेक्ट्रिक कार ज्यादा रफ्तार से चलेगी और बैटरी बैकअप भी ज्यादा होगा।

गैलियम ट्रांजिस्टर पर काम करने वाले शोधार्थी डा नरेंद्र यादव ● जागरण

इन अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित है डा. नरेंद्र का शोध

- सालिड स्टेट साइंस एंड टेक्नोलाजी का ईसीएस जर्नल
- सेमीकंडक्टर सिग्नेर जर्नल
- जर्नल आफ कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रानिक्स, स्प्रिंगर जर्नल
- जर्नल आफ सेमीकंडक्टर्स, आइओपी साइंस जर्नल

विश्वविद्यालय के शोध का कई अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित होना और उसे भारतीय पेटेंट प्राप्त होना उपलब्धि है। इससे विश्वविद्यालय के अन्य शोधार्थी भी गुणवत्ता और सामाजिक उपयोगिता वाले शोध के लिए प्रेरित होंगे।

प्रो. जेपी सैनी, कुलपति मदनमोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

मालवणी जहरीली शराब कांड में चार दोषी करार

मुंबई, प्रेट्र: सत्र न्यायालय ने सोमवार को 2015 के मालवणी जहरीली शराब कांड मामले में चार आरोपितों को दोषी करार दिया और 10 अन्य को बरी कर दिया। आरोपितों को आइपीसी और बांबे निषेध अधिनियम के प्रासंगिक प्रविधानों के तहत आपराधिक षड्यंत्र और गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोपों का दोषी पाया। अब न्यायालय छह मई को सजा पर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनेगा। जून 2015 में पश्चिमी उपनगर मलाड के मालवणी में लक्ष्मी नगर झुग्गी बस्ती में जहरीली शराब पीने से 102 लोगों की मौत हो गई थी। आरोपितों को दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। सरकार ने मौतों की जांच के लिए मुख्य सचिव के अधीन जांच का आदेश दिया था।

****

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 30 अप्रैल, 2024

दैनिक जागरण

विचारों के सांचे से ही व्यक्तित्व आकार लेता है

सूरत के बाद इंदौर

कांग्रेस की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आम चुनावों की घोषणा के बाद से शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो, जब किसी कांग्रेस नेता के पार्टी छोड़ने या नाराज होकर घर बैठने अथवा अपने पद से त्यागपत्र देने की खबर न आई हो। इसी सिलसिले के बीच गत दिवस यह खबर आई कि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति ने नामांकन वापसी के अंतिम दिन उम्मीदवारी वापस ले ली और भाजपा नेताओं के साथ हो लिए। इंदौर में तो मतदान होगा, क्योंकि कुछ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन सूरत में इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि वहां कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी होने के चलते उनका नामांकन रद हो गया और इसी के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी वापस लेकर भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ कर दिया। जब नीलेश कुंभानी का नामांकन रद हुआ था, तब कांग्रेस नेताओं ने देश में अघोषित तानाशाही आ जाने का शोर मचाते हुए भाजपा पर तरह-तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन एक हफ्ते बाद उन्हें कुंभानी को पार्टी से निकालना पड़ा, क्योंकि वह नामांकन रद होने के बाद ही लापता हो गए थे। उनके प्रस्तावक भी कांग्रेस के संपर्क से बाहर हो गए थे। कांग्रेस के स्थानीय नेता नीलेश कुंभानी को गद्दार बता रहे, लेकिन वह अब भी खुद को कांग्रेसी कह रहे हैं। इसके विपरीत इंदौर से प्रत्याशी बनाए गए अक्षय कांति भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं।

यह पहली बार नहीं, जब किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लेकर विरोधी उम्मीदवार की राह आसान की हो। 2014 के लोकसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर के कांग्रेस प्रत्याशी मतदान से चंद दिन पहले भाजपा में चले गए थे। इसके पहले 2012 में लोकसभा उपचुनाव में कन्नौज से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव विरोधी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने और नामांकन न दाखिल कर पाने के कारण बिना लड़े चुनाव जीत गई थीं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ हो रहे विधानसभा चुनाव में तो भाजपा के दस प्रत्याशी बिना लड़े चुनाव जीत गए। अतीत में अन्य अनेक नेता चुनौती के अभाव में बिना मतदान हुए लोकसभा या विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन सूरत और इंदौर के मामले कांग्रेस की दयनीय दशा को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि उसके उम्मीदवार मुकाबले से बाहर आ गए। दोनों स्थानों पर कांग्रेस नेता ही यह कह रहे हैं कि उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया। वैसे तो प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के प्रति कुछ न कुछ असहमति और असंतोष रहता ही है, लेकिन यह सामान्य बात नहीं कि कोई नेता प्रत्याशी बनने के बाद चुनाव लड़ने से पीछे हट जाए। अच्छा हो कि कांग्रेस नेतृत्व उन कारणों की तह तक जाए, जिनके चलते ऐसा हो रहा है और उसकी किरकिरी हो रही है।

श्रद्धालुओं की सुविधा

उत्तराखंड में आगामी 10 मई से चार धाम यात्रा आरंभ होने जा रही है। इन दिनों सरकार इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पिछले वर्ष 56 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम पहुंचे थे और इस वर्ष के लिए जिस तेजी से यात्री पंजीकरण करा रहे हैं, उससे इस रिकार्ड के इस बार टूट जाने की पूरी संभावना है। इन धामों के लिए अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग पंजीकरण करा चुके हैं। चारों धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी तरह की कठिनाई न हो और उन्हें अधिक समय तक कतार में नहीं लगना पड़े, इसके लिए सरकार इस बार टोकन व्यवस्था अमल में लाने जा रही है। यदि यह व्यवस्था पूरी तरह धरातल पर उतरती है तो किसी भी श्रद्धालु को एक घंटे से अधिक समय कतार में नहीं लगना पड़ेगा। यद्यपि, इसे अमल में लाने की चुनौती तंत्र के सामने रहेगी। यही नहीं, यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो सुबह सात बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक संचालित किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि एसडीआरएफ यात्रा की अवधि में आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेगी, जो किसी भी आपात स्थिति से निबटने का कार्य करेगी। केदारनाथ धाम के लिए ही पांच स्थानों पर एसडीआरएफ ने पांच पड़ाव चिह्नित किए हैं। प्रत्येक पड़ाव पर दो से तीन दल तैनात रहेंगे, जिनका कार्य एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक चौबीसों घंटे नजर रखना होगा। निश्चित रूप से यात्रा को सुगम, सुरक्षित और निरापद बनाने के लिए ये प्रयास आवश्यक हैं।

चारों धाम में दर्शन के लिए टोकन की व्यवस्था यदि पूरी तरह धरातल पर उतरती है तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा रहेगी

आंकड़ों के अभाव में असंतुलित विमर्श

शिवकांत शर्मा

कई मुद्दे चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में होते हैं, लेकिन प्रामाणिक आंकड़े न होने से उन पर सार्थक बहस नहीं हो पाती

अवधेश राजपूत

भारतीय चुनावों में जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप-प्रत्यारोप आम हैं, परंतु क्या इनकी भूमिका निर्णायक होती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रख्यात अर्थशास्त्री डा. सुरजीत भल्ला का कहना है कि जीवन में सुधार को लेकर लोगों की राय और नेतृत्व पर भरोसे की भूमिका सबसे बड़ी होती है। अपनी पुस्तक 'हाउ वी वोट' में उन्होंने पिछले सात दशकों के आंकड़ों की सहायता से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि युद्ध और आतंक जैसी विपदाओं को छोड़ दें तो मतदाताओं के फैसले का 70 प्रतिशत उसकी इसी धारणा पर निर्भर करता है कि कौनसा नेतृत्व उसके जीवन में सुधार ला सकता है। यह सुधार नागरिक सुविधाओं के बिना संभव नहीं है और ऐसी सुविधाएं आर्थिक विकास के बिना संभव नहीं। डा. भल्ला के आंकड़े दिखाते हैं कि कोविड महामारी की मार के बावजूद पिछले पांच वर्षों में आर्थिक विकास में तेजी के साथ-साथ आर्थिक विषमता का ह्रास भी हुआ है।

अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के निष्कर्ष मुख्यतः आंकड़ों पर आधारित होते हैं। आंकड़ों के बिना उपयोगी नीतियां नहीं बन सकतीं, पर आंकड़ों को लेकर दो समस्याएं हैं। पहली विश्वसनीयता की और दूसरी व्याख्या की। सरकारें आंकड़ों में मिलावट कर सकती हैं या उन्हें गढ़ भी सकती हैं, लिहाजा उनके आंकड़े पूरी तरह भरोसेमंद नहीं। अंतरराष्ट्रीय और गैर-सरकारी संस्थाओं के आंकड़ों के अपने निहितार्थ होते हैं। आंकड़े विश्वसनीय होने पर भी उनकी व्याख्या से परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आंकड़ों की विश्वसनीयता और व्याख्या की इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए बहुत से लोकतांत्रिक देशों ने आर्थिक एवं सामाजिक आंकड़ों को एकत्र करने और उनकी वस्तुनिष्ठ व्याख्या के लिए केंद्रीय बैंकों की तरह की स्वायत्त संस्थाएं बना रखी हैं। ये संस्थाएं सरकार और विपक्ष की बजट और कराधान नीतियों, उनके प्रभावों, अर्थव्यवस्था, कर्ज, बेरोजगारी, महंगाई और विकास दर जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के आंकड़े और उनकी व्याख्या करती हैं और समय-समय पर सरकार और विपक्ष को उनकी नीतियों और उनके संभावित प्रभावों के प्रति सचेत करती हैं।

ब्रिटेन की ऐसी ही स्वायत्त संस्था का नाम ओबीआर या बजट दायित्व कार्यालय है। यह सरकार और विपक्ष की राजस्व नीतियों का विश्लेषण करते हुए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों पर उनके संभावित प्रभाव का पूर्वाकलन करती है। इसकी वजह से राजनीतिक दल उन लोकलुभावन वादों से बचते हैं, जिनके लिए धन जुटाने की कारगर योजना उनके पास न हो। मीडिया और गैर-सरकारी संस्थाएं भी उसके आंकड़ों और आकलन का भरोसे के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसी तटस्थ संस्थाएं यूरोप, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया समेत कुल 37 देशों में हैं, जिन्हें राजस्व निगरानी समिति या परिषद कहा जाता है। अमेरिका में बजट नीतियों की समीक्षा और अनुमोदन चूंकि संसद ही करती है, इसलिए वहां ऐसी अलग संस्था की जरूरत नहीं है। यहां तक कि ईरान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको और चिली में भी राजस्व नीतियों पर निगाह रखने वाली स्वायत्त संस्थाएं हैं, परंतु भारत में नहीं हैं, जहां ऐसी स्वायत्त संस्थाओं की जरूरत केंद्र ही नहीं, हर राज्य में है। स्वायत्तता के लिए इन्हें रिजर्व बैंक का हिस्सा भी बनाया जा सकता है।

भारत में जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक विरोध बढ़ रहा है, उसके चलते संभव है कि स्वायत्त बजट निगरानी संस्था का भी विरोध हो। इसके बावजूद गैर-जिम्मेदाराना लोकलुभावनवाद पर अंकुश लगाने के लिए यह जरूरी है। अन्यथा राजस्व का अधिक भाग आर्थिक विकास को गति देने वाले बुनियादी विकास के उत्पादक कामों पर खर्च होने की जगह सब्सिडी और नकद भत्ते जैसे अनुत्पादक कामों पर खर्च होने लगेगा। ऐसी संस्था होती तो सरकार से पूछ सकती थी कि अगले पांच वर्ष तक तीन चौथाई आबादी को पांच किलो मुफ्त राशन देने का क्या तुक है? इस पर खर्च होने वाले करीब दो लाख करोड़ को उद्योगों के विकास में लगाकर रोजगार क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे या फिर इस पैसे को गरीबी रेखा से नीचे के लोगों में बांटकर गरीबी का उन्मूलन क्यों नहीं किया जा रहा? इसी तरह कांग्रेस से पूछा जा सकता था कि 30 लाख सरकारी नौकरी, हर स्नातक और हर गरीब परिवार की महिला को एक-एक लाख प्रतिवर्ष और एमएसपी की गारंटी जैसे वादों को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ प्रतिवर्ष कहां से आएगा? अगर विरासत कर लगाएंगे तो उसकी दर क्या होगी? मकान और धन-संपत्ति पर ही टैक्स लगेगा या जमीन पर भी? ऐसे टैक्स का रियल एस्टेट कारोबार पर क्या असर हो सकता है व कितना राजस्व मिल सकता है? उससे आर्थिक नुकसान अधिक होगा या कर की आमद? अमेरिका में केंद्र सरकार विरासत कर नहीं, बल्कि संपत्ति कर लेती है। संपत्ति कर सौ करोड़ रुपये से ऊपर की संपत्ति पर लगता है। विरासत कर छह राज्य सरकारें लगाती हैं, जिससे बचने के लिए लोग संपत्ति बेचकर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। ब्रिटेन में सवा तीन करोड़ से ऊपर की संपत्ति पर 40 प्रतिशत की दर से विरासत कर लगता है।

महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भले अपने आप में निर्णायक न हो, लेकिन यह सीधे तौर पर जीवन में सुधार लाने से जुड़ा है, इसलिए हमेशा चर्चा में रहता है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और रुपये की हैसियत को लेकर तमाम आंकड़े उछाले जा रहे हैं। यदि स्वायत्त आंकड़ा संस्था होती तो उसके आंकड़े संतुलित विमर्श का आधार बन सकते थे। मुफ्त राशन लोगों की गरीबी का परिचायक है या एमएसपी की खरीद से सरकार के मत्थे पड़े अनाज के सही उपयोग का? रुपया संप्रग सरकार की तुलना में अधिक गिरा या कम? लोगों का जीवन स्तर सुधरा है या गिरा? कृषि सुधार न होने से किसानों और देश का फायदा हुआ या नुकसान? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो जीवन सुधार की धारणा बनाने में मदद करते हैं और चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रामाणिक आंकड़ों के बिना इन पर सार्थक विमर्श संभव नहीं हो पाता। यूरोप जैसी स्वायत्त संस्था ही इसे संभव बना सकती है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

न्यायपालिका की गरिमा पर आघात

सीवीपी श्रीवास्तव

नेताओं एवं वकीलों को यह समझना होगा कि अदालत का हर फैसला उनके मन मुताबिक नहीं हो सकता

ममता बनर्जी के निशाने पर कलकत्ता हाई कोर्ट। प्रेट्र

हाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से 25 हजार शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति रद करने के फैसले से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गईं। उन्होंने ऐसे बयान दिए कि फैसला पक्षपाती है और कोर्ट बिक गया। उनके इन बयानों को अदालत की अवमानना करार देकर वकीलों ने हाई कोर्ट से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पता नहीं, कोर्ट वकीलों की इस शिकायत का संज्ञान लेता है या नहीं, लेकिन यह पहली बार नहीं, जब किसी ने अदालत के किसी फैसले से असहमत होकर ऐसा कुछ कहा हो कि उसने किसी के इशारे पर या दबाव में फैसला दिया। ऐसे आरोप अनुच्छेद 370, अयोध्या मामले में भी लगाए जा चुके हैं। शायद न्यायपालिका को निशाना बनाए जाने के इसी सिलसिले को देखते हुए बीते दिनों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने 'सोचे-समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक रूप से अपमान के जरिये न्यायपालिका को कमजोर करने के कुछ गुटों' के बढ़ते प्रयासों पर मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा। कुछ समय पहले भी 600 अधिवक्ताओं ने भी इसी विषय पर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। प्रश्न यह है कि क्या सही मायने में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात हो रहा है?

एक सफल और जीवंत लोकतंत्र में फैसलों से असहमति और संस्थाओं की कार्यप्रणाली की आलोचना उसकी सुदृढ़ता बढ़ाती है, लेकिन आलोचना सकारात्मक और पूर्वाग्रह रहित होनी चाहिए। यह राजनीतिक उद्देश्यों से भी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अन्य विशेष रूप से नेता एवं अधिवक्ता न्यायिक निर्णयों की आलोचना करते हैं तो उसका आधार कानून में अंतर्निहित तथ्य होने चाहिए, न कि उनके राजनीतिक विचार। न्यायपालिका के निर्णय वस्तुनिष्ठ और विधि पर आधारित होते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका पर दबाव बनाना सरल नहीं होता। इसके साथ ही, जो विषय आम जनता के बीच चर्चा में होता है, उसमें सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से न्यायिक निर्णय प्रभावित नहीं होता। न्यायपालिका के किसी फैसले से असहमति हो सकती है और उसकी आलोचना भी हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसकी साख पर सवाल उठाए जाएं या फिर उसे बदनाम किया जाए। यह दुखद है कि कई बार जाने-माने अधिवक्ताओं द्वारा भी अदालत के फैसलों पर असहमति जताते समय राजनीतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह खराब चलन बढ़ रहा है। इसमें नेता भी शामिल हो रहे हैं। अदालत के फैसलों की आलोचना लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन वह सकारात्मक और भाषाई दृष्टि से विधिसम्मत होनी चाहिए। आलोचकों और विशेषकर नेताओं एवं अधिवक्ताओं को यह समझना होगा कि आलोचना को राजनीतिक स्वर देने से न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित होती है। उन्हें यह समझना होगा कि अदालत का हर फैसला उनके मन मुताबिक नहीं हो सकता।

संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए शक्तियों के पृथक्कीकरण के सिद्धांत को आधार बनाया था। संविधान के अनुच्छेद-50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच ऐसे पृथक्कीकरण का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि विधायिका और न्यायपालिका के बीच ऐसा पृथक्कीकरण अनुच्छेद 121 और 122 में अंतर्निहित है, जिनमें क्रमशः यह कहा गया है कि संसद में न्यायाधीश के आचरण पर सामान्य परिस्थितियों में चर्चा नहीं की जाएगी और संसदीय कार्यवाही में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि स्वतंत्र न्यायपालिका के निरंकुश हो जाने की आशंका भी होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में ही रखी हैं, ताकि न्यायपालिका पर संवैधानिक नियंत्रण बना रहे। इस संबंध ने उच्चतम न्यायालय ने एल. चंद्रकुमार बनाम भारत संघ 1997 मामले में स्वयं यह कहा था कि न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित हैं, लेकिन शक्ति पृथक्कीकरण के सिद्धांत के प्रचलन के कारण भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है।

अक्सर यह देखा गया है कि न्यायपालिका सरकार की नीतियों के संवैधानिक न होने पर उन्हें निरस्त करने से पीछे नहीं हटती। इसका हाल का सबसे बड़ा उदाहरण चुनावी बांड पर दिया गया निर्णय है। इसी प्रकार हाल में एमके रणजीत सिंह बनाम भारत संघ 2024 मामले में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार को एक मूल अधिकार बनाकर और उसे अनुच्छेद-14 और अनुच्छेद-21 (क्रमशः समानता और जीवन का अधिकार) से जोड़कर राज्य को पर्यावरण के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए निर्देश दिया गया। न्यायपालिका का उद्देश्य राज्य-नागरिक संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखना है। संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करने के कारण न्यायपालिका को किसी भी बाह्य दबाव से उन्मुक्ति है। यह संभव नहीं कि कोई न्यायाधीश या खंडपीठ व्यक्तिगत विचार के आधार पर निर्णय दे, क्योंकि इससे विधि के शासन और संविधान की सर्वोच्चता, दोनों ही सिद्धांत बाधित होते हैं। जहां राज्य के अधिकारों और प्राधिकार के संरक्षण की आवश्यकता है, वहीं नागरिकों के अधिकारों को सीमित करने में न्यायपालिका पीछे नहीं हटती। किसी भी निर्णय की आलोचना करने के पहले उस मामले के तथ्यों और संबंधित विधियों पर विचार किया जाना चाहिए। यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता कि न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव है। यह ठीक नहीं कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने ऐसे आरोप लगाए कि न्यायाधीश सत्तारूढ़ दल के दबाव में हैं। आलोचना का अर्थ यह नहीं कि हम मर्यादा की सीमा लांघ दें और स्वतंत्र संस्थाओं की गरिमा पर आघात करें।

(लेखक सेंटर फार अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस के अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

गुरु कृपा और साधना

चूंकि गुरु प्रत्यक्ष हैं, इसलिए साधक उन्हें मनुष्य मानकर, उनके वचनों को वाक्य मानकर और उनकी कृपा को स्वभाव मानकर प्रायः अवज्ञा भी कर देता है। जबकि सबसे कठिन साधना और सबसे सरल साधन यही है कि जो प्रत्यक्ष उपलब्ध है उसी में अप्रत्यक्ष, निर्गुण तत्व को शिरोधार्य किया जाए। इससे ज्ञान और भक्ति की एकरूपता अनायास ही सिद्ध हो जाती है। गुरु का स्मरण करके एकाग्र हुआ जा सकता है। वाणी की साधना गुरु की स्तुति करके करनी चाहिए। गुरु को नमन करके विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। उनके गुणों को गीत बनाकर उन्हीं के गुणों का गायन करने से ब्रह्म रूप अगुण और भगवान रूप सगुण की साधना में दिव्यता आ जाती है।

जलेबी में मिठास और शक्कर अलग-अलग नहीं होते। मिठास शक्कर को ही सिद्ध करती है। उसी तरह गुरु में अगुण एवं सगुण दोनों परिव्याप्त होता है। हम अपनी मान्यताओं और अपेक्षाओं के वशीभूत होने के कारण गुरु के सगुण स्वरूप में भेद रहित व्यावहारिक रूप में दिखाई देने वाली भिन्नता में भेदभाव मानकर गुरु से ही विभक्त हो जाते हैं, लिहाजा न तो हम सगुणोपासना कर पाते हैं और न ही निर्गुण की उपासना कर पाते हैं।

साधक के अंतःकरण में किसी वस्तु को कठिनाई और पुरुषार्थ से प्राप्त करने पर उसका अहंकार ही तुष्ट होता है कि मैंने कितनी मेहनत और अपने बल पर यह उपलब्धि प्राप्त की है। इसी कारण वह सहजता एवं सरलता से उपलब्धि को तात्विक नहीं मान पाता। साधक ऐसी स्थिति में प्रलोभनों में पड़कर सांसारिक वस्तुओं को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानकर भटक जाता है। जबकि साधना उस ईश्वर के लिए ही की जाती है कि जो हमें प्राप्त तो है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। भक्ति का फल भक्ति है, ज्ञान का फल ज्ञान है और दोनों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम कर्म या साधना है। यही गुरु कृपा है।

स्वामी मैथिलीशरण

विश्व में भुखमरी का बढ़ता संकट

देवेंद्रराज सुथार

अनेक कारणों से वैश्विक खाद्य संकट बढ़ रहा है, जिसका समुचित समाधान आवश्यक है

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 'ग्लोबल रिपोर्ट आन फूड क्राइसिस' ने एक बार फिर भूख की वैश्विक भयावहता को उजागर किया है। वर्ष 2023 में 59 देशों के करीब 28.2 करोड़ लोग भूख से दुष्प्रभावित हुए हैं, जबकि 2022 में 2.4 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सामग्री की भारी कमी से जूझना पड़ा है। भूख की विभीषिका एक गहरा मानवीय संकट है जो लाखों लोगों के जीवन को दुष्प्रभावित करता है, उनकी गरिमा एवं स्वास्थ्य को छीन लेता है। इससे सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में बाधा पहुंच रही है।

वैश्विक खाद्य संकट के मूल कारणों में संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और असमानता आदि हैं। सशस्त्र संघर्ष कृषि गतिविधियों को बाधित करते हैं, समुदायों को विस्थापित करते हैं और खाद्य सहायता तक मानवीय पहुंच में बाधा डालते हैं, जिससे संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन अपने अनियमित मौसम पैटर्न और चरम घटनाओं के साथ खाद्य उत्पादन के लिए खतरा पैदा करता है, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं।

आर्थिक अस्थिरता और असमानता ने समस्या को बढ़ा दिया है, क्योंकि हाशिये पर रहने वाले समुदाय पौष्टिक भोजन एवं आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोविड महामारी ने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया, जिससे दुनिया में खाद्य असुरक्षा बढ़ गई है। वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए जरूरतमंद लोगों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय सहायता को बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें खाद्य वितरण कार्यक्रम, पोषण संबंधी सहायता, स्वच्छ पानी एवं स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच शामिल है। सामाजिक संगठनों को संघर्ष प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में कमजोर आबादी तक पहुंचने के लिए संसाधन जुटाने होंगे। साथ ही, खाद्य असुरक्षा के मूल कारणों को दूर करने के लिए लचीलापन बनाने और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें कृषि विकास में निवेश करना, जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुदृढ़ीकरण पर जोर देना शामिल है।

इसके अलावा वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के प्रयासों को समावेशिता और स्थिरता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। महिलाओं, बच्चों और हाशिये पर रहने वाले समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने व संसाधनों एवं अवसरों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। छोटे किसानों, ग्रामीण समुदायों एवं खाद्य-असुरक्षित आबादी की जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार और मानवीय प्रयासों के साथ हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, जहां कोई भी भूखा नहीं रहे व सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

लोकतंत्र में बढ़ती महिलाओं की भूमिका

'निर्णायक भूमिका में महिला मतदाता' शीर्षक से लिखे आलेख में डा. ऋतु सारस्वत ने महिलाओं की निर्णायक भूमिका का विश्लेषण करते हुए बताया कि कैसे भारतीय महिलाएं अब लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बना रही हैं। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं और अपनी जरूरतों के अनुसार वोट दे रही हैं। महिलाओं के बीच आत्म-सशक्तीकरण के बढ़ते हुए स्तर ने उन्हें लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की गुंजाइश दी है। मेरे विचार में, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनकी स्वायत्तता भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। महिलाओं को अपने मन की आवाज सुनने और अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और भी मजबूत करेगा और समाज में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देगा। सरकारों को महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण करना चाहिए। इस तरह से महिलाओं की भागीदारी और उनके आत्म-सशक्तीकरण का दायरा और बढ़ेगा। साथ ही, सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें अपने मत का महत्व समझाना भी आवश्यक है।

अमरजीत कुमार, चिरैला-औरंगाबाद (बिहार)

कांग्रेस के हवाई वादे

वर्ष 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा एवं वादों का जिम्मा प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपा था। इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से सबसे आगे राहुल गांधी हैं। करोड़ों लोगों के खातों में हर वर्ष एक लाख रुपये देने का वादा करने वाली कांग्रेस मतदाताओं का विश्वास जीत पाएगी? गरीब महिलाओं के खाते में एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने का वादा सुनने के बाद मतदाता चौक-चौराहों पर तरह-तरह की बातें बनाते सुनाई दे रहे हैं। किसानों के कर्ज माफ करने का चुनावी वादा राजस्थान में निभा पाने में असमर्थ कांग्रेस दूसरा बड़ा दांव खेल कर मतदाताओं को रिझाने निकली है। कांग्रेस कथनी और करनी समान रखने में समर्थ होगी तभी मतदाता वोट देंगे। तुष्टीकरण की नीति में उलझी कांग्रेस असंभव को संभव करते हुए दिखाना चाहती है। आय का बड़ा बजट महिलाओं को आवंटित करने का भ्रम पाल रही कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। वहीं भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार ने बीड़ा उठाया है। उसको पूरा करने के लिए सरकार का हाथ मजबूत करने के लिए महिला सशक्तीकरण और युवाओं का योगदान सराहनीय रहेगा। बढ़ते कदमताल को और आगे बढ़ाने के लिए युवा मतदाता जागरूक होता दिखाई दे रहा है। देश मजबूत बन चुका है। देश में अलगाववादी ताकतें शांत हो चुकी हैं। हर मतदाता सुकून की जिंदगी जीना चाहता है। मजबूत सरकार को छोड़कर पुरानी सरकार का दामन थामने में किसको दिलचस्पी होगी? कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र और दावे हर बार खोखले ही साबित हुए हैं।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

मेलबाक्स

महिला मतदाता

निर्णायक भूमिका में महिला मतदाता- शीर्षक लेख के तहत ऋतु सारस्वत ने इस विचार को नकारा कि हमारे देश की महिलाएं परिवार के पुरुष सदस्यों के सोच के अनुसार मतदान करती हैं। बिल्कुल यह सही हो सकता है कि हमारे देश में महिलाओं का भी मतदान करते समय सोच बदला हो और वे अपनी इच्छानुसार अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मत देती होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि गांवों की महिलाएं अभी भी शायद ऐसा नहीं करती होंगी, क्योंकि वहां मतदान के प्रति जागरुकता का अभाव है। महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए और इसके लिए गांवों में विशेष रूप से काम करना चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि वे जागरूक बनें अपने कीमती मत का प्रयोग करें। महिलाओं को भी यह याद रखना होगा कि किसी गलत उम्मीदवार को दिया गया मत उन्हें पछतावा ही देगा और हमारी भावी पीढ़ी के कैरियर को भी बर्बाद करेगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

25,753 लोगों की नियुक्ति की गई थी बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा वर्ष 2016 में, जिसे हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा रद कर दिया गया है।

डा. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु तथा वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

आजकल

सब्सिडी के वितरण से जुड़ी विसंगतियां

लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच राजनीतिक दलों की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिए गए हैं। अधिकांश दलों ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का जीवन स्तर उन्नत करने की दिशा में कार्य किए जाने के वादे किए हैं। ऐसे में मतदाताओं को यह भी समझना होगा कि मुफ्त योजनाओं एवं सब्सिडी के बढ़ते दायरे की कीमत दीर्घकाल में उन्हें ही चुकानी होगी, लिहाजा अल्पकालिक लाभ की प्रवृत्ति का त्याग करते हुए दीर्घकालिक विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने को समर्थन प्रदान करें

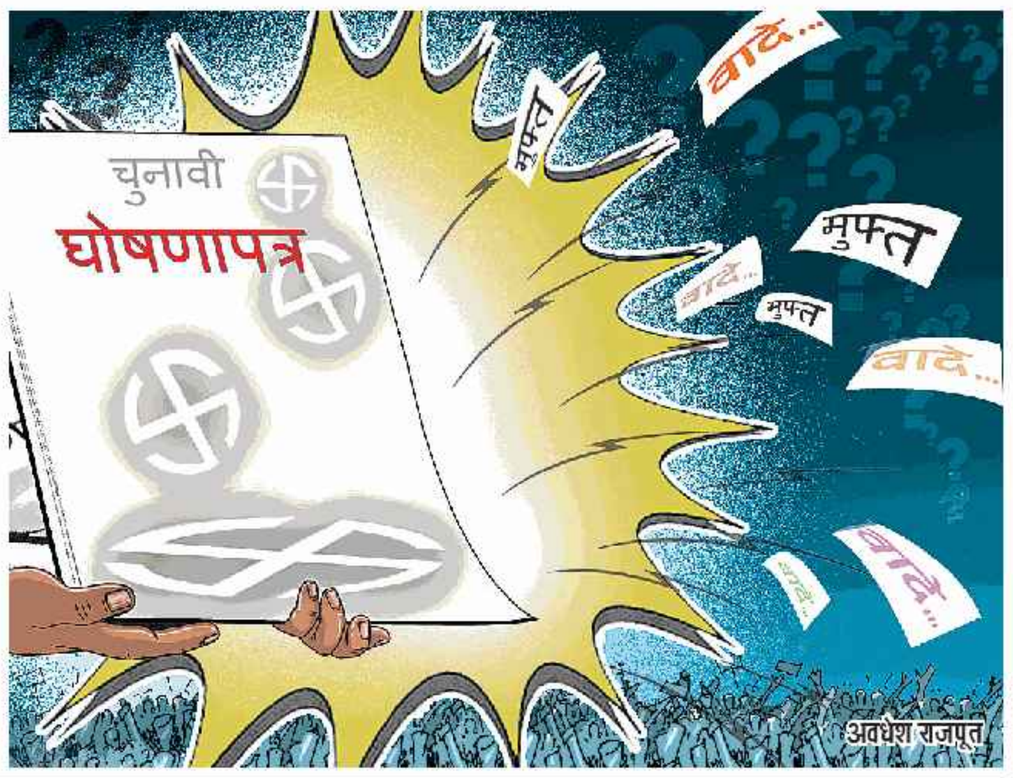

आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकारें निरंतर प्रयासरत रहती हैं। निचले पायदान पर जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए सरकारों द्वारा कुछ अधिक ही प्रयास किए जाते हैं। परंतु सरकारी नीतियों की जटिलताओं के कारण कई बार इच्छित एवं जरूरतमंद लाभार्थी इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। रियायती बिजली और पानी की कहानी पर विचार करें तो मूल रूप से इसे दिए जाने का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद उपलब्ध कराना था, परंतु अनजाने में यह समृद्ध लोगों के लिए कहीं अधिक लाभकारी साबित हो रहा है। इसी प्रकार से कृषि ऋण माफी की गाथा विशेष रूप से संपन्न किसानों के लिए एक वरदान के रूप में सामने आती है, जबकि हाशिये पर रहने वाले लोग आज भी ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं। यह एक विरोधाभासी वास्तविकता है। वस्तुतः वंचितों के उत्थान के लिए बनाई गई सब्सिडी अनजाने में अभिजात वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है।

कार्यक्रमों की विफलता : देखा जाए तो गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से कई सरकारी कार्यक्रम अपना लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे हैं। गरीबों के लिए निर्धारित सब्सिडी अक्सर अमीरों के लिए अप्रत्याशित लाभ का काम करती है, लिहाजा दिखावटी रूप से परोपकारी नीतियां अप्रत्याशित परिणामों में बदल सकती है। ऐसे में वर्तमान में जारी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के वितरण प्रारूप में आमूल-चूल बदलाव की आवश्यकता है, जो केवल आर्थिक मदद देने से लेकर सामाजिक उन्नति के लिए व्यापक अवसरों को बढ़ावा देने तक केंद्रित हो। इसी क्रम में वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं को देखा जा सकता है, जिसके तहत लाभार्थियों के दायरे में एक बड़ा ऐसा संपन्न वर्ग भी शामिल है, जिसे वह सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे में गैर-योग्यता वाली सब्सिडी और क्षणिक मुफ्त सुविधाओं पर संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय सरकारों को प्रगति की आधारशिला को मजबूत करने के लिए अपने राजकोष का उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में संसाधनों को लगाने के लिए इससे प्रेरणा मिलती है। इससे नागरिक सुविधाओं के लिए विविध प्रकार की संपदाओं का निर्माण संभव होता है। संपदा के निर्माण से अर्थव्यवस्था को तेजी मिलती है, जिसके फलस्वरूप विकास की गति तीव्र होती है। ऐसा होने से आजीविका को मजबूती मिलती है और स्वाभाविक रूप से नौकरियों के अवसर बढ़ते हैं। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश व्यापक परिवर्तन के लिए एक घटक के रूप में काम करते हैं। इससे हमारी अनेक प्रकार की छिपी हुई संपदाएं सामने आती हैं या फिर यह कहा जा सकता है कि अनेक छिपी संपदाओं को अनलाक करने में हम सक्षम हो पाते हैं, परिणामस्वरूप टिकाऊ और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

व्यवसाय अनुरूप वातावरण : हम सभी यह जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय को पनपने और विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण यानी माहौल की आवश्यकता होती है। इस कार्य में सरकार की बड़ी भूमिका होती है। सरकारें व्यवसायों के लिए सहायक माहौल तैयार करके एवं समुचित निवेश करके व समावेशिता को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती हैं। इसका मतलब नियमों को सुव्यवस्थित करना, लालफीताशाही को कम करना और स्पष्ट एवं पूर्वानुमानित नियम स्थापित करना है। ये उपाय विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के लिए फायदेमंद हैं, जो कई अर्थव्यवस्थाओं की जीवनरेखा हैं। वे उद्यमियों को नवाचार करने, निवेश करने और नौकरियां पैदा करने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसके अलावा, सरकारें व्यक्तियों को आज के गतिशील नौकरी बाजार में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल से सज्जित करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश कर सकती हैं। यह एक ऐसा कार्यबल सुनिश्चित करता है जो तकनीकी प्रगति को अपना सकता है एवं अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान दे सकता है। ऐसे में सभी के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराए जाने जैसी स्थितियां प्रदान करने से जहां हर किसी को अपनी ओर से इसमें योगदान करने का अवसर मिल सकता है, वहीं सरकारें अधिक नवीन और गतिशील व्यापार परिदृश्य को बढ़ावा दे सकती हैं, जिससे अंततः आर्थिक विस्तार को बढ़ावा मिल सकता है।

स्थायी आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन : रणनीतिक निवेश और तकनीकी प्रगति को अपनाना आर्थिक विकास के आगे के इंजन के रूप में कार्य करता है। सरकारें प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण संभावनाओं वाले उच्च विकास वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकती हैं और उनके विकास में रणनीतिक रूप से निवेश कर सकती हैं। ये क्षेत्र उत्पादकता लाभ को अनलाक करने और लंबे समय में स्थायी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट आफ थिंग्स जैसी तकनीकों को अपनाने से उद्योगों में क्रांति आ सकती है, पूरी तरह से नए अवसर पैदा हो सकते हैं और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।

वास्तव में समावेशी विकास हासिल करने के लिए सभी क्षेत्रों में सहयोग महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी सरकारों, व्यवसायों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज को एक साथ लाती है। ये साझेदारियां संसाधनों का लाभ उठाती हैं, विशेषज्ञता साझा करती हैं और जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटती हैं जो आर्थिक प्रगति में बाधा बन सकती हैं। इसमें अधारभूत ढांचे के विकास परियोजनाओं पर सहयोग करना अथवा सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए काम करना शामिल हो सकता है। योग्यता आधारित नीतियों को प्राथमिकता देने से यह सुनिश्चित होता है कि अवसर कौशल व क्षमताओं के आधार पर आवंटित किए जाते हैं, विशेषाधिकार के आधार पर नहीं।

सामाजिक हितों का ध्यान : आजकल मतदाताओं में राजनीतिक उत्साह चरम पर है। निश्चित रूप से चुनाव प्रचार के तमाशे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर ऐसे दौर में जहां मुफ्त और सब्सिडी के वादे प्रचुर मात्रा में हो रहे हैं। अनेक राजनीतिक दल अल्पकालिक उपहारों से मतदाताओं को लुभाकर वोट पाने की होड़ में रहते हैं, लेकिन चिंताजनक यह है कि अक्सर यह दीर्घकालिक टिकाऊ विकास की कीमत पर होता है। अधिकांश राजनीतिक दलों के घोषणापत्र ऐसी प्रतिज्ञाओं से भरे होते हैं, जो कहीं से भी व्यावहारिक प्रतीत नहीं होते हैं। इससे अल्पकालिकवाद की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जिससे व्यापक सामाजिक हित कमजोर होते हैं। ऐसे में यह मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे अल्पकालिक लोकलुभावनवाद के झांसे को खारिज करें और समाज के दीर्घकालिक कल्याण को प्राथमिकता देने वाले विकल्प को चुनें। अपने मताधिकार का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करके मतदाता शासन को एक ऐसे पथ की ओर ले जा सकते हैं जो मुफ्त और सब्सिडी के क्षणिक आकर्षण से परे हो।

समृद्धि की कुंजी है आर्थिक विकास

हमारे देश की बढ़ती युवा जनसंख्या और अनगिनत प्रतिभाओं के साथ हमारे देश की जनसांख्यिकीय संरचना भविष्य के लिए अपार संभावनाएं रखती है। हालांकि यह क्षमता तब तक अप्रयुक्त रहती है, जब तक मजबूत आर्थिक विकास के साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा न हों। यह केवल जनसांख्यिकीय लाभ का मामला नहीं है, यह निरंतर आर्थिक विस्तार के माध्यम से इस जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के बारे में है।

उल्लेखनीय है कि आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्पष्ट है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था फलती-फूलती है, वैसे-वैसे यह विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पैदा करती है, व्यक्तियों और परिवारों को गरीबी से बाहर निकालती है। इसके अलावा, एक उत्साही अर्थव्यवस्था नवाचार, उद्यमशीलता और निवेश को बढ़ावा देती है, जिससे समृद्धि का एक अच्छा चक्र बनता है जो समाज के हर वर्ग में व्याप्त है। आर्थिक विकास केवल भौतिक समृद्धि के बारे में नहीं है, यह मानव विकास की व्यापक धारणा को भी रेखांकित करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच एक मजबूत अर्थव्यवस्था पर निर्भर है जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को स्थायी रूप से वित्त पोषित कर सकती है। इस संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता और कल्याण को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

हालांकि आर्थिक विकास को समावेशिता एवं स्थिरता के विचारों से भी संयमित किया जाना चाहिए। समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ समान रूप से वितरित हों, जिससे समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। इसमें हाशिए पर विद्यमान समुदायों को सशक्त बनाना, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना शामिल है। इसी प्रकार, पर्यावरण की सुरक्षा और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित करने के लिए सतत विकास आवश्यक है। अल्पकालिक लाभ पर अदूरदर्शी ध्यान पारिस्थितिक क्षरण का कारण बन सकता है और दीर्घकालिक समृद्धि की नींव को कमजोर कर सकता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जबकि जीडीपी द्वारा मापी गई आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच्ची सामाजिक प्रगति तब हासिल होती है, जब हम एक स्वस्थ, खुशहाल और न्यायसंगत समाज का निर्माण करते हैं। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, न कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को। (डा. विकास सिंह)

खरी-खरी

कार में लंच

पूरन सरमा

मुझे यह तो पता चल गया था कि यह अफसर रिश्वत धड़ल्ले से खाता है, यह भी पता चला था कि वह रिश्वत कार में खाता है। दफ्तर या घर में वह रिश्वत को हाथ भी नहीं लगाता। परंतु मेरे सामने कठिनाई यह थी कि अफसर को कार में कैसे बिठाऊं? पर भगवान बड़ा दयालु है। यह समस्या भी हल हो गई। कार स्वयं अफसर के पास थी। उसके एक मातहत कर्मचारी ने साहब के लंच पर जाने के बहाने मुझे उसकी कार में पीछे बैठा दिया। कार चल पड़ी, अफसर बोला, 'चुपचाप माल सीट के नीचे रख दो।'

मैंने बैग खोलकर सौ के नोटों की दस गड्डियां ठिकाने लगा दीं। कार किसी भी जगह लंच करने नहीं रुकी। मुझे एक जगह उतार दिया और अफसर आगे बढ़ गया। इस घटना के एक माह बाद मैं हैरान रह गया। मुझे उस आफिस में पांच लाख रुपये की सप्लाई का ठेका डाक से मिल गया। जुआ में लगाया पैसा फलीभूत हो गया। खुशी के मारे मैं उछल पड़ा। भाग कर उसी अफसर के पास पहुंचा तो उसने आंखें निकालीं। मैं बोला, 'लंच टाइम हो गया, चलिये टंच हो लें।'

अफसर ने दफा हो जाने को कहा, तो मैंने कहा, 'मैं बैग खाली करना चाहता हूं।' अफसर बोला, 'रिश्वत केवल मार्च में ही खाता हूं।'

मैं अफसर की ईमानदारी पर गदगद हो गया, बोला, 'प्रभु, अवधि बढ़ाइए, इस एक माह की जगह दो माह कर दीजिए।'

'भला चाहते हो तो निकल जाओ यहां से, वरना जो आदेश मिला है उसमें भी व्यवधान खड़े कर दूंगा।' अफसर ने कहा और मैं लौट आया।

एक दिन उसी दफ्तर का वही मातहत कर्मचारी आया और बोला, 'मेरा भी तो ख्याल करिये। मैंने आपका लेटर बनाकर साहब के हस्ताक्षर करवाए हैं।'

मैं बोला, 'ये लो सौ रुपये का नोट, पर एक बात बताओ कि साहब रिश्वत कार में ही क्यों खाते हैं?'

कर्मचारी बोला, 'अब क्या बताऊं। दफ्तर में ईमानदार कहलाते हैं हमारे अफसर। घर में पूजा-पाठ करते हैं और सारी कृपा ईश्वर की मानते हैं। कार में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का भी खतरा नहीं रहता।'

मैं यह सब सुनकर अफसर की ईमानदारी पर दंग रह गया।

पोस्ट

आम आदमी पार्टी से अनैतिक गठबंधन के खिलाफ अरविंदर सिंह लवली का फैसला स्वागतयोग्य है। जब अन्य सभी चुप रहे, तब उन्होंने साहस दिखाया।
डा. मुनीश कुमार रायजादा@DrMunishRaizada

अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। चुनाव के बीच पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से इतनी परेशानी थी, तो इतने समय चुप क्यों रहे? मानक गुप्ता@manakgupta

पिछले कुछ वर्षों से यह विमर्श चलाया जा रहा है कि अमुक समुदाय तो अनुसूचित जातियों से भी पिछड़ा है। ऐसा विमर्श चलाने वाले घोर जातिवाद से पीड़ित हैं। उनकी नजर में अनुसूचित जातियों को समाज के निचले पायदान पर ही रहना चाहिए।
अरविंद कुमार@arvind_kumar_

गुजरात की सूरत और मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट भाजपा की पारंपरिक रूप से सुरक्षित सीटों में गिनी जाती हैं। ऐसी सीटों पर मुकाबला खत्म करने के पीछे भाजपा का सोच क्या है, यह समझ नहीं आ रहा। यह अच्छा संदेश तो नहीं ही दे रहा।
अरविंद चोटिया@arvindchotia

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन को लेकर असहजता दर्शाता है?

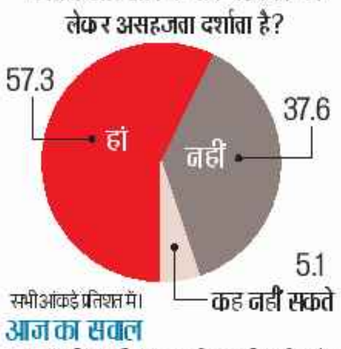

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या अरविंदर सिंह लवली का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा राजधानी में कांग्रेस की चुनावी संभावनाएं खराब करेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

है करना अपराध क्यों उद्यम अरु व्यापार,
जो उद्यम का रिस्क ले हो उस पर ही वार।
हो उस पर ही वार उसी को चोर बताएं,
भले उसी से मांग पार्टी खर्च चलाएं।
राजनीति के खेल उद्यमी को है डरना,
आरोपों के बीच उसे बिजनेस है करना।
- ओमप्रकाश तिवारी

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

चुनाव के बीच डबल 'एस' का झंझावात

लोकसभा चुनाव के दो चरण समाप्त हो चुके हैं। बंगाल की 42 में से छह लोकसभा सीटों पर मतदाता अपने निर्णय को ईवीएम में कैद कर चुके हैं। चुनावी जंग के बीच बंगाल में पहले से ही मुद्दों में शुमार रहे डबल 'एस' को लेकर हुई दो कार्रवाई ने इसे झंझावात का रूप दे दिया है। इससे किस-किस की राजनीतिक जड़ें हिलेंगी और उखड़ेंगी, इसका पता तो चार जून को चलेगा। परंतु बंगाल में यह डबल 'एस' अब लोकसभा चुनाव का सबसे ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। इसमें पहला 'एस' स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा 2016 में की गई 25,753 लोगों की नियुक्तियों को कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा रद किया जाना है और दूसरा 'एस' संदेशखाली है, जहां बीते शुक्रवार को दूसरे चरण के मतदान के दिन ही तृणमूल कांग्रेस के पूर्व बाहुबली नेता शाहजहां शेख के करीबी के ठिकानों से भारी मात्रा में विदेश हथियार, गोली और बम-बारूद मिले हैं। सीबीआइ को इन असलहों व बम-बारूद की बरामदगी में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) की मदद लेनी पड़ी। ये दोनों ही घटनाएं सबकी जुबां पर हैं।

एसएससी भर्ती घोटाले व 25,753 लोगों की नौकरियां जाने एवं संदेशखाली के मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक अपनी चुनावी सभाओं में उठा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर इन मुद्दों पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर उनके भतीजे व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भाजपा पर हमलावर हैं और इतनी अधिक संख्या में लोगों की नौकरियां जाने के लिए भाजपा को दोषी बताते हुए कोस रहे हैं। उधर, माकपा-कांग्रेस के नेता तृणमूल और भाजपा, दोनों पर निशाना साध रहे हैं।

संदेशखाली से बरामद हथियार। फाइल

सभी दलों के नेता इन मुद्दों को अपने-अपने हिसाब से भुना रहे हैं। सभी दलों के नेता इन मुद्दों की 'राजनीतिक फसल' अपने-अपने हिसाब से काटने को आतुर हैं। भाजपा नेता अगर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं तो माकपा-कांग्रेस के नेता उसके विपरीत बयान दे रहे हैं, वहीं तृणमूल नेता दावा कर रहे हैं कि विपक्ष जितना भी जोर लगाए, जनता की राय उनके पक्ष में होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि शिक्षा विभाग के भर्ती मामले में राज्य सरकार ने योग्य लोगों की नौकरी बचाए रखने में भूमिका निभा रही है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ संदेशखाली से हथियार बरामद होने के मामले में भी ममता यह मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं कि वहां हथियार सीबीआइ वालों ने ही रखा था।

भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा का सीधे तौर पर कहना है कि नियुक्तियां रद होने का एकमात्र कारण भ्रष्टाचार है। तृणमूल ने भ्रष्टाचार को 'संस्थागत रूप' दे दिया है। इसके बाद माकपा-कांग्रेस ने कहा कि भाजपा को इस पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि सुवेंदु अधिकारी, जो अब इस मुद्दे में विरोध का पुरोधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस घोटाले के दौरान राज्य के मंत्री और तृणमूल के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। माकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने कहा, 'हमारा बयान बिल्कुल स्पष्ट है। पहला, भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरा, योग्य लोगों को बहाल किया जाए। भाजपा को इस पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस समय तृणमूल ने यह भ्रष्टाचार किया था, उस समय तृणमूल की जर्सी पहनने वाले कुछ नेता थे, जो अब भाजपा की जर्सी पहनकर भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं।'

चिटफंड से लेकर नारद स्टिंग, भर्ती व राशन घोटाला बंगाल में तृणमूल के शासनकाल में हुए। भ्रष्टाचार के इन मामलों की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक आखिरी छोर तक नहीं पहुंच सकी है। कभी इसकी गति तेज हो जाती है तो कभी रुक जाती है। एक तरफ जहां माकपा-कांग्रेस तृणमूल और भाजपा को समान रूप से दोषी बता रही है। वहीं भाजपा तृणमूल और माकपा-कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए आलोचना कर रही है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने कहा, 'भ्रष्टाचार और नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी की माकपा से मिली विरासत को तृणमूल आगे बढ़ा रही है।'

भाजपा का कहना है कि वर्तमान में मंत्री उदयन गुहा एक समय फारवर्ड ब्लाक के नेता थे। उनके पिता वामपंथी सरकार में मंत्री थे। उन्होंने दावा किया है कि उनके पिता ने भी कई लोगों को नौकरियां दी थीं।

राजारहाट के पूर्व माकपा नेता और वर्तमान में तृणमूल विधायक तापस चटर्जी ने भी वाम शासन में नियुक्तियों में अनियमितता की बात कही थी। इससे स्पष्ट है कि तृणमूल किसकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। जिस दिन फैसला सुनाया गया, उस दिन कई तृणमूल नेताओं ने आपसी चर्चा में आशंका व्यक्त की थी कि हाई कोर्ट का फैसला चुनाव को प्रभावित करेगा। एक वरिष्ठ प्रत्याशी ने तो यहां तक कह दिया कि वे जेल जाकर पार्थ चटर्जी को थप्पड़ मारना चाहते हैं। इससे साफ हो जाता है कि हालात क्या हैं। संदेशखाली से विदेशी हथियारों की बरामदगी ऐसा मुद्दा बन गया है कि आने वाले समय में बड़ा गुल खिला सकता है।

मंथन

पीएचडी से संबंधित बदलाव

यूजीसी द्वारा इस वर्ष से नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। पीएचडी में नामांकन के लिए भी यह एक आवश्यक पात्रता होती है। ऐसे में इस परिवर्तन को समझा जाना चाहिए

सुधीर कुमार
सीनियर रिसर्च फेलो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जून-2024 की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना ऐसे समय में जारी की गई है, जब चंद दिनों पूर्व यूजीसी ने नेट परीक्षा से जुड़े कई अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य उच्च शिक्षा की स्थिति और शोध गुणवत्ता में सुधार लाना है। एनटीए द्वारा नेट की परीक्षा वर्ष में दो बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का महत्व इस रूप में है कि देश के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए न्यूनतम पात्रता नेट की परीक्षा में उत्तीर्ण होना रखा गया है। पीएचडी में नामांकन के लिए भी यह एक जरूरी पात्रता होती है। उच्च शिक्षा में भविष्य देखने वाले युवाओं के लिए यह एक अहम शैक्षिक पड़ाव होता है। इस वर्ष यूजीसी नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। इससे पहले 2017 में यह बदलाव किया गया था। नेट की परीक्षा का आयोजन आनलाइन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार से इस आफलाइन मोड में किया जाएगा। अब उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी, कंप्यूटर उपकरणों के अपर्याप्त रखरखाव और बिजली की बाधा जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

नेट परीक्षा से जुड़ा एक बदलाव इस रूप में किया गया है कि पहले केवल स्नातकोत्तर पास करने वाले छात्र ही इस परीक्षा में शामिल हो सकते थे, लेकिन अब चार वर्षीय एकीकृत स्नातक कर रहे अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकेंगे। ऐसे उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए। ये छात्र किसी भी विषय में नेट की परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें वे पीएचडी करना चाहते हैं, भले ही उन्होंने चार वर्षीय स्नातक डिग्री किसी भी विषय में प्राप्त की हो। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव नेट परीक्षा के परिणाम की प्रकृति से जुड़ा है। पहले केवल नेट और जेआरएफ- दो वर्गों में इसके परिणाम जारी किए जाते थे। नेट क्वालीफाइ करने वाले छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता रखते थे और पीएचडी में भी नामांकन के लिए योग्य समझे जाते थे, वहीं दूसरा वर्ग जेआरएफ का था, जिसे उपरोक्त दो सुविधाओं के अतिरिक्त अधिकतम पांच वर्ष तक प्रत्येक महीने फेलोशिप प्रदान की जाती थी। हालांकि नेट और जेआरएफ के लिए क्वालीफाइ करने के बावजूद विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी में एडमिशन के लिए उन्हें पृथक-पृथक प्रवेश परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। लेकिन यूजीसी के नए बदलाव के तहत पीएचडी में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब नेट के स्कोर के आधार पर वे किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के परिणाम तीन वर्गों में जारी किए जाएंगे। पहले वर्ग में सर्वाधिक परसेंटाइल पाने वाले अभ्यर्थी होंगे, जिन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता और पीएचडी में एडमिशन की पात्रता भी हासिल होगी। वहीं दूसरे वर्ग में ऐसे अभ्यर्थी होंगे, जिन्हें फेलोशिप के योग्य नहीं समझा जाएगा, लेकिन वे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और पीएचडी में एडमिशन की पात्रता रखेंगे। वहीं, तीसरे वर्ग में चयनित अभ्यर्थी को न तो फेलोशिप का लाभ मिलेगा और न ही वे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता रख पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए योग्य माने जाएंगे। इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव इस रूप में है कि पहले नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी की पात्रता जीवनभर के लिए मान्य होती थी, लेकिन अब दूसरी व तीसरी श्रेणी में चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष के भीतर इसका लाभ उठाना होगा, अन्यथा उनकी पात्रता रद हो जाएगी।

पहली नजर में ऐसा लगता है कि इससे छात्रों की परेशानियां कम हो सकती हैं। इस संबंध में पहला तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे छात्रों को पीएचडी में एडमिशन के लिए भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा देने से मुक्ति मिल जाएगी। यह सही भी है। लेकिन यह भी देखना होगा कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा भले समाप्त हो गई है, लेकिन पीएचडी में एडमिशन की जो व्यवस्था बनाई गई है, वह भी निष्पक्ष प्रतीत नहीं होती है। अब पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट स्कोर को 70 प्रतिशत के एवज में माना जाएगा, शेष 30 प्रतिशत अंक विश्वविद्यालय के पास होंगे, जो इसके लिए साक्षात्कार का आयोजन करेंगे। विश्वविद्यालय को मिले इसी 30 अंक में अक्सर 'धांधली' होती है और कई बार योग्य अभ्यर्थी एडमिशन नहीं ले पाते हैं। हालांकि इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो कुछ अंकों से नेट क्वालीफाइ करने से चूक जाते थे और उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता था। कहा जा सकता है कि ऐसे अभ्यर्थियों को 'सांत्वना पुरस्कार' के रूप में तीसरी कैटेगरी दी जाएगी, जिससे वे कम से कम पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे।

पीएचडी में नामांकन की नई व्यवस्था। प्रतीकात्मक

बहरहाल, उम्मीद की जा रही है कि यूजीसी द्वारा किए जा रहे बदलाव देश में उच्च शिक्षा की स्थिति को सुधारने में सहायक साबित होंगे। शोध में गुणवत्ता लाने के लिए योग्य उम्मीदवारों को मौका देना आवश्यक है। शोध की दिशा में ठोस काम करने की दरकार है। शोध ऐसा हो, जो आमजन के जीवन को सुधारने में सहायक हो। शोध महज औपचारिक न हो, बल्कि उसकी गुणवत्ता देश को नई दिशा देने में समर्थ होना चाहिए। इस दिशा में युवाओं को ध्यान देने की आवश्यकता है।

****

अल्ट्राटेक सीमेंट का शुद्ध लाभ 35 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने सोमवार को बताया कि जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के दौरान उसका शुद्ध लाभ 2,258.58 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वर्ष की समान अवधि के 1,670.10 करोड़ के मुकाबले यह 35.24 प्रतिशत ज्यादा है। आदित्य बिरला समूह की कंपनी ने बताया कि बीती तिमाही में संचालन राजस्व 9.41 प्रतिशत बढ़कर 20,418.94 करोड़ रुपये रहा है। बीती तिमाही में कंपनी की बिक्री 11 प्रतिशत बढ़कर 3.50 करोड़ टन रही है। (प्रेट्र)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व में 3-5 प्रतिशत की वृद्धि रह सकती है, जो मौजूदा हालातों में काफी अच्छी वृद्धि होगी।
— सी. विजयकुमार, सीईओ, एचसीएल टेक्नोलाजीज

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलोग्राम	डालर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
74,671.28 ▲ 941.12	22,643.40 ▲ 223.45	₹72,750 ▼ ₹130	₹84,500 बदलाव नहीं	₹83.45 ▼ ₹0.07	$89.04

एक नजर में

महिंद्रा ने लांच की कांपैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 3एक्सओ

नासिक: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सोमवार को अपनी नई कांपैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 3एक्सओ लांच की। इसकी शुरुआती कीमत 7.49 लाख रुपये है। एक्सयूवी 3एक्सओ की बुकिंग 15 मई से शुरू होगी। इस मौके पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के कार्यकारी निदेशक राजेश जेजुरिकर ने कहा कि तीन वर्षों में हम कांपैक्ट एसयूवी श्रेणी में शीर्ष दो कंपनियों में शामिल होना चाहते हैं। (प्रेट्र)

ट्रैवल-टूरिज्म क्षेत्र में जुड़ेंगी 5.82 करोड़ नौकरियां

नई दिल्ली: वैश्विक टेक्नोलाजी फर्म एनएलबी सर्विसेज का कहना है कि 2033 तक भारत का ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र 5.82 करोड़ नौकरियां जोड़ने के लिए तैयार है। एनएलबी सर्विसेज के सीईओ सचिन अलग का कहना है कि इस क्षेत्र के बढ़ते तालमेल से देश के टियर-1 और टियर-2 शहरों में लगातार रोजगार सृजित हुआ है। कैलेंडर वर्ष 2023 में इस क्षेत्र में 16 लाख नौकरियां जुड़ने की उम्मीद है। (प्रेट्र)

ओला कैब्स के सीईओ ने चार माह में दिया इस्तीफा

नई दिल्ली: कैब सेवाएं देने वाले प्लेटफार्म ओला कैब्स के सीईओ हेमंत बख्शी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीईओ बनने के चार महीने के भीतर ही यह पद छोड़ दिया है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी पुनर्गठन की योजना बना रही है जिससे कम से कम 10 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। नया सीईओ चुने जाने तक कंपनी के संस्थापक भाविश अग्रवाल यह जिम्मेदारी संभालेंगे। (आइएएनएस)

वाई-फाई 6ई राउटर की आनलाइन बिक्री बंद हो

नई दिल्ली: सेल्यूलर आपरेटर्स के संगठन सीओएआइ ने एमेजान, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कामर्स प्लेटफार्म पर वाई-फाई 6ई राउटर की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। दूरसंचार विभाग को भेजे पत्र में सीओएआइ ने कहा है कि अभी तक सरकार ने 6 गीगाहर्टज बैंड उपयोग के लिए जारी नहीं किया है। ऐसे में इनकी बिक्री पूरी तरह से अवैध है।

बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से 941 अंक उछला सेंसेक्स

74,671 के स्तर पर बंद हुआ बीएसई का मानक सूचकांक, निफ्टी भी 223 अंक बढ़कर 22,650 के करीब पहुंचा

मुंबई, प्रेट्र: वैश्विक बाजारों में मजबूती के बीच घरेलू स्तर पर बैंकों और ढांचागत कंपनियों के शेयरों में तगड़ी खरीदारी से सोमवार को बीएसई सेंसेक्स ने 941 अंक की छलांग लगाई। जबकि एनएसई निफ्टी 22,600 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 941.12 अंक यानी 1.28 प्रतिशत उछलकर 74,671.28 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 990.99 अंक तक बढ़कर 74,721.15 पर पहुंच गया था। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का सूचकांक निफ्टी भी 223.45 अंक यानी एक प्रतिशत बढ़कर 22,643.40 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से आइसीआइसीआइ बैंक में लगभग पांच प्रतिशत की तेजी रही। मार्च तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 18.5 प्रतिशत बढ़कर 11,672 करोड़ रुपये हो जाने से इसके शेयरों को रफ्तार मिली। वहीं एचसीएल टेक्नोलाजीज के तिमाही नतीजे निवेशकों का उत्साह जगाने में नाकाम रहे और कंपनी के शेयर करीब छह प्रतिशत गिर गए। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के बढ़िया तिमाही नतीजों और बांड यील्ड में गिरावट आने से घरेलू स्तर पर बाजारों में तगड़ी उछाल देखी गई। बैंक निफ्टी ने चौथी तिमाही में अपने मजबूत प्रदर्शन से बाकी को पीछे छोड़ दिया।

इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में 2.48 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अब बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का पूंजीकरण 406.52 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

2015 शेयरों में तेजी दर्ज की गई | **1,894** शेयरों में गिरावट आई | **179** शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ

- शुद्ध लाभ बढ़ने से आइसीआइसीआइ बैंक में लगभग पांच प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई
- एचसीएल टेक्नोलाजीज के शेयर छह प्रतिशत गिरे, तिमाही नतीजे उत्साह बढ़ाने में नाकाम रहे

बढ़कर बंद होने वाले शेयर: आइसीआइसीआइ बैंक, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक

इन शेयरों में दर्ज की गई गिरावट
एचसीएल टेक्नोलाजीज, आइटीसी, विप्रो और बजाज फिनसर्व

सेक्टरवार तेजी

सेक्टर	तेजी
बैंकेक्स	2.70%
वित्तीय सेवाएं	1.81%
यूटिलिटी	1.12%
पावर	0.90%
एनर्जी	0.79%

बाजार ने सप्ताह की शुरुआत मजबूत रुख के साथ की और मौजूदा रुझान को जारी रखते हुए एक प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। अनुकूल वैश्विक संकेतों के साथ-साथ बैंकों और ढांचागत कंपनियों के शेयरों में उल्लेखनीय तेजी ने सकारात्मक शुरुआत में मदद की, जो दिन चढ़ने के साथ और मजबूत हुई।
-अजीत मिश्रा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, रेलिगेयर ब्रोकिंग

सोना 130 रुपये गिरा

सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 130 रुपये गिरकर 72,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। वहीं चांदी की कीमत 84,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटी के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कामेक्स पर सोना हाजिर 2,333 डालर पर कारोबार कर रहा था।

सेबी ने बीएसई से कुल मूल्य के आधार पर शुल्क मांगा

नई दिल्ली, प्रेट्र: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बीएसई को प्रीमियम मूल्य के बजाय उसके विकल्प अनुबंधों के 'कुल मूल्य' के आधार पर शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके बाद शेयर बाजार को अब अधिक रेगुलेटरी शुल्क चुकाना पड़ सकता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अनुबंध के कुल मूल्य (नोशनल वैल्यू) और प्रीमियम मूल्य के बीच बड़े अंतर के कारण बीएसई की ओर से सेबी को दिए जाने वाले शुल्क भुगतान में वृद्धि होगी। एक्सचेंज को पिछले वर्षों के अंतर भुगतान को 15 प्रतिशत ब्याज सहित चुकाने को कहा गया है। बीएसई के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि एक्सचेंज को 165 करोड़ रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना पड़ सकता है। सेबी के इस कदम के बाद बीएसई का शेयर सोमवार को एनएसई में 13.31 प्रतिशत तक गिरकर 2,783 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय करीब 19 प्रतिशत तक लुढ़क गया था। एक्सचेंज का बाजार वैल्यूएशन 37,675.24 करोड़ रुपये है। विकल्प कारोबार में 'नोशनल' यानी कुल कारोबार किए गए सभी अनुबंधों के कुल खरीद/बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 'प्रीमियम टर्नओवर' कारोबार किए गए सभी अनुबंधों पर भुगतान किए गए 'प्रीमियम' का योग है। चूंकि कुल मूल्य 'प्रीमियम' कारोबार से अधिक है, ऐसे में कुल कारोबार का चयन करने पर ज्यादा शुल्क देना होगा।

बीते वित्त वर्ष में एटीएम से औसत मासिक निकासी 5.51% बढ़ी

मुंबई, प्रेट्र: नकदी प्रबंधन करने वाली दिग्गज कंपनी सीएमएस इन्फोसिस्टम्स ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में एटीएम से औसत मासिक निकासी में 5.51 प्रतिशत की वृद्धि रही है। पूरे वित्त वर्ष के दौरान एक एटीएम से हर महीने 1.43 करोड़ रुपये की औसत निकासी की गई है। कंपनी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एक एटीएम से औसत मासिक निकासी 1.35 करोड़ रुपये थी।

रिपोर्ट के अनुसार, बीते वित्त वर्ष के दौरान महानगरों में औसत नकदी निकासी में 10.37 प्रतिशत की वृद्धि रही है। इसी तरह, अर्ध-शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 3.94 प्रतिशत और अर्ध-महानगरों में 3.73 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, एटीएम से नकदी निकासी में महानगरों में 37.49 प्रतिशत और अर्ध-शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 12.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सीएमएस इन्फोसिस्टम्स देश के करीब आधे एटीएम का प्रबंधन करती है। रिपोर्ट के अनुसार, बीते वित्त वर्ष के दौरान मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्षेत्र में औसत खर्च 29.30 प्रतिशत बढ़ा है।

ब्याज वसूली के अनुचित तरीकों के प्रयोग पर आरबीआइ चिंतित

केंद्रीय बैंक ने ऋणदाताओं से प्रक्रिया में सुधार करने और वसूले गए अतिरिक्त शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ ने कुछ बैंकों द्वारा ब्याज वसूलने में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने पर चिंता जताई है। केंद्रीय बैंक ने उन्हें इस प्रक्रिया में सुधार करने और ग्राहकों से वसूले गए अतिरिक्त शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया है। एक सर्कुलर में आरबीआइ ने कुछ ऋणदाताओं द्वारा अपनाई जा रही कुछ अनुचित प्रथाओं पर भी प्रकाश डाला है।

केंद्रीय बैंक ने सभी ऋणदाताओं को निर्देश दिया है कि वे ऋण वितरण के तरीके, ब्याज और अन्य शुल्क के संबंध में अपनाई प्रक्रियाओं की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करें। मौके पर जांच के दौरान आरबीआइ को इस तरह के मामले मिले, जिसमें कर्ज मंजूरी की तारीख से ब्याज वसूला जा रहा था ना कि ग्राहक को धन हस्तांतरण की तारीख से। ऐसे भी मामले सामने आए, जहां चेक की तारीख से ब्याज वसूल गया जबकि ग्राहक को चेक कई दिनों बाद सौंपा गया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि कुछ बैंक ऋण वितरण या पुनर्भुगतान के मामले में उस अवधि के लिए ब्याज नहीं ले रहे थे, जिसके लिए ऋण बकाया था। आरबीआइ ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में ग्राहकों को इस तरह के अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क वापस करने को कहा गया है।

घरेलू उद्योग के राजस्व में 4-6% वृद्धि संभव

मुंबई, प्रेट्र: क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही में भारतीय उद्योग के राजस्व में 4-6 प्रतिशत की वृद्धि रह सकती है। यह सितंबर, 2021 में शुरू हुई कोरोना महामारी की रिकवरी के बाद से सबसे धीमी तिमाही वृद्धि है। यह रिपोर्ट 350 कंपनियों के विश्लेषण पर आधारित है। हालांकि इसमें वित्तीय सेवाओं और तेल और गैस क्षेत्र की कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रेटिंग एजेंसी द्वारा जिन 47 सेक्टरों पर नजर रखी जाती है, उनमें से केवल 12 में तिमाही के लिए क्रमिक और साल-दर-साल राजस्व वृद्धि में सुधार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वस्थ शहरी मांग के कारण संगठित खुदरा क्षेत्र में लगातार 13वीं तिमाही में वृद्धि दर्ज की गई है।

बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं से प्रभावित होगा निर्यात

- निर्यातकों के संगठन फियो ने कहा, अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो इसका असर वैश्विक मांग पर दिखाई पड़ेगा
- भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के अलावा उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरें भी मांग में मंदी की प्रमुख वजह

नई दिल्ली, प्रेट्र: निर्यातकों के संगठन फियो ने कहा है कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के निर्यात पर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं ने 2023-24 में भारत के निर्यात को प्रभावित किया है। यह 3.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 437 अरब डालर पर आ गया है। आयात भी आठ प्रतिशत से अधिक घटकर 677.24 अरब डालर रह गया है।

फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, 'अगर वैश्विक स्थिति ऐसी ही बनी रही तो इसका असर वैश्विक मांग पर दिखाई पड़ेगा। पहली तिमाही में मांग में सुस्ती दिख सकती है।' उन्होंने कहा, 'तमाम चुनौतियों के बावजूद माल ढुलाई की दरों में नरमी आ रही है और यह संकेत देता है कि आने वाले समय में मांग पर असर पड़ सकता है। अगर मौजूदा स्थिति कायम रहती है तो विश्व व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।' उन्होंने कहा, 'भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के अलावा उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरें भी मांग में मंदी की प्रमुख वजह हैं। यूरोप जैसी कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में और अधिक मंदी देखी जा सकती है।' उन्होंने यह भी कहा कि 2023-24 के दौरान भारत की घरेलू मुद्रा में चीनी युआन के 4.8 प्रतिशत के मुकाबले 1.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं रुपये के मुकाबले थाइलैंड की मुद्रा में 6.3 प्रतिशत और मलेशिया की रिंगिट में सात प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

निर्यातकों को लंबी अवधि के लिए धन उपलब्ध कराए सरकार: सहाय

फियो के महानिदेशक ने सरकार को नकदी के मोर्चे पर निर्यातकों के लिए कुछ कदम उठाने का भी सुझाव दिया। सहाय ने कहा, "मांग में कमी के कारण, उसका उठाव कम होगा, इसलिए विदेशी खरीदारों को भुगतान करने में भी लंबा समय लगेगा। ऐसे में हमें लंबी अवधि के लिए धन की जरूरत होगी। उन्होंने निर्यातकों को भी ब्याज सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ब्याज समानीकरण योजना को आगे भी जारी रखने की मांग की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठ दिसंबर, 2023 को इस योजना को 30 जून तक जारी रखने के लिए 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी दी थी।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

महादेव एप मामले में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने मांगा समय

मुंबई: महादेव सट्टेबाजी एप मामले में महाराष्ट्र साइबर विभाग के समक्ष पेश होने के लिए अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने समय मांगा है। अभिनेत्री ने मुंबई में नहीं होने का हवाला देते हुए समय देने का अनुरोध किया है। गायक व रैपर बादशाह को भी पूछताछ का सामना करना पड़ा था। अभिनेता संजय दत्त को भी तलब किया गया था लेकिन उन्होंने पेश होने के लिए समय मांगा है। (एएनआइ)

मालवणी जहरीली शराब कांड में चार दोषी करार, 10 बरी

मुंबई: सत्र न्यायालय ने सोमवार को 2015 के मालवणी जहरीली शराब कांड मामले में चार आरोपितों को दोषी करार दिया। हालांकि सुबूतों के अभाव में 10 आरोपितों को बरी कर दिया गया। मामले में पुलिस ने महिलाओं समेत 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। जून 2015 में पश्चिमी पश्चिमी उपनगर मलाड के मालवणी में लक्ष्मी नगर झुग्गी बस्ती में जहरीली शराब पीने से 106 लोगों की मौत हो गई थी और 74 लोग दिव्यांग हो गए थे। (मिड-डे)

पाक में एसजीपीसी कर्मियों ने मस्जिद में पढ़ी नमाज, जांच

अमृतसर: बैसाखी पर्व पर पाकिस्तान स्थित गुरुधामों की यात्रा के दौरान एसजीपीसी के दो कर्मचारियों की ओर से वहां की एक मस्जिद में नमाज अदा करने के मामले की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने जांच शुरू कर दी है। पटियाला स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के मैनेजर करनैल सिंह ने बताया कि एसजीपीसी के सेवादार राम सिंह चड्ढा एवं गोबिंद सिंह बैसाखी पर्व पर जत्थे के साथ पाक गए थे। वहां दोनों ने मस्जिद में नमाज अदा की थी। (जासं)

दो बेटों को कमर में बांधकर कुएं में कूदी मां, तीनों की मौत

चित्रकूट: यूपी के चित्रकूट में पति से कहासुनी के बाद महिला दो मासूम बेटों को कमर में बांध कर कुएं में कूद गई। पति के घर लौटने पर पत्नी व बच्चों को घर में नहीं देख खोजबीन शुरू की गई तो तीनों के शव कुएं में उतराते मिले। (जासं)

इस्लाम न मानने वाले मुस्लिमों पर शरिया लागू होगा या नहीं, विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

- शीर्ष अदालत ने केंद्र और केरल सरकार को जारी किया नोटिस
- जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी इस मामले की अगली सुनवाई

नई दिल्ली, एएनआइ: सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर विचार करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया, जिसमें यह मांग की गई है कि मुस्लिम परिवारों का जो व्यक्ति मुस्लिम पर्सनल ला या शरिया कानून न मानना चाहे उस पर भारतीय उत्तराधिकार कानून लागू होना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने अटार्नी जनरल, आर. वेंकटरमणी से एक कानून अधिकारी को नामित करने के लिए कहा जो अदालत की सहायता कर सके। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी।

केरल निवासी और 'एक्स-मुस्लिम्स आफ केरल' की महासचिव साफिया पीएम नाम की महिला ने याचिका दायर कर कहा है कि इस्लाम में उसकी आस्था नहीं है हालांकि आधिकारिक तौर पर इस्लाम नहीं छोड़ा है। अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के मौलिक अधिकार चाहती हैं। इसमें "किसी भी धर्म को न मानने का अधिकार" भी शामिल है। इसलिए उस पर मुस्लिम पर्सनल ला (शरिया कानून) के बजाय विरासत के संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू होना चाहिए। कहा कि उसके पिता की भी मुस्लिम धर्म में आस्था नहीं लेकिन उन्होंने भी आधिकारिक तौर पर धर्म नहीं छोड़ा है।

याचिका में कहा गया, शरिया कानून के अनुसार जिस व्यक्ति की इस्लाम में आस्था खत्म हो जाती है उसे मुस्लिम समुदाय से बाहर कर दिया जाता है। इस कारण वह अपनी पैतृक संपत्ति में किसी भी विरासत के अधिकार की हकदार नहीं होगी।

शरिया कानून के अनुसार जिसने इस्लाम छोड़ दिया है, वह विरासत का अधिकार खो देगा। धर्म छोड़ने के बाद विरासत के अधिकार के लिए कोई प्रविधान नहीं होने से खतरनाक स्थिति हो जाएगी क्योंकि न तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और न ही शरिया कानून उसकी रक्षा कर सकेंगे।

याचिकाकर्ता से अनुरोध किया है कि उस पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रविधान लागू होना चाहिए। याचिकाकर्ता का मानना है कि शरिया कानून मुस्लिम महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं।

मप्र के मुख्य न्यायाधीश से सिविल जज के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा

नईदुनिया, जबलपुर

- एक ही मुद्दे पर दो अलग-अलग आदेश पारित करने का मामला

एक ही मुद्दे पर दो अलग-अलग आदेश पारित करने के मामले में मप्र हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने रायसेन जिले के बरेली में पदस्थ सिविल जज शर्मिला बिलवर के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा मुख्य न्यायाधीश से की है। एकलपीठ ने मामला मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश हाई कोर्ट प्रशासन को दिए हैं। दरअसल, उक्त सिविल जज ने एक ही उत्तराधिकार अधिनियम से जुड़े मुद्दे पर पर दो बार अलग-अलग तिथियों पर आदेश किया, जिसे हाई कोर्ट ने कदाचरण माना। हाई कोर्ट ने जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) को भेज सिविल जज शर्मिला की फाइलों की जांच करने व प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

रायसेन के बरेली में रहने वाली राम बाई, कमला बाई और ममता बाई की ओर से अधिवक्ता विजय शंकर पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पूर्व विधायक उदयपुरा भगवत सिंह की जुलाई 2023 में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। उनकी करोड़ों रुपये की संपत्ति के लिए उनकी विवाहित लड़कियों ने सिविल कोर्ट बरेली में प्रकरण प्रस्तुत कर दावा किया है। दोनों पक्षों के बीच एक तीसरा व्यक्ति मृतक भगवत सिंह का करीबी बता कर प्रकरण में पक्षकार बनाने का आवेदन देता है। जिस तिथि को आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, उसी दिन कोर्ट आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी के रूप में जोड़ने का आदेश कर देता है। पुनः दो माह बाद कोर्ट उसी आवेदन को स्वीकार करता है। दलील दी गई कि एक ही आवेदन पर दो बार आदेश नहीं दिया जा सकता, यह कृत्य जज की न्यायिक दक्षता पर प्रश्न बनकर सामने आया है।

बिहार में दामाद को सास से हो गया प्रेम, ससुर ने दोनों की करा दी शादी

जासं, बांका: बिहार के बांका जिले में दामाद को सास से प्रेम होने पर ससुर ने दोनों की शादी करवा दी। शादी के दौरान दामाद की मां भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र ने सास से शादी की है, मैं उसे पुत्रवधू के रूप में स्वीकार्य करती हूं। दिलेश्वर दर्वे और गीता देवी की पुत्री से सिकंदर यादव से शादी हुई थी। कुछ दिन पहले सिकंदर की पत्नी का देहांत हो गया। सिकंदर के एक बेटा और बेटी है। पत्नी के मरने के बाद सिकंदर यादव और सास गीता निकट आने लगे। पिछले कुछ दिनों से सिकंदर अक्सर ससुराल हीर मोती गांव आने लगा। दिलेश्वर को शक हुआ। ग्रामीणों ने सिकंदर व गीता को बुलाकर समझाया और कहा कि ऐसा व्यवहार समाज को कलंकित करता है, लेकिन दोनों ने शादी कर देने की बात कही। ग्रामीणों के सामने दिलेश्वर दर्वे ने पत्नी और दामाद की शादी करवा दी। बांका न्यायालय में जाकर दोनों की शादी को कानूनी मान्यता दिला दी।

वाराणसी समेत देश के 30 हवाईअड्डों को बम से उड़ाने की दी गई धमकी

जागरण संवाददाता, वाराणसी

- एयरपोर्ट निदेशक को आए मेल के बाद आइबी और एलआइयू अलर्ट पर

जयपुर, नागपुर, कानपुर, वाराणसी सहित देश के 30 हवाईअड्डों को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मिला है। वाराणसी एयरपोर्ट के निदेशक पुनीत गुप्ता को सोमवार को भेजे गए ईमेल में लिखा है कि हमने सभी 30 एयरपोर्ट पर बम लगा दिया है और रिमोट का बटन दबाते ही उनमें धमाका हो जाएगा। हाईअलर्ट जारी करते हुए आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सीआइएसएफ, कमिश्नरेट पुलिस समेत खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। ग्रामीणों को संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति दिखाई देने पर सूचना देने को कहा। सीआइएसएफ के वरिष्ठ कमांडेंट अजय कुमार ने कहा कि यह सिरफिरे का काम हो सकता है, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आइबी व एलआइयू को अलर्ट रहने को कहा गया है।

तीसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी: वाराणसी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की तीसरी बार धमकी मिली है। इससे पहले बिहार के गया निवासी सिंचाई विभाग के इंजीनियर बिनीत कुमार ने एक ईमेल एयरपोर्ट निदेशक को भेजा था। उसने लिखा था कि होली के दिन एयरपोर्ट, राष्ट्रपति भवन, रेलवे स्टेशन, दिल्ली का जंतर-मंतर, संसद भवन, वाराणसी एयरपोर्ट आदि पर ड्रोन से रासायनिक हमला करेगा। हालांकि, चार दिन बाद बिहार की एसआइटी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि विरोधियों को फंसाने के लिए यह हरकत की थी। पिछले साल आठ सितंबर को भदोही के मानसिक दिव्यांग युवक अशोक कुमार ने एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर के नंबर पर फोन कर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी थी। उसे अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मेडिकल प्रमाण पत्र दिखाने के बाद छोड़ दिया गया।

सलमान खान के घर पर फायरिंग के तीन आरोपितों को पुलिस हिरासत में भेजा

मुंबई, प्रेट्र: मुंबई की एक विशेष अदालत ने बांद्रा स्थित सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों को सोमवार को आठ मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने आरोपित विक्की गुप्ता, सागर पाल और अनुज थापन को पुलिस हिरासत में और सोनू कुमार चंदर बिश्नोई को चिकित्सा आधार पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने शूटर गुप्ता और पाल के साथ ही बिश्नोई और थापन के खिलाफ मकोका कानून के प्रविधानों के तहत शनिवार को मुकदमा दर्ज किया था। बिश्नोई और थापन पर दो पिस्टल और कारतूस उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस ने गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई व उसके भाई अनमोल को वांछित आरोपित बताया है। इसके तार लारेंस गैंग से जुड़ने से पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है।

****

बेटी व दामाद के साथ 48 किलो हेरोइन सप्लाई करने जा रहा किंगपिन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जालंधर

पंजाब पुलिस ने 48 किलो हेरोइन और 41 लाख ड्रग मनी के साथ अंतरराष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह के किंगपिन और उसकी बेटी व दामाद को जालंधर से गिरफ्तार किया है। आरोपित बेटी और दामाद के साथ हेरोइन की सप्लाई करने निकला था। आरोपितों की पहचान शहीद भगत सिंह नगर के गांव ढंडियां के रहने वाले किंगपिन सतनाम सिंह उर्फ बब्बी, उसकी बेटी रोजी और दामाद हरदीप सिंह के रूप में हुई है। गिरोह के किंगपिन सतनाम सिंह के पास से आठ किलो हेरोइन बरामद की गई, जबकि बाकी 40 किलो हेरोइन रोजी और हरदीप सिंह से बरामद की गई है। पुलिस ने इनसे तीन महंगी इनोवा, महिंद्रा एक्सयूवी और हुंडई वरना कारें भी जब्त की हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि जालंधर पुलिस ने सोमवार को भगत सिंह कालोनी बाईपास के पास नाके पर एक कार को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने गाड़ी भगा ली। पुलिस ने पीछा कर कार चालक सतनाम सिंह को काबू कर गाड़ी की तलाशी ली तो एक बैग से आठ किलो हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी बेटी रोजी और दामाद हरदीप भी हेरोइन की सप्लाई करने जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने नकोदर जालंधर रोड पर दोनों गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 40 किलो हेरोइन, 41 लाख रुपये की ड्रग मनी, दो कारें और एक नकदी गिनने की मशीन बरामद की। पुलिस ने सतनाम को कोर्ट में पेश कर छह दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि पुलिस ने बीते दिनों एक नशा तस्कर को पकड़ा था तो पता चला कि वह जम्मू-कश्मीर से हेरोइन लेकर आया। पुलिस ने जांच की तो सतनाम का नाम सामने आया। यहीं से पता चला था कि सतनाम पंजाब में बड़ी सप्लाई करने के लिए निकला है। बरामद हेरोइन पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात के अलावा कनाडा सहित अन्य कई देशों में सप्लाई होनी थी। आरोपितों को विदेश से ड्रग मनी हवाला के जरिये आती थी।

हेरोइन तस्करों से बरामद कारें, ड्रग मनी व नकदी गिनने वाली मशीन। सौ: पुलिस

45 लोगों की मौत सोमवार को केन्या के माईमाहिउ क्षेत्र में किजाबे बांध के टूटने पर बाढ़ आने से हो गई। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अबतक 100 लोगों की मौत हो चुकी है।

इजरायली हमले में रफाह में 25 फलस्तीनी मरे

युद्ध का दंश ▶ मरने वालों में छह महिलाएं, पांच बच्चे, उनमें एक पांच दिन का

अमेरिकी विदेश मंत्री छह महीने में सातवीं बार क्षेत्र के दौरे पर

यरुशलम, एपी : इजरायल ने मिस्र सीमा पर बसे गाजा के रफाह शहर पर जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं की है लेकिन हवाई हमलों में कोई रियायत नहीं कर रहा है। सोमवार रात इजरायली सेना के हवाई हमले में रफाह में 25 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में छह महिलाएं और पांच बच्चे हैं। इजरायली हमले में मारा गया एक बच्चा महज पांच दिन का था।

इजरायल रफाह पर लगातार हवाई हमले कर रहा है जबकि वहां पर करीब 14 लाख बेघर लोग शरण लिए हुए हैं। ये लोग इजरायली सेना के निर्देश पर ही जान बचाने के लिए रफाह आए थे लेकिन हवाई हमलों के शिकार होने के साथ ही पिछले डेढ़ महीने से इन पर जमीनी सैन्य कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। इस समय इजरायली सेना क्षेत्र में घेरा डाले हुए है और इजरायल ने 33 लाचार बंधकों की अविलंब रिहाई न होने पर रफाह पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इजरायली सेना के अनुसार बेघर लोगों के बीच हमास के सैकड़ों लड़ाके छिपे हुए हैं। आमजनों को क्षेत्र से स्थानांतरित कर लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गाजा युद्ध शुरू होने के बाद सातवीं बार क्षेत्र के दौरे पर हैं। उनकी कोशिश इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा में लड़ाई रुकवाने की है। सऊदी अरब से दौरा शुरू करने के बाद ब्लिंकन जार्डन और इजरायल जाएंगे। इस बीच ब्लिंकन ने युद्धविराम के लिए हमास से इजरायल का प्रस्ताव मान लेने का अनुरोध किया है। इजरायल ने छह हफ्ते के युद्धविराम के लिए 33 बंधकों की रिहाई की शर्त रखी है। अनुमान है कि हमास के पास इजरायल के 129 नागरिक हैं जिन्हें सात अक्टूबर, 2023 को इजरायली शहरों से अगवा कर बंधक बनाया गया था। करीब सात महीने के युद्ध में इजरायली हमलों में 34 हजार से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं।

दक्षिण गाजा पट्टी के रफाह में सोमवार को इजरायल के हवाई हमले में स्वजन के मारे जाने पर मातम करती फलस्तीनी महिला। रायटर

दक्षिण गाजा पट्टी के रफाह में सोमवार को इजरायल के हवाई हमले में ध्वस्त भवनों का मलबा। रायटर

फलस्तीनियों की मौत पर इजरायली नेताओं के लिए जारी हो सकता वारंट

यरुशलम, एपी : इजरायल के अधिकारियों को आशंका है कि गाजा में निर्दोष लोगों को मारे जाने के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इजरायली नेताओं की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। 2014 में हुई इजरायल और हमास की लड़ाई में कई निर्दोष फलस्तीनी मारे गए थे। न्यायालय ने तीन वर्ष पूर्व निर्दोषों के मारे जाने की जांच कराई थी। इसमें इजरायल के कई नेताओं और अधिकारियों की युद्ध अपराध के मामलों में संलिप्तता पाई गई है। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन संकेत दिया कि कई लोगों की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकते हैं। इजरायली विदेश मंत्री इजरायल काज ने कहा है कि ऐसा कोई वारंट हमास और अन्य आतंकी संगठनों के हौसले बढ़ाएगा।

ब्रिटेन के प्राकृतिक संग्रहालय बोर्ड में दोबारा सलाहकार बना भारतवंशी

लंदन, ब्रेटू: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पर्यावरण विज्ञान क्षेत्र के अग्रणी भारतवंशी शिक्षाविद् यादविंदर माल्ही को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में दोबारा नियुक्त किया है। चार वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त प्रोफेसर माल्ही अवैतनिक सलाहकार की भूमिका में प्राकृतिक संरक्षण में संस्था की भूमिका की देखरेख करेंगे। इससे पहले मई 2020 में उन्हें बोर्ड में पहली बार नियुक्ति मिली थी।

प्रोफेसर माल्ही ने अपनी नियुक्ति पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य अद्भुत, सम्मानित और बहुचर्चित संस्थान को अनुसंधान और सार्वजनिक-नीतिगत जुड़ाव में मदद करना है।

उन्होंने कहा कि सबसे बुनियादी सवाल है कि हम प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने संबंधों को कैसे समझ और पुनर्स्थापित कर सकते हैं। आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भूगोल और पर्यावरण स्कूल में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रोफेसर माल्ही को 2020 में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जन्मदिन के अवसर पर उनकी सेवाओं के लिए सीबीई (कमांडर आफ ब्रिटिश एंपायर) की पदवी से सम्मानित किया गया था।

विदित हो कि 50 वर्षीय माल्ही ब्रिटिश पारिस्थितिकी सोसायटी और एसोसिएशन फार ट्रापिकल बायोलाजी एंड कंजर्वेशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वह विज्ञान व संरक्षण की दिशा में वैश्विक समानता के पक्षधर हैं।

ट्रूडो के सामने लगे खालिस्तान समर्थक नारे, भारत नाराज

- कहा भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर जताई चिंता
- कहा- यह कनाडा में अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को दी गई राजनीतिक संरक्षण को दर्शाता है

टोरंटो, एएनआइ : कनाडा में खालसा दिवस समारोह में एकत्र लोगों ने पीएम जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। टोरंटो में रविवार को इस अवसर पर सिख समुदाय को संबोधित करते हुए कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कहा कि देश में आपके मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं, भारत ने खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने पर पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उप उच्चायुक्त को तलब किया है। कहा, यह कनाडा में अलगाववाद, उग्रवाद व हिंसा को दी गई राजनीतिक जगह को दर्शाता है।

खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की पिछले वर्ष जून में कनाडा के सरे में हुई हत्या का आरोप जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर लगाकर विवाद खड़ा कर दिया था। भारत ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद से कनाडा और भारत के संबंधों में खटास आ गई। कनाडा के सीपीएसी टीवी द्वारा जारी वीडियो में दिख रहा है कि खालसा दिवस समारोह में जस्टिन ट्रूडो के भाषण के दौरान जमकर खालिस्तान समर्थक नारे लग रहे हैं। समारोह में विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवरे, एनडीपी नेता जगमीत सिंह और टोरंटो मेयर ओलविया चाऊ आदि मौजूद थे।

पीएम ट्रूडो ने सिख समुदाय से कहा कि लगभग आठ लाख कनाडाई सिख देश की विरासत में भागीदार हैं। सरकार सामुदायिक केंद्रों, गुरुद्वारों की सुरक्षा और मजबूत करेगी। साथ ही कनाडा सरकार भारत के साथ दोनों देशों के बीच उड़ानें और रूट बढ़ाने को लेकर नए समझौते पर काम कर रही है। इसमें अमृतसर के लिए और उड़ान बढ़ाना शामिल है।

टोरंटो के सिटी हाल में सोमवार को खालसा दिवस समारोह के दौरान कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को तलवार और अन्य वस्तुएं भेंट की गईं। एपी

जी-7 देश 2035 तक कोयले वाले बिजली संयंत्र बंद करने पर सहमत

- जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम
- ब्रिटेन के ऊर्जा सुरक्षा मंत्री ने इसे ऐतिहासिक समझौता बताया

ट्यूरिन, रायटर : जी7 समूह के ऊर्जा मंत्रियों ने एक समझौता किया है जिसमें 2035 तक अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करने पर सहमति बनी है। इसे जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्रिटेन के ऊर्जा सुरक्षा मंत्री एंड्रयू बावी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक समझौता है। इटली के राजनयिक सूत्रों ने कहा कि एक तकनीकी समझौता हो गया है। इस समझौते को ट्यूरिन में दो दिवसीय बैठक के अंत में मंगलवार को जारी होने वाली जी7 ऊर्जा मंत्रियों की अंतिम घोषणा में शामिल किया जाएगा।

इटली के जलवायु परिवर्तन थिंक-टैंक ईसीसीओ के सह-संस्थापक सदस्य लुका बर्गमास्ची ने कहा कि यह विशेष रूप से जापान में और व्यापक रूप से चीन और भारत सहित संपूर्ण एशियाई अर्थव्यवस्था में कोयले से स्वच्छ प्रौद्योगिकी की ओर निवेश के बदलाव में तेजी लाने में मदद करेगा। इटली ने पिछले साल कुल बिजली का 4.7 प्रतिशत उत्पादन कोयला आधारित स्टेशनों के माध्यम से किया था। रोम वर्तमान में सार्डिनिया द्वीप को छोड़कर 2025 तक अपने संयंत्रों को बंद करने की योजना बना रहा है। जर्मनी और जापान में कोयले की बड़ी भूमिका है। पिछले साल जापान की अध्यक्षता में जी7 समूह ने कोयला से बिजली उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की दिशा में ठोस कदमों को प्राथमिकता देने का वादा किया था, लेकिन एक विशिष्ट समय सीमा का संकेत नहीं दिया गया था।

उल्लेखनीय है जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरा विश्व चिंतित है और विभिन्न स्तरों पर ऐसे उपायों पर जोर दिया जा रहा कि तापमान में हो रही बढ़ोतरी को जल्द से जल्द थामा जाए। इस दिशा में यह अच्छी पहल है।

पेड्रो सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री बने रहेंगे

मेड्रिड, एपी : स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सोमवार को कहा कि कई दिनों के चिंतन के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि वे पद पर बने रहेंगे। सांचेज ने देश को उस समय चौंका दिया था, जब घोषणा की थी कि एक अदालत द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी पत्नी के खिलाफ प्रारंभिक कार्यवाही शुरू किए जाने के बाद अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए वह पांच दिन की छुट्टी ले रहे हैं।

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज (फाइल)। एपी

उन्होंने कहा कि मैंने स्पेन की सरकार के शीर्ष पर और भी अधिक मजबूती के साथ बने रहने का फैसला लिया है। उनकी पत्नी बेगोना गोमेज के खिलाफ कानूनी शिकायत की गई थी, जिसमें कहा गया है कि गोमेज ने व्यापारिक सौदों को प्रभावित करने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया।

नाटो प्रमुख बोले, यूक्रेन को अब तेज होगी हथियारों की आपूर्ति

- यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे स्टोलटेनबर्ग ने माना, पश्चिमी देश वादा पूरा करने में रहे विफल
- जेलेंस्की ने रूस से मुकाबला करने को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने का किया अनुरोध

कीव, रायटर: नाटो प्रमुख जेंस स्टोलटेनबर्ग इस समय यूक्रेन यात्रा पर हैं। उन्होंने सोमवार को यूक्रेन से कहा कि हाल के महीनों में गठबंधन सदस्य सैन्य सहायता देने का अपना वादा पूरा करने में विफल रहे हैं, लेकिन अब हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति बढ़ेगी। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति तेज करने का अनुरोध किया है, जिससे रूस का मुकाबला किया जा सके।

यूक्रेन की अघोषित यात्रा पर पहुंचे नाटो महासचिव स्टोलटेनबर्ग ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर युद्ध के हालात पर चर्चा की। वह यूक्रेन की संसद को भी संबोधित करेंगे। फरवरी, 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से नाटो प्रमुख की यह तीसरी यूक्रेन यात्रा है।

नाटो प्रमुख ने कहा कि मैं राष्ट्रपति और संसद से ईमानदारी से कहूं तो नाटो ने हाल के महीनों में अपना वादा नहीं निभाया है। अमेरिका ने पैकेज पर सहमत होने में छह महीने लगा दिए, जबकि यूरोपीय सहयोगी हथियारों की मदद करने में विफल रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं इस बारे में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसमें जल्द बदलाव दिखेगा। इस बीच, तुर्किये ने कहा है कि वह नए नाटो प्रमुख के लिए नीदरलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूट्स की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा।

वहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसकी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र के एक गांव पर कब्जा कर लिया है और खार्कीव क्षेत्र में बेहतर स्थिति में है।

कीव में वार्ता पहले नाटो महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग का स्वागत करते यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। यह फोटो यूक्रेनी राष्ट्रपति प्रेस सेवा ने सोमवार को जारी की। एएफपी

नए देश भी मदद को आ सकते हैं आगे

स्टोलटेनबर्ग ने अमेरिका का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिकी कांग्रेस ने 60 अरब डालर के पैकेज को मंजूरी दे दी है। पिछले हफ्ते ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भी यूक्रेन से प्रतिबद्धता दोहराई है। जर्मनी भी पेट्रियाट वायु रक्षा प्रणाली देने पर सहमत हुआ है, नीदरलैंड्स भी सहायता को बढ़ाएगा। इसके साथ ही नई प्रतिबद्धताओं की भी उम्मीद है। सब ठीक हो जाएगा। वहीं, चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा ताइवान के लिए पैकज पर हस्ताक्षर करने को लेकर संकेत दिया है कि इससे प्रतिशोध बढ़ सकता है।

पोलैंड के किसान यूक्रेन सीमा से हटे

पोलैंड और यूक्रेन के बीच सभी सीमाएं खुल गई हैं। पोलैंड के किसानों और ट्रक वालों ने कई महीनों से सीमा को अवरुद्ध कर रखा था। उनमें रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा और सस्ते अनाज को लेकर रोष था। उन्होंने सरकार से विदेशी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले घाटे को लेकर चिंता जताई थी।

अमेरिका में फलस्तीन समर्थकों से वार्ता विफल, आंदोलन हुआ तेज

- लास एंजिलिस में फलस्तीन और इजरायल समर्थकों में टकराव
- बाइडन ने कहा, सभी को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार

लास एंजिलिस, रायटर : अमेरिका के विश्वविद्यालयों में फलस्तीनियों के समर्थन में छात्रों का आंदोलन कमजोर नहीं पड़ रहा है। न्यूयार्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में आंदोलनकारियों के साथ प्रशासन की वार्ता विफल हो गई है और धरना दे रहे छात्रों को परिसर छोड़ने के लिए कहा गया है। जबकि लास एंजिलिस के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में नारेबाजी करते फलस्तीन व इजरायल समर्थक आमने-सामने आ गए और उनमें टकराव हो गया। इस टकराव में कई छात्र-छात्रा चोटिल हुए हैं। आंदोलन के चलते सोमवार को भी सैकड़ों छात्र-छात्राओं की गिरफ्तारी हुई है।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में आमने-सामने आए दोनों पक्षों के छात्रों ने नारेबाजी करते हुए एक-दूसरे को धक्के दिए और घूंसेबाजी की। बाद में वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों और विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों ने बेंत चलाकर दोनों पक्षों के लोगों को तितर-बितर किया। विश्वविद्यालय की कुलपति मैरी ओसाको ने कहा है कि विश्वविद्यालय का इतिहास शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का रहा है लेकिन हिंसा की ताजा घटना से उन्हें धक्का लगा है। बीते दो हफ्तों में फलस्तीनियों के समर्थन में अमेरिका में आंदोलन तेजी से बढ़ा है। ज्यादातर विश्वविद्यालय और कालेज इसकी चपेट में आ गए हैं। आंदोलनकारी गाजा में युद्धविराम और इजरायल के साथ अमेरिका के संबंध तोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। न्यूयार्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, अटलांटा और बोस्टन में आंदोलन में शामिल सैकड़ों छात्र-छात्रा गिरफ्तार किए गए हैं। कई शिक्षण संस्थाओं में दंगा निरोधी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

देश में तेज हो रहे फलस्तीनियों के समर्थन वाले आंदोलन का राष्ट्रपति जो बाइडन ने संज्ञान लिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जान किर्बी ने बताया है कि राष्ट्रपति किसी भी मसले पर शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन करते हैं। लेकिन वह हिंसा, घृणास्पद बयानों और यहूदी विरोधी भावनाओं के विरोधी हैं।

फ्रांस के विवि में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला : फ्रांस में पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय के नजदीक सोमवार को फलस्तीनियों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए छात्रों ने जुलूस निकाला। करीब एक सौ छात्रों ने बड़ा सा फलस्तीनी झंडा लेकर फलस्तीन के समर्थन और इजरायल के विरोध में जुलूस निकाला।

चीन में पहली कोविड वैक्सीन विकसित करने वाले विज्ञानी संसद से बर्खास्त

बीजिंग, ब्रेटू : चीन में कोरोना महामारी के दौरान पहली वैक्सीन विकसित करने वाले विज्ञानी को कथित भ्रष्टाचार के लिए संसद से बर्खास्त कर दिया गया। चाइना नेशनल फार्मास्युटिकल ग्रुप की वैक्सीन सहायक कंपनी चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप (सीएनबीजी) के अध्यक्ष यांग जियाओमिंग को गंभीर अनुशासन और कानून के उल्लंघन के कारण नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की सदस्यता से हटाया गया है। 62 वर्षीय यांग अनुभवी शोधकर्ता हैं। उन्होंने सीएनबीजी में उस टीम का नेतृत्व किया था, जिसने सिनोफार्मा की बीबीआइबीपी-कोरवी वैक्सीन विकसित की थी। यांग को सितंबर 2020 में इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यांग की बर्खास्तगी चीन की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर सबसे बड़ी कार्रवाई के बीच आई है, जो पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा शुरू किए गए व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का विस्तार है।

चीन ने मस्क को दी बड़ी राहत, टेस्ला कारों से हटाया प्रतिबंध

- तकनीकी दिग्गज रविवार को अचानक पहुंचे थे चीन, प्रधानमंत्री कियांग से की थी मुलाकात

बीजिंग, ब्रेटू: भारत की यात्रा टालने के एक सप्ताह बाद रविवार को अचानक चीन पहुंचे एलन मस्क के लिए सोमवार राहत भरी खबर लेकर आया। चीन ने डाटा सुरक्षा नियमों के अनुपालन की मुख्य परीक्षा पास करने का हवाला देते हुए टेस्ला की कारों से सभी प्रतिबंध हटा दिए। चीन ने हाल के महीनों में डाटा सुरक्षा लीक होने की चिंता के कारण सैन्य ठिकानों के अलावा सरकारी इमारतों में टेस्ला कारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। मस्क ने रविवार को टेस्ला कारों से प्रतिबंध हटाने के लिए प्रधानमंत्री ली कियांग से बातचीत की थी।

चाइना एसोसिएशन आफ आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क इमरजेंसी रिस्पांस टेक्निकल टीम ने सोमवार को देश के डाटा सुरक्षा परीक्षणों को पास करने वाले इंटेलिजेंट कनेक्टेड वाहनों के 76 माडलों की सूची प्रकाशित की। इस सूची में टेस्ला की कारें भी शामिल हैं। सरकार द्वारा संचालित शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह सूची बीवाईडी और टेस्ला सहित स्थानीय चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के माडल को मंजूरी देने वाले दो संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सुरक्षा परीक्षणों के बाद जारी की गई।

इधर, चीन यात्रा के दौरान मस्क ने एक्स पोस्ट में वीडियो साझा करते हुए कहा कि मैं चीन का बहुत बड़ा फैन हूं और मेरे भी यहां बहुत प्रशंसक हैं। इसके साथ ही मस्क ने चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ वाली फोटो भी एक्स पोस्ट की है।

डाटा सुरक्षा लीक होने के डर से टेस्ला कार कई स्थानों पर था प्रतिबंधित

पुतिन ने नवलनी की जान लेने का आदेश नहीं दिया : अमेरिकी अधिकारी

वाशिंगटन, एपी : अमेरिकी गुप्तचर अधिकारियों का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जेल में बंद क्रेमलिन के धुर आलोचक नेता 47 वर्षीय नवलनी की जान लेने का आदेश नहीं दिया। आर्कटिक पीनल कालोनी में बंद नवलनी की 16 फरवरी को मौत हो गई थी। रूस के अधिकारियों ने नवलनी की मृत्यु स्वाभाविक बताया था।

गौरतलब है कि नर्व एजेंट जहर दिए जाने से बीमार हो गए नवलनी इलाज के लिए जर्मनी गए थे और रूस लौटने के बाद जनवरी 2021 से जेल में बंद थे। नवलनी ने उस समय क्रेमलिन पर उन्हें जहर देने का आरोप लगाया था। नवलनी की मौत के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि पुतिन अंततः जिम्मेदार हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे पुतिन पर आदेश देने का आरोप नहीं लगाया था। बाइडन ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी मौत पुतिन और उनके साथियों के कारनामे का परिणाम थी।

स्काटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने इस्तीफा दिया

लंदन, एपी : स्काटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले ही सोमवार को इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले ही हमजा की अगुआई वाली स्काटिश नेशनल पार्टी ने नीतिगत मुद्दों पर तनातनी के बाद ग्रीन पार्टी से संबंध तोड़ लिया था। 39 वर्षीय यूसुफ ने पिछले साल मार्च में स्काटलैंड के पहले मुस्लिम और क्षेत्र के सबसे युवा फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में पदभार संभाला था।

हमजा यूसुफ। एएफपी

एडिनबर्ग के ब्यूट हाउस में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं बहुत आभारी हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, जो ऐसा अवसर मुझे मिला। पाकिस्तानी और केन्याई मूल के यूसुफ ने ब्रिटेन की विविधता की भी इस दौरान बात की।

तबाही के निशां

चीन के दक्षिणी गुआंगजौ में आए शक्तिशाली तूफान ने भारी तबाही मचाई है। सर्वाधिक नुकसान एक करोड़ 90 लाख की आबादी वाले शहर गुआंगजौ में हुआ है, जहां सैकड़ों घर तबाह हो गए। तूफान के दौरान कई लोगों की मौत होने की भी सूचना है। न्यूज एजेंसी की खबरों में बताया गया है कि तूफान में 141 फैक्ट्रियों की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। फिलहाल नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। रायटर

सोलोमन द्वीप के चीन समर्थक पीएम अगले कार्यकाल की दौड़ से बाहर

मेलबर्न, एपी : दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित रणनीतिक महत्व के सोलोमन द्वीप के निवर्तमान प्रधानमंत्री मानासेह सोगावारे ने सोमवार को अगले कार्यकाल की दौड़ से स्वयं को बाहर कर लिया। अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंद्विता का केंद्र कहे जाने वाले सोलोमन द्वीप में दो सप्ताह पहले आम चुनाव कराए गए थे। चुनाव में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला। इसी सप्ताह नए प्रधानमंत्री का चुनाव कराया जाएगा और सोगावारे की पार्टी पूर्व विदेश मंत्री जेरेमिआह मानेले का समर्थन कर सकती है। सोलोमन द्वीप की दो प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने शनिवार को गठबंधन किया। किसी के पास बहुमत नहीं होने के कारण दोनों पार्टियां सरकार बनाने के लिए सोगावारे की पार्टी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। 50 सदस्यीय चैंबर में प्रधानमंत्री को कम से कम 26 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। चुनाव में सोगावारे की यूनिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी पार्टी को सबसे ज्यादा 15 सीटें मिली हैं।

पाकिस्तान ने आइएमएफ के सामने फिर फैलाया हाथ

इस्लामाबाद, ब्रेटू : आर्थिक बदहाली झेल रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के सामने हाथ फैलाया है। रियाद में चल रही वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की एक विशेष बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आइएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जार्जीवा से मुलाकात की और उनसे नए ऋण पैकेज को लेकर गुहार लगाई। उन्होंने बदहाल पाकिस्तान को कंगाली से बचाने के लिए तीन अरब डालर का राहत पैकेज देने के लिए आइएमएफ का धन्यवाद भी किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस्लामाबाद की ओर से कहा गया है कि उसे कम से कम तीन वर्ष के लिए एक लोन की सख्त जरूरत है, जिससे देश में आर्थिक स्थिरता लाने में सहायता मिल सके। अगर यह राहत पैकेज मंजूर होता है तो यह आइएमएफ की ओर से 24वां बेलआउट पैकेज होगा।

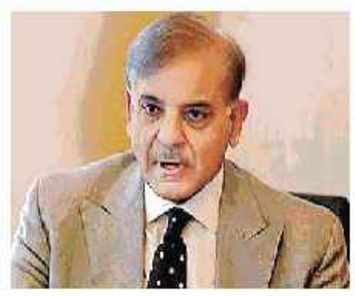

शहबाज शरीफ। फाइल फोटो

इस बीच, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि आइएमएफ से बेलआउट मांगने का सरकार का निर्णय एक स्वीकारोक्ति है कि हम विफल रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अर्थव्यवस्था के सभी संकेतक नकारात्मक हैं। इससे अलग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनका देश पोलियो उन्मूलन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

****

टी-20 आइपीएल

www.jagran.com

पर्पल कैप

गेंदबाज	टीम	विकेट
बुमराह	मुंबई	14
मुस्तफिजुर	सीएसके	14
हर्षल पटेल	पंजाब	14

आरेंज कैप

बल्लेबाज	टीम	रन
विराट कोहली	आरसीबी	500
रुतुराज	सीएसके	447
साई सुदर्शन	गुजरात	418

बदली पिच पर गेंदबाजों ने बदला खेल

केकेआर ने गेंदबाजों के जबरदस्त प्रदर्शन से दिल्ली को सात विकेट से हराया चक्रवर्ती ने लिए तीन विकेट

विशाल श्रेष्ठ ● जागरण

कोलकाता: पिछले मैच में पंजाब के हाथों ऐतिहासिक हार के बाद चौतरफा आलोचना झेल रहे कोलकाता के गेंदबाजों ने सोमवार को उसी ईडन गार्डेंस स्टेडियम में दिल्ली के विरुद्ध जबर्दस्त तरीके से वापसी करते हुए उसकी मजबूत बल्लेबाजी का गर्दा उड़ा दिया। बाकी कसर आरंभिक बल्लेबाज फिल साल्ट ने पूरी कर दी। पिछले दो मैचों में 200 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दिल्ली इस बार पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 153 रन ही जोड़ पाई। कोलकाता ने इसके जवाब में 16.3 ओवर में ही तीन विकेट खोकर 157 रन बना डाले। इस सत्र में कोलकाता की दिल्ली पर यह दूसरी जीत है। इससे पहले कोलकाता ने आइपीएल में अपना अब तक का सर्वाधिक स्कोर 272 बनाते हुए दिल्ली को 106 रनों से करारी शिकस्त दी थी। जबकि ईडन गार्डेंस में कोलकाता ने 10 मैचों में आठवीं बार दिल्ली को हराया है।

बदला नजारा : कौन कहेगा, इसी ईडन गार्डेंस में महज दो दिन पहले पंजाब 262 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को आसानी से साधकर आइपीएल ही नहीं, बल्कि टी-20 क्रिकेट की सबसे बड़ी 'चेज मास्टर' बनी थी। 48 घंटे बीतते न बीतते पूरा नजारा बदल गया। पिछले कुछ मैचों से बुरी तरह पीटते आ रहे कोलकाता के गेंदबाजों ने कमाल दिखाते हुए दिल्ली की मजबूती बल्लेबाजी को धराशायी कर दिया। कुछ कैच न छूटे होते तो शायद दिल्ली के इतने रन भी न बन पाते। उसका कोई बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं जड़ पाया। शानदार फार्म में चल रहे कप्तान रिषभ पंत, जैक फ्रेजर मैक्गर्क से लेकर ट्रिस्टन स्टब्स व शाई होप तक किसी का बल्ला नहीं बोला। आठवें नंबर के बल्लेबाज कुलदीप यादव ने सर्वाधिक अविजित 35 रन बनाए।

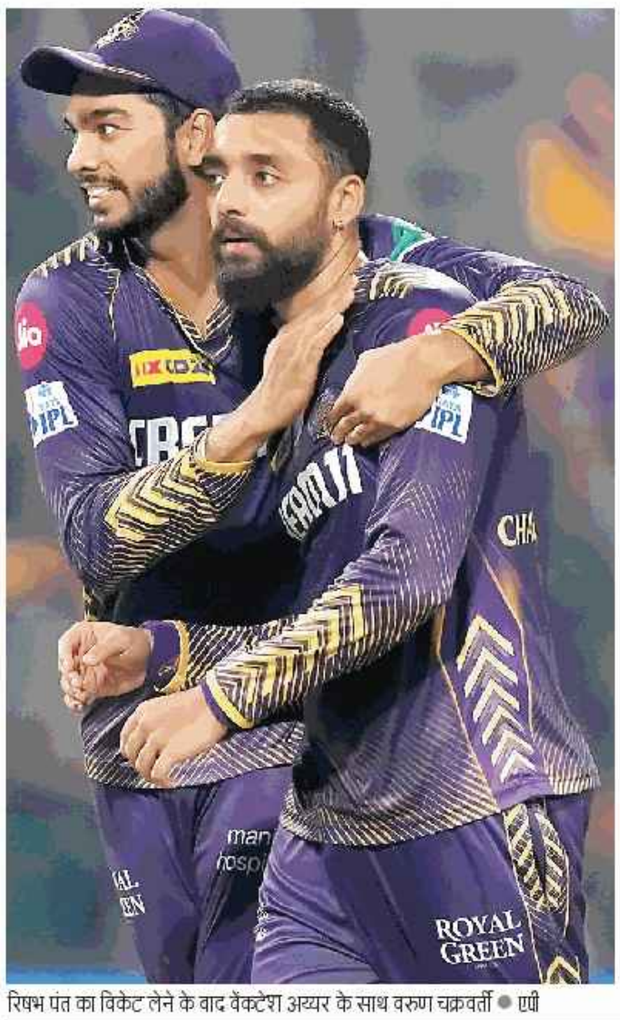

रिषभ पंत का विकेट लेने के बाद वेंकटेश अय्यर के साथ वरुण चक्रवर्ती ● एपी

हड़बड़ में हुई गड़बड़ : दिल्ली की खराब बल्लेबाजी का एक प्रमुख कारण तेजी से रन बनाने के चक्कर में हड़बड़ी में बल्लेबाजी भी है। यहां पिछले कुछ मैचों में बने बड़े-बड़े स्कोर को देखकर दिल्ली को लगा कि 200 से कम रन बनाने पर जीतना मुश्किल हो जाएगा लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जिन पिचों पर रन बने थे, यह वह पिच नहीं है।

गेंदबाजों के नाम मैच : पिच के नाम पर कोलकाता के गेंदबाजों से श्रेय छीन लेना सही नहीं होगा क्योंकि इसी पिच पर कोलकाता के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। पिछले मैच में बेहद शर्मनाक गेंदबाजी के बाद कोलकाता के गेंदबाजों ने जिस तरह से वापसी की है, वह काबिले तारीफ है। अंतिम एकादश में वापसी करने वाले वैभव अरोड़ा ने शुरू में दोहरा झटका दिया तो वरुण चक्रवर्ती ने उससे दिल्ली के बल्लेबाजों को उबरने नहीं दिया।

शानदार साल्ट : कोलकाता के आरंभिक बल्लेबाज फिल साल्ट (68) मैच-दर-मैच विध्वंसक होते जा रहे हैं। उन्होंने 33 गेंदों पर 68 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें सात चौके व पांच छक्के शामिल रहे। आइपीएल में यह उनका चौथा अर्धशतक है। साल्ट ने पंजाब के विरुद्ध पिछले मैच में भी 37 गेंदों पर धुआंधार 75 रन बनाए थे।

तो क्या सौरव की सुन ली : पूर्व कप्तान व दिल्ली के क्रिकेट निदेशक सौरव गांगुली ने दो दिन पहले ही आइपीएल में गेंदबाजों की बेरहमी से हो रही पिटाई पर गंभीर चिंता जताते हुए बीसीसीआइ से इस ओर देखने का अनुरोध किया था। दरअसल उनका इशारा परोक्ष तौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल सपाट विकेट बनाए जाने की ओर था। उन्होंने कहा था कि गेंद और बल्ले के बीच संतुलन होना जरुरी है। लगता है कि बीसीसीआइ, विशेषकर उनके होम ग्राउंड रहे ईडन गार्डेंस के क्यूरेटर सुजन मुखर्जी ने इसपर विचार किया है। सोमवार को जिस पिच पर मैच हुआ, वह भिन्न विकेट थी। ईडन गार्डेंस के क्यूरेटर सुजन मुखर्जी ने खुद इसकी पुष्टि की, हालांकि यह नहीं बताया कि उन्होंने इस पिच को गेंदबाजों के अनुकूल बनाने के लिए कुछ किया था या नहीं।

स्कोर बोर्ड

दिल्ली कैपिटल्स : 153/9 (20 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
पृथ्वी का. साल्ट बो. वैभव	13	07	3/0
मैक्गर्क का. वेंकटेश बो. स्टार्क	12	07	1/1
पोरेल बो. हर्षित राणा	18	15	2/1
शाई होप बो. वैभव	06	03	0/1
रिषभ पंत का. श्रेयस बो. चक्रवर्ती	27	20	2/1
अक्षर बो. नारायण	15	21	2/0
स्टब्स का. साल्ट बो. चक्रवर्ती	04	07	0/0
कुशाग्र का. साल्ट बो. चक्रवर्ती	01	03	0/0
कुलदीप यादव अविजित	35	26	5/1
रसिख डार का. श्रेयस बो. हर्षित	08	10	1/0
विलियम्स अविजित	01	02	0/0

अतिरिक्त : 13 (लेबा-3, वा-9, नोबा-1)
कुल : 20 ओवर में नौ विकेट पर 153 रन
विकेटपतन : 1-17 (पृथ्वी, 1.3), 2-30 (मैक्गर्क, 2.5), 3-37 (होप, 3.3), 4-68 (पोरेल, 6.4), 5-93 (पंत, 10.1), 6-99 (स्टब्स, 12.1), 7-101 (अक्षर, 13.3), 8-111 (कुशाग्र, 14.3), 9-140 (डार, 18.2)
गेंदबाजी : स्टार्क 3-0-43-1, वैभव 4-0-29-2, हर्षित 4-0-28-2, नारायण 4-0-24-1, चक्रवर्ती 4-0-16-3, आंद्रे रसेल 1-0-10-0

कोलकाता : 157/3 (16.3 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
फिल साल्ट बो. अक्षर	68	33	7/5
नारायण का. मैक्गर्क बो. अक्षर	15	10	3/0
रिंकू का. कुलदीप बो. विलियम्स	11	11	1/0
श्रेयस अय्यर अविजित	33	23	3/1
वेंकटेश अय्यर अविजित	26	23	2/1

अतिरिक्त : 4 (लेबा-2, वा-1, नोबा-1)
कुल : 16.3 ओवर में तीन विकेट पर 157 रन
विकेटपतन : 1-79 (नारायण, 6.1), 2-96 (साल्ट, 8.1), 3-100 (रिंकू, 9.2)
गेंदबाजी : विलियम्स 3-0-38-1, खलील 3-0-28-0, रसिख डार 2.3-0-30-0, अक्षर पटेल 4-0-25-2, कुलदीप 4-0-34-0

कोलकाता के क्रिकेट प्रेमी बोले, जहां दादा, वहां हम

ईडन गार्डेंस में सोमवार को कोलकाता नाइटराइडर्स के समर्थकों का खेमा बंटा नजर आया। अन्य मैचों के समय कोलकाता का पुरजोर समर्थन करने वाले बहुत से लोग इस दिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए तालियां बजाते दिखे। इसका कारण भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली हैं, जो वर्तमान में दिल्ली कैपिटल्स के निदेशक हैं। मालूम हो कि कोलकाता के क्रिकेट प्रेमियों का सौरव से मजबूत भावनात्मक जुड़ाव है। मैच देखने पहुंचे सुमित पाल व आशीष बनर्जी ने कहा- 'हम तो वहां हैं, जहां हमारे दादा हैं। हम अन्य टीमों के विरुद्ध मैच के समय कोलकाता का समर्थन करते हैं लेकिन अभी दिल्ली का मनोबल बढ़ाने आए हैं।

इकाना स्टेडियम में एलएसजी का आज मुंबई से होगा सामना

'राजधानी एक्सप्रेस' वापसी को तैयार

विकास मिश्र ● जागरण

लखनऊ : राजस्थान रायल्स के विरुद्ध हार से बेपटरी हुई लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम को मुंबई के विरुद्ध घर पर फिर से जीत की पटरी पर लाने के लिए 'राजधानी एक्सप्रेस' मैदान में उतरेंगे। करियर की शुरुआत दो मैचों में टीम की जीत के नायक रहे तेज गेंदबाज मयंक यादव मुंबई इंडियंस के विरुद्ध चोट से उबरकर वापसी करेंगे। मुंबई इंडियंस के विरुद्ध टीम की जीत के साथ प्लेआफ का दावा मजबूत करने पर होंगी। साथ ही टी-20 विश्व कप की टीम की घोषणा से पहले केएल राहुल भी अच्छा प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं की नजरों में दावा मजबूत करना चाहेंगे।

गेंदबाजी कोच ने की पुष्टि : लखनऊ सुपरजायंट्स के गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल ने मुंबई के विरुद्ध मैच की पूर्व संध्या पर कहा कि मयंक यादव पूरी तरह फिट हैं। उन्होंने नेट पर देर तक गेंदबाजी की है। मयंक ने फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया है। अब किसी तरह की समस्या नहीं है। टीम प्रबंधन उनकी वापसी को लेकर उत्साहित है। वह मंगलवार को मैदान में उतरने को तैयार हैं।

केएल राहुल के पास बड़ा अवसर: लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के पास आगामी टी-20 विश्व कप के लिए चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का अंतिम अवसर होगा। राहुल इस मैच में अगर बल्ले से कमाल करते हैं तो टीम इंडिया के लिए दरवाजा खुलना तय माना जाएगा। आइपीएल के मौजूदा सत्र में 42 की औसत और 144 के स्ट्राइक रेट से 378 रन बनाकर शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल राहुल का मुंबई के अच्छा रिकार्ड रहा है। बुमराह ने राहुल को भले ही दो पारियों में आउट किया है, लेकिन राहुल, बुमराह पर 71.5 की औसत और 127.67 के स्ट्राइक रेट से रन जुटाए हैं। पीयूष चावला और हार्दिक पांड्या के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट लगभग 170 और मोहम्मद नबी के विरुद्ध 200 से अधिक का है। वहीं, कैरेबियाई बल्लेबाज निकोलस पूरन भी शानदार फार्म में हैं। उन्होंने नौ मैचों में 291 रन बनाए हैं। लखनऊ को अगर जीत की पटरी पर लौटना है तो क्विंटन डिकाक और मार्कस स्टोइनिस को बड़ी पारी खेलनी होगी।

लखनऊ का पलड़ा भारी : लखनऊ और मुंबई के बीच अब तक हुए चार मुकाबलों में एलएसजी का पलड़ा 3-1 से भारी है, जबकि इकाना के मैदान में पिछले साल ये दोनों टीमें पहली बार भिड़ी थीं तो लखनऊ को पांच रनों की रोमांचक जीत मिली थी। अंक तालिका की बात करें तो नौ मैचों में पांच जीत और 10 अंकों के साथ लखनऊ की टीम पांचवें, जबकि इतने ही मैचों में छह अंकों के साथ मुंबई नौवें स्थान पर है। टीम को प्लेआफ में जगह बनाने के लिए पांच मैच जीतने होंगे।

अभ्यास के दौरान मयंक यादव ● प्रेट्र

मुंबई इंडियंस : हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, डेवाल्ड ब्रेविस, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, टिम डेविड, श्रेयस गोपाल, इशान किशन, अंशुल कंबोज, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, क्वेना मफाका, मोहम्मद नबी, शम्स मुलानी, नमन धीर, शिवालिक शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, अर्जुन तेंदुलकर, तिलक वर्मा, नुवान तुषारा, हार्विक देसाई, नेहाल वढेरा और ल्यूक वुड।

एलएसजी : केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डिकाक, दीपक हुड्डा, आयुष बडोनी, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, क्रुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, शमार जोसेफ, यश ठाकुर, एम सिद्धार्थ, प्रेरक मांकड, अरशद खान, कृष्णप्पा गौतम, अमित मिश्रा, काइल मेयर्स, एश्टन टर्नर, मैट हेनरी, नवीन उल हक, देवदत्त पडिक्कल, युद्धवीर चरक, मयंक यादव और अर्शिन कुलकर्णी।

अंक तालिका		मैच	जीत	हार	टाई	नेट रन रेट	अंक
1	राजस्थान	9	8	1	0	+0.694	16
2	केकेआर	9	6	3	0	+1.096	12
3	सीएसके	9	5	4	0	+0.810	10
4	हैदराबाद	9	5	4	0	+0.075	10
5	लखनऊ	9	5	4	0	+0.059	10
6	दिल्ली	11	5	6	0	-0.442	10
7	गुजरात	10	4	6	0	-1.113	8
8	पंजाब	9	3	6	0	-0.187	6
9	मुंबई	9	3	6	0	-0.261	6
10	आरसीबी	10	3	7	0	-0.415	6

एक नजर में

ओलिंपिक क्वालीफायर टीम में नहीं किया कोई बदलाव

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ ने नए ट्रायल के लिए समय की कमी के कारण अगले महीने इस्तांबुल में अंतिम ओलिंपिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के लिए लगभग उसी टीम का चयन किया है, जिसने बिश्केक में एशियाई क्वालीफायर में भाग लिया था। नौ से 13 मई तक होने वाले विश्व ओलिंपिक खेल क्वालीफायर में एशियाई क्वालीफायर की टीम में विनेश फोगाट (50 किग्रा), अंशू मलिक (57 किग्रा) और अंडर-23 विश्व चैंपियन रितिका (76 किग्रा) को शामिल नहीं किया गया। (प्रेट्र)

मुक्केबाजी में बृजेश, सागर, सुमित के पदक पक्के

अस्ताना: भारत के बृजेश तामता, सागर जाखड़ और सुमित ने एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश करके पदक पक्के कर लिए। बृजेश (48 किग्रा) ने उज्बेकिस्तान के साबिरोव सैफिद्दीन को हराया। दोनों मुक्केबाजों ने एक एक दौर जीता, लेकिन तीसरे दौर में भारतीय मुक्केबाज ने 4-3 से जीत दर्ज की। सागर (60 किग्रा) और सुमित (67 किग्रा) ने क्रमश: थाईलैंड के कलासीरम टी और कोरिया के होंग सियो जिन को 5-0 से हराया। (प्रेट्र)

गिलेस्पी ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को दिया संदेश

लाहौर: पाकिस्तान के नए मुख्य कोच जेसन गिलेस्पी चाहते हैं कि उनके प्रतिभाशाली खिलाड़ी 'वास्तविक' बने रहें और किसी विशिष्ट पद्धति के अनुरूप अपने खेल में बदलाव नहीं करें। उनका कहना है कि टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए उन्हें केवल सकारात्मक और आक्रामक रहने की आवश्यकता है। (प्रेट्र)

दीक्षा एलईटी आर्डर आफ मेरिट के शीर्ष 10 में पहुंचीं

केपटाउन: भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर इन्वेस्टेक दक्षिण अफ्रीका महिला ओपन में एक और अच्छे प्रदर्शन के बाद लेडीज यूरोपियन टूर (एलईटी) के आर्डर आफ मेरिट के शीर्ष-10 में पहुंच गईं। दीक्षा अब 455 अंकों के साथ एलईटी में नौवें स्थान पर है। इंग्लैंड के ब्रोंटे ला शीर्ष पर हैं। प्रणवी उर्स अपने पहले वर्ष में 25वें स्थान के साथ अगली सर्वश्रेष्ठ भारतीय हैं। दीक्षा का आगामी पेरिस ओलिंपिक खेलों में भाग लेना लगभग तय है जो टोक्यो के बाद उनका दूसरा ओलिंपिक होगा। (प्रेट्र)

चैंपियंस ट्राफी के लिए तीन स्थलों का चयन

क्रिकेट डायरी

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अगले वर्ष होने वाली चैंपियंस ट्राफी के स्थलों के रूप में कराची, लाहौर और रावलपिंडी का चयन किया है। चैंपियंस ट्राफी में भारत की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हाइब्रिड माडल की अटकलों के बीच पीसीबी ने फिर दोहराया है कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही आयोजित किया जाएगा। चैंपियंस ट्राफी अंतिम बार 2017 में इंग्लैंड में आयोजित की गई थी और इसके अगले वर्ष फरवरी-मार्च में कराए जाने की संभावना है।

भारत ने अभी तक अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है और ऐसी अटकलें हैं कि आइसीसी हाइब्रिड माडल का उपयोग करके भारत के मैच तटस्थ स्थान पर करा सकता है, अगर भारतीय टीम को सरकार से यात्रा की मंजूरी नहीं मिलती है। आइसीसी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह किसी सदस्य देश को उसकी सरकारी नीति का उल्लंघन करने को नहीं कहेगा। पिछले वर्ष एशिया कप का आयोजन हाइब्रिड माडल पर किया गया था।

स्टीव वा ने जयपुर की गलियों का लिया आनंद

आस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वा इन दिनों जयपुर की गलियों का भ्रमण कर रहे हैं। भारत दौरे पर आए पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने इस दौरान ई-रिक्शा की भी सवारी की। साथ ही उन्होंने सड़कों पर सब्जी बेचने वालों के साथ फोटो भी खिंचवाई। वा 1999 में विश्व कप जीतने वाली आस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे। स्टीव ने जयपुर के एक स्थानीय क्रिकेट क्लब का भी दौरा किया, जहां आस्ट्रेलियाई लड़कियों की टीम अभ्यास मैच खेलने पहुंची थीं ● एक्स

रिंकू को विश्व कप टीम में देखना चाहता हूं: शाह रुख

नई दिल्ली, जेएनएन : कोलकाता नाइटराइडर्स के सह स्वामी शाह रुख खान ने अपनी टीम के आक्रामक बल्लेबाज रिंकू सिंह को आगामी टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम में शामिल करने की अनुशंसा की। उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि रिंकू भारतीय टीम का हिस्सा हों। साथ ही उन्होंने कहा कि वह रिंकू जैसे खिलाड़ियों में स्वयं को देखते हैं, उन्हें आगे बढ़ते देखकर बहुत खुशी होती है। एक कार्यक्रम में चर्चा के दौरान शाह रुख ने कहा, 'मैं यही चाहता हूं कि रिंकू विश्व कप की टीम का हिस्सा हों। मैं जब इनको खेलते देखता हूं, मुझे लगता है कि मैं इनमें एक खिलाड़ी के रूप में जी रहा हूं। विशेषकर रिंकू और नीतीश जैसे खिलाड़ियों में मैं स्वयं को देखता हूं। उन्हें देखकर खुशी होती है।'

आज भारतीय टीम पर बनाई जाएगी सहमति

अभिषेक त्रिपाठी ● जागरण

टीम चयन को लेकर अहमदाबाद में मंगलवार को होगी बैठक

नई दिल्ली : अमेरिका और वेस्टइंडीज में तीन जून से होने वाले वाले टी-20 विश्व कप के लिए मंगलवार को अहमदाबाद में चयनसमिति की बैठक होगी। टीम की घोषणा बुधवार तक की जानी है क्योंकि इसी दिन आइसीसी को 15 सदस्यीय टीम की सूची सौंपने की अंतिम तिथि है। मंगलवार को अहमदाबाद में मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर सहित सभी चयनकर्ता और कोच राहुल द्रविड़ उपस्थित रहेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मंगलवार को लखनऊ से आनलाइन जुड़ सकते हैं। वह सुपरजायंट्स के विरुद्ध मुंबई इंडियंस के लिए मैच खेलने के लिए लखनऊ में हैं। बैठक में बीसीसीआइ सचिव जय शाह भी मौजूद रहेंगे। अलग-अलग कई बैठकें होने के बाद अब अंतिम बैठक होगी। इसमें अंतिम-15 पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी।

हाल ही में विदेश में छुट्टियां बिताकर लौटे मुख्य चयनकर्ता अगरकर ने दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के मैच से इतर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ से दिल्ली में मुलाकात की थी। रोहित ने अगरकर और द्रविड़ को टी-20 विश्व कप में टीम संयोजन व आवश्यकता से अवगत करा दिया है और संभव है कि 15 सदस्यीय टीम में कोई चौंकाने वाला नाम न हो। सूत्रों के अनुसार, शीर्ष तीन बल्लेबाजों के रूप में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली का चयन हो सकता है। ऐसे में संजू सैमसन को टीम में शामिल करने पर चयनकर्ताओं को माथापच्ची करनी पड़ेगी क्योंकि संजू भी आइपीएल में नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि नंबर चार पर सूर्यकुमार यादव का खेलना तय है। ऐसे में फिलहाल संजू की जगह बनती नहीं दिख रही है। इसी तरह शुभमन गिल का चुना जाना भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि वह भी शीर्ष क्रम में खेलते हैं। विकेटकीपर के रूप में रिषभ पंत पहली पसंद हैं। दूसरे विकेटकीपर के रूप में केएल राहुल, ध्रुव चंद जुरैल और जितेश शर्मा के नामों पर भी चर्चा है क्योंकि ये पांचवें और छठे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं।

न्यूजीलैंड ने पुराने चेहरों पर लगाया दांव

नई दिल्ली, जेएनएन : न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सोमवार को आगामी टी-20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें ज्यादातर पुराने खिलाड़ियों पर ही भरोसा जताया गया है। केन विलियमसन को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि केवल रचिन रवींद्र और मैट हेनरी ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहली बार टी-20 विश्व कप में खेलेंगे। अंगूठे की चोट के कारण आइपीएल से बाहर चल रहे डेवोन कान्वे की कीवी टीम में वापसी हुई है।

न्यूजीलैंड टीम के 15 में से 13 खिलाड़ी 2022 में वेस्टइंडीज दौरे पर खेल चुके हैं। विलियमसन छठी बार टी20 विश्व कप खेलेंगे। वहीं टिम साउदी का यह सातवां टी20 विश्व कप होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के केंद्रीय अनुबंध से बाहर रहने वाले ट्रेंट बोल्ट को पांचवीं बार टी-20 विश्व कप टीम में जगह मिली है। टखने की चोट के कारण एडम मिल्ने बाहर हैं जबकि काइल जैमीसन कमर की चोट के कारण टीम में नहीं हैं।

नई जर्सी में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ● एक्स

टीम इस प्रकार है

केन विलियमसन (कप्तान), फिन एलेन, ट्रेंट बोल्ट, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कान्वे, लाकी फर्ग्युसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, जिमी नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सैंटनर, ईश सोढी और टिम साउथी। बेन सीयर्स (रिजर्व खिलाड़ी)।

स्टीव स्मिथ का कट सकता है पत्ता: आइपीएल में बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर रहे जैक फ्रेजर मैक्गर्क के कारण टी-20 विश्व कप के लिए आस्ट्रेलियाई टीम में स्टीव स्मिथ की जगह खतरे में पड़ गई है। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो स्मिथ को आस्ट्रेलियाई टीम में जगह मिलना मुश्किल है।

भारत क्वार्टर फाइनल में

चेंगडू, प्रेट्र : गत चैंपियन भारत ने इंग्लैंड को 5-0 से हराकर थामस कप बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 4-1 से हराया था। एच एच प्रणय ने हैरी हुआंग को 21-15, 21-15 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। सात्विकसाईंराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बेन लेन और सीन वेंडी को डबल्स मुकाबले में 21-17, 19-21, 21-15 से हराया। विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने नदीम दलवी को 21-16, 21-11 से हराकर भारत को 3-0 से बढ़त दिला दी। दूसरी डबल्स टीम एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला ने रोरी और एलेक्स को 21-17, 21-19 से हराया। अंतिम मैच में किरण जार्ज ने कायान को 21-18, 21-12 से मात दी। भारत का सामना अंतिम ग्रुप मैच में इंडोनेशिया से होगा। एक दिन पहले भारतीय महिला टीम ने उबेर कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी।

जीत के बाद भारतीय बैडमिंटन टीम ● एक्स

ओलिंपिक में हिस्सा लेंगे सात भारतीय शटलर : पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधू सहित सात भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपनी ओलिंपिक खेल क्वालीफिकेशन रैंकिंग के आधार पर चार वर्ग में पेरिस खेलों के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालीफाई किया। सिंधू और शीर्ष सिंगल्स पुरुष खिलाड़ी प्रणय और लक्ष्य सेन ने बहुत पहले ही ओलिंपिक में जगह पक्की कर ली थी और इसकी औपचारिकता सोमवार को पूरी हुई, जो निर्धारित कट आफ तिथि थी। पात्रता नियमों के अनुसार कट आफ तिथि पर ओलिंपिक खेल क्वालीफिकेशन रैंकिंग के आधार पर पुरुष और महिला सिंगल्स में शीर्ष 16 बैडमिंटन खिलाड़ी ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई करते हैं। सिंधू 12वें स्थान पर रहीं, जबकि पुरुष सिंगल्स में प्रणय और लक्ष्य क्रमशः नौवें और 13वें स्थान पर रहे।

बायर्न के सामने रीयल मैड्रिड की चुनौती

चैंपियंस लीग

बायर्न म्यूनिख vs रीयल मैड्रिड
रात 12:30 बजे | स्थान : म्यूनिख
सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क

नई दिल्ली, जेएनएन : जर्मनी के शीर्ष फुटबाल क्लब बायर्न म्यूनिख के सामने मंगलवार को चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के पहले चरण में 14 बार के चैंपियन रीयल मैड्रिड की चुनौती होगी। घर पर भले इस सत्र में बायर्न का रिकार्ड शानदार रहा हो, परंतु विगत सात मुकाबलों में रीयल मैड्रिड के सामने उनकी एक नहीं चली है। टीम के लिए इस सत्र में सबसे शानदार प्रदर्शन हैरी केन का रहा है, एक बार फिर दिग्गज टीम के सामने उनपर टीम का दारोमदार होगा। वहीं, रीयल मैड्रिड की ओर से इस सत्र में सबसे अधिक प्रभावित जूड बेलिंघम ने किया है।

केन पर निर्भर है टीम : पहले ही बुंडिसलीगा खिताब की दौड़ और डीएफबी पोकल से बाहर हो चुकी बायर्न म्यूनिख की टीम की अंतिम उम्मीद चैंपियंस लीग ही है। क्वार्टर फाइनल के पहले चरण में पिछड़ने के बावजूद घरेलू मैदान अलियांज अरीना में टीम ने दूसरे चरण में शानदार वापसी करते हुए एटलेटिको मैड्रिड को हराया था। टीम को एक बार फिर स्पेन की शीर्ष टीम के विरुद्ध वैसा ही प्रदर्शन करना होगा। इसमें टीम की नजरें हैरी केन पर होंगी, जिन्होंने इस सत्र में टीम के लिए रिकार्ड 42 गोल दागे हैं। चैंपियंस लीग में भी उन्होंने सात गोल किए हैं।

क्वार्टर फाइनल में गत चैंपियन मैनचेस्टर सिटी के विरुद्ध पेनाल्टी शूटआउट में जीतने वाली रीयल मैड्रिड की टीम अब बायर्न के विरुद्ध पहले ही चरण में बड़ी बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी। टीम ने अपने स्वभाव से विपरीत मैनचेस्टर सिटी के विरुद्ध रक्षात्मक खेल दिखाया था, परंतु अब अलियांज अरीना में टीम अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में दिखेगी। इस दौरान टीम के युवा स्ट्राइकर जूड बेलिंघम, विनिसियस जूनियर और रोड्रिगो पर नजरें होंगी। बेलिंघम ने इस सत्र में टीम के लिए सर्वाधिक 21 गोल दागे हैं।

हैरी केन ● एएफपी

जूड बेलिंघम ● एएफपी

दीपिका टाप्स में फिर शामिल

खेल डायरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : शंघाई में हाल ही में हुए विश्व कप में रजत पदक जीतने वाली विश्व की पूर्व नंबर एक तीरंदाज दीपिका कुमारी को पेरिस ओलिंपिक से पहले टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम (टाप्स) में फिर शामिल किया गया है। दिसंबर 2022 में मां बनने के बाद पिछले वर्ष पूरे सत्र में बाहर रहीं दीपिका ने हाल ही में वापसी की है और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा खेल रही हैं। तीन बार की ओलिंपियन रिकर्व तीरंदाज दीपिका ने इस वर्ष एशिया कप में भी पदक जीता। अभी तक पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में सिर्फ धीरज बोम्मादेवरा ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई कर सके हैं। अंतिम क्वालीफाइंग टूर्नामेंट अंताल्या में 15 और 16 जून को होगा।

खेल मंत्रालय के अनुसार तीरंदाज मृणाल चौहान को भी टाप्स विकास ग्रुप में शामिल किया गया है जबकि प्रवीण जाधव को विकास से कोर ग्रुप में डाला गया है। पैरा पावरलिफ्टर अशोक को भी कोर ग्रुप में रखा गया है। मिशन ओलिंपिक सेल ने 133वीं बैठक में स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह, अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार को भी टाप्स विकास ग्रुप में रखा है ताकि वे 2028 लास एंजिलिस खेलों की तैयारी कर सकें।

दीपिका कुमारी ● फाइल फोटो, प्रेट्र

भारत के सेंथिल कुमार ने जीता बैच ओपन स्क्वाश

पेरिस, प्रेट्र : भारत के वेलावन सेंथिल कुमार ने बैच ओपन चैलेंजर टूर्नामेंट जीत लिया है जो पेशेवर स्क्वाश एसोसिएशन टूर (पीएसए) पर उनका आठवां खिताब है। दुनिया के 58वें नंबर के खिलाड़ी सेंथिल कुमार ने फ्रांस के मेलविल स्कियानिमानिको को 11-6, 11-9, 11-6 से हराया। 12,000 डालर (लगभग 10 लाख रुपये) के टूर्नामेंट में जीत के बाद सेंथिल ने कहा कि मुझे शुरुआत से ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ा और मुझे खुशी है कि मैं ऐसा कर सका।

****

दैनिक जागरण
सप्तरंग
अंतस और अध्यात्म का
मंगलवार, 30 अप्रैल, 2024

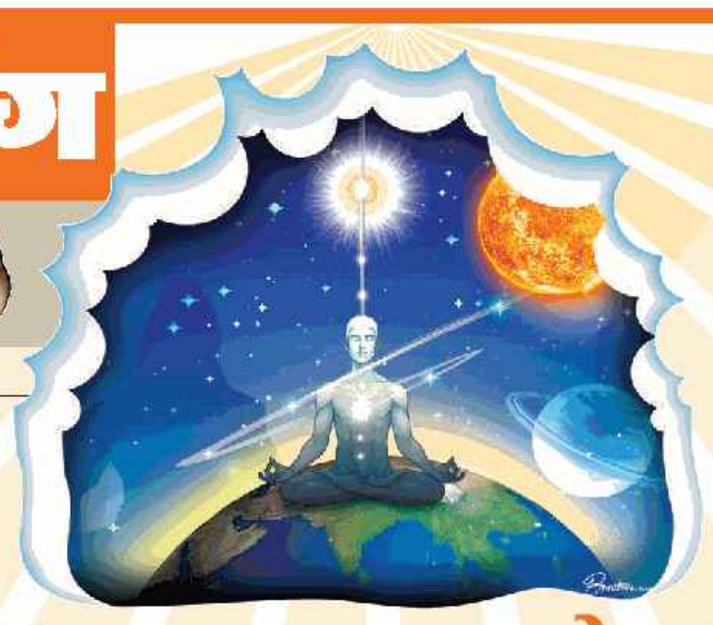

जीवन दर्शन

ब्रह्मा कुमारी शिवानी
प्रेरक वक्ता

आत्म-परमात्म योग

हम शाश्वत प्रेम के अर्थ को जानें तथा अपनी दृष्टि, वृत्ति, रुचि, स्नेह और श्रद्धा को बाह्य तत्वों से आत्मिक सत्यों की ओर मोड़ें अर्थात अपने मन, बुद्धि एवं भावनाओं को स्नेह स्वरूप अंतरात्मा की ओर ले चलें और इन्हें शाश्वत प्रेम के सागर परमात्मा के साथ जोड़ें...

मूल रूप में हम आत्मा हैं। प्रेम स्वरूप हैं। इस सत्य स्वरूप या आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम असीम प्रेम व स्नेह की ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। प्राणी, प्रकृति और पूरी सृष्टि के साथ अपने संबंधों को हम मधुर व स्नेहसंपन्न बना सकते हैं। आवश्यकता यह है कि हम शाश्वत प्रेम के अर्थ को जानें, उसकी परिभाषा समझें तथा अपनी दृष्टि, वृत्ति, रुचि, स्नेह और श्रद्धा को बाह्य तत्वों से आत्मिक सत्यों की ओर मोड़ें अर्थात अपने मन, बुद्धि एवं भावनाओं को निर्मल स्नेह स्वरूप अंतरात्मा की ओर ले चलें और इन्हें शाश्वत प्रेम के सागर परमात्मा के साथ जोड़ें। इस आत्म-परमात्म योग के बाद हमें प्रेम की भावनाओं को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पूरा जीवन ही प्रेममय हो जाएगा।

वस्तुतः हम अपने आप में प्रेम ही हैं और हमारा सत्य स्वरूप और स्वाभाविक स्वभाव भी प्रेम ही है। लेकिन, हमारे अंदर का असुरक्षा भाव, दूसरों के प्रति दोष-दृष्टि, क्रोध, प्रतिस्पर्धा, अपमान या आहत होने की भावनाएं हमारे असीम प्रेम के निर्मल प्रवाह को बाधित कर देती हैं। अंदर का व्यर्थ, अस्वस्थ एवं नकारात्मक सोच स्नेह की कोमल भावनाओं का दमन कर देता है। प्रेम के स्वच्छ और शाश्वत स्रोत में अवरोध उत्पन्न करता है।

आज सच्चा प्रेम पाने या अनुभव करने के लिए हम किसी अन्य पर आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि आत्मिक स्नेह का मूल अंतरात्मा से तथा प्रेम के शाश्वत स्रोत परमात्मा से हमारे मन, बुद्धि व भावनाओं का नाता टूट गया है। इसलिए अगर हम अपने से या दूसरों से अहैतुक प्रेम पाना चाहते हैं, तो हमें भी उन्हें बिना किसी शर्त प्यार देना होगा। इसके लिए हमें अपने सत्य स्वरूप को जानना होगा, साथ ही दूसरों की भावनाओं और अपेक्षाओं को भी महसूस करना होगा। अक्सर प्रेम को कुछ नकारात्मक संवेदनाओं, जैसे-मोह, अपेक्षा, चिंता, तनाव, भय या क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो ठीक नहीं है। मोह या आसक्ति हमें शक्तिहीन करता है, जबकि सच्चा प्रेम शक्तिशाली बनाता है।

वर्तमान में संबंधों में टकराव का मूल कारण लोगों का दृष्टिकोण एवं भौतिकवादी मानसिकता है, जिसके कारण कुछ जगह जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, प्रांत आदि के आधार पर भेदभाव और अनैतिक आचरण होता है। ऐसे वातावरण को जीवन अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इस बदलाव की प्रक्रिया में सर्वप्रथम मानवीय सोच, विचार, भावना, दृष्टि, वृत्ति, कर्म, व्यवहार, संस्कार और संबंधों में सुधार लाने की आवश्यकता है। इस सुधार की आधारशिला के रूप में जीवन में सत्यबोध, आत्मबोध व आत्मिक प्रेम की आवश्यकता है।

पूरी मानवता आज क्षणभंगुर इंद्रियभोग और दैहिक प्रेम से ऊब चुकी है। मानव को आत्मिक प्रेम व सहयोग की आवश्यकता है। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान-अध्यास की प्रक्रिया से हम सही सोचने, समझने, परखने और निर्णय लेने की आंतरिक शक्ति विकसित कर पाएंगे। इस आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं, जैसे हैं, उनको हम बिना किसी शर्त, बिना किसी तुलना या अपेक्षा के सहज ही स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में समाज के प्रति हम अपने अहैतुक प्रेम को प्रकट व संचारित कर सकते हैं। हमें ईश्वर के समान प्रेम-स्वरूप की मनोस्थिति में रहना होगा, तब हमारी दृष्टि में संपूर्ण जगत सुखदाई, भावपूर्ण व प्रेममय हो जाएगा।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

आध्यात्मिक ज्ञान से जागता है प्रेम

सच्चा प्रेम कोई बाहरी स्थूल वस्तु नहीं है, जिसे जब चाहे खरीदा या बेचा जा सके या उपयोग कर त्याग किया जा सके। सच्चा प्रेम तो हमारी अपनी प्रकृति के रूप में हमारे अंदर निहित है। उसे मात्र आध्यात्मिक ज्ञान और योग बल से जगाने की देरी है। निश्छल प्रेम वास्तव में स्वयं और सबके प्रति समानतापूर्वक आत्मिक स्नेह, दया, करुणा, सहानुभूति और संवेदनशीलता भरी शुभभावना व शुभकामनाओं से प्रस्तुत होने की सहज, सरल और पवित्र मानसिकता है। शाश्वत प्रेम तो स्वयं को तथा औरों को बिना किसी शर्त या पूर्वाग्रह के समझने, समझाने, सहने, स्वीकारने एवं सराहने की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है।

चिंतन धरोहर

स्वामी रामकृष्ण परमहंस

बनें ईश्वर का दास

अहंकार दो प्रकार का होता है। एक है पक्का 'मैं' और दूसरा कच्चा 'मैं'। 'जो कुछ भी है, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है। यह शरीर भी मेरा नहीं है। मैं नित्यमुक्त हूं, मैं ज्ञानस्वरूप हूं।' यह पक्का 'मैं' है। 'मैं प्रभु का दास हूं'-यह विद्या का 'मैं' है, जिसे पक्का 'मैं' कहा जाता है। 'यह मेरा लड़का है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा शरीर है' यह कच्चा मैं है। जो 'मैं' मनुष्य को संसारी बनाता है, कामिनी-कांचन में आबद्ध करता है, वह कच्चा 'मैं' है। जीव और ब्रह्म में भेद बस इसलिए है कि उनके बीच में यह 'मैं' खड़ा हुआ है। पानी पर एक लाठी डाल दी जाए तो पानी दो भागों में बंटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। 'अहंकार' या 'मैं' ही यह लाठी है, इसे उठा लो तो जल एक ही रह जाएगा।

'मैं' को दूर करना कठिन है। इस कारण अपने 'मैं' से यह कहना चाहिए कि तू ईश्वर का दास बनकर रह। मैं ईश्वर का दास हूं, भक्त हूं- ऐसे भाव में रहो, तो दोष नहीं। यह पक्का 'मैं' भक्तिपथ पर आगे बढ़ने का सूचक है। इसके द्वारा ईश्वर लाभ होता है। ईश्वर प्राप्ति के पश्चात 'दास मैं' या 'भक्त मैं' किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर को छूने पर तलवार सोना बन जाती है, तलवार का आकार तो रहता है, पर वह किसी को हत नहीं कर सकती।

अगले मंगलवार को पढ़ें श्री श्री रविशंकर का चिंतन

सप्ताह के व्रत त्योहार

30 अप्रैल, मंगलवार : श्री गुरु अर्जुनदेव जयंती
एक मई, बुधवार : शीतलाष्टमी व्रत
चार मई, शनिवार : श्री वल्लभाचार्य जयंती,
पांच मई, रविवार : प्रदोष व्रत।

वर्ग पहेली-2616

बाएं से दाएं
5 सुगंधित, खुशबूदार (3) । 6 आनंद, दशा (3) । 7 दुर्दशा, आफत (3) । 9 नमकीन, लवण-संबंधी (4) । 11 आधा कच्चा (4) । 13 बिना नाम वाला, जिसे कोई नहीं जानता हो (3) । 14 उदाहरण, मिसाल (3) । 16 बैलगाड़ी, छकड़ा (3) । 19 गबन, [illegible] (3) । 21 शरीर पर मलने योग्य लेप (4) । 23 कहने योग्य (4) । 25 किसी प्रिय के अलगाने का संताप (3) । 26 सुर, भगवान (3) । 27 पंकज, सरोज, अरविंद (3) ।

ऊपर से नीचे
1 झूठा दोष, कोसना, शाप (4) । 2 झटपट, जल्दी, शीघ्र (3) । 3 समझाना-बुझाना (4) । 4 सुनना (3) । 8 रहने का घर (3) । 10 उल्टी, कै (3) । 12 [illegible] (3) । 15 सहसा, [illegible] (3) । 17 शाखा, डाली (3) । 18 किसी काम को करने का सुंदर ढंग, सलीका (3) । 20 गीत-गोविंद के रचनाकार (4) । 22 भ्रष्ट होना, भटकन (4) । 24 तमाचा, चांटा, चमेटा (3) । 25 विस्तार, फैलाव, समूह (3) ।

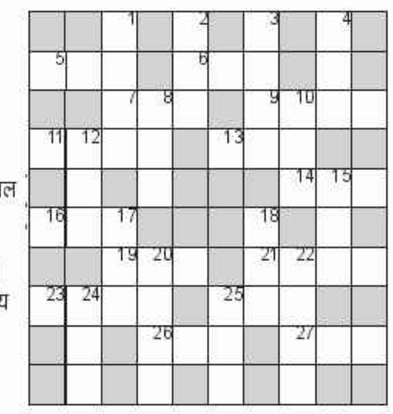

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

जागरण सुडोकू-2616

	9			8			7	
		6		3			2	
7	3		6		5	8		9
	8							2
2			8		1		9	
		1			4			6
6				7			3	
	7	9		4		2		8
4							5	

कल का हल

1	8	5	9	3	7	4	6	2
4	2	7	6	5	8	1	9	3
9	6	3	2	4	1	7	5	8
3	1	2	7	8	4	5	9	6
8	5	9	3	1	6	2	7	4
7	4	6	5	2	9	3	8	1
6	7	4	8	9	2	1	3	5
2	3	8	1	7	5	6	4	9
5	9	1	4	6	3	8	2	7

आज का भविष्यफल- 30 अप्रैल, 2024 मंगलवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: वैशाख मास कृष्णपक्ष षष्ठी। आज का राहुकाल: अपराह्न 03 बजकर से 04 बजकर 30 मिनट तक। आज का दिशाशूल: उत्तर। आज की भद्रा: प्रातः 07 बजकर 06 मिनट से सायं 06 बजकर 26 मिनट तक।

कल 01 मई, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल: उत्तर।
कल का पर्व एवं त्योहार: शीतलाष्टमी।
विशेष: अष्टमी तिथि क्षय, गुरु वृषराशि में एवं श्रमिक दिवस।
विक्रम संवत 2081 शके 1946 उत्तरायण, उत्तरगोल, वसंत ऋतु, वैशाख मास कृष्णपक्ष की सप्तमी तत्पश्चात अष्टमी, श्रवण नक्षत्र तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र, शुभ योग तत्पश्चात शुक्ल योग, मकर में चंद्रमा।

मेष: गुरु का परिवर्तन और शुक्र का अस्त होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
वृष: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
मिथुन: गुरु व्यय भाव में है। पारिवारिक मामलों में समस्याएं देंगे।
कर्क: मांगलिक योजना साकार होगी, लेकिन निजी सुख में व्यवधान आएगा।
सिंह: पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
कन्या: आर्थिक मामलों में सफलता देगा। निजी सुख में वृद्धि कराएगा।
तुला: स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। अध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी।
वृश्चिक: दांपत्य जीवन में चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा।
धनु: रोग और विरोधी तनाव देंगे। कार्य क्षेत्र में व्यवधान मिल सकता है।
मकर: गुरु का परिवर्तन संतान की प्रगति में सहायक होगा।
कुंभ: निजी सुख व संपत्ति में वृद्धि। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
मीन: पुरुषार्थ सार्थक होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।

दर्शन परंपरा

डा. चिन्मय पण्ड्या
प्रतिकुलपति, देवसंस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य

महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का अवतरण उनके पूर्वजों द्वारा पांच पीढ़ियों तक सौ सोमयज्ञ पूर्ण करने के उपरांत हुआ था। उनका जन्म विक्रम संवत 1535 में दक्षिण के उत्तरादि (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर) में तैलंग ब्राह्मण परिवार में पिता लक्ष्मण भट्ट और माता श्रीइलम्मा के घर द्वितीय पुत्र के रूप में हुआ। भागवत प्रेमियों और सुसंस्कारित परिवार में बचपन बीता और उन्होंने काशी के प्रकांड विद्वान माधवेंद्र पुरी से वेद-शास्त्र का अध्ययन मात्र 11 वर्ष की आयु में कर लिया।

वेदांत के संप्रदायों में वल्लभ संप्रदाय अपनी अलग विशेषता रखता है। वल्लभाचार्य जी ने विशेष सिद्धांतों की नींव पर वैष्णव संप्रदाय का भवन खड़ा किया। उन्होंने वेदांत सूत्रों को लेकर अणुभाष्य किया और श्रीमद्भगवद्गीता को लेकर सुबोधिनी तथा अनेक ग्रंथों व सूत्रों की रचना कर शुद्धाद्वैत के सिद्धांतों की व्याख्या की। भक्ति संप्रदाय में इसे पुष्टिमार्ग के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि प्रभु की भक्ति तब पूरी होती है, जब साधक का तन, मन और हृदय उनमें समर्पित हो अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु की भक्ति करने से ही ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है।

श्री वल्लभाचार्य ने वृंदावन में रहकर भगवान श्रीकृष्ण के बालस्वरूप की प्रेममयी आराधना की। इनकी अष्टयाम सेवा बड़ी ही सुंदर है। इसमें माधुर्यभाव है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए वल्लभाचार्य जी ने भगवान श्रीकृष्ण की वात्सल्य भाव से उपासना की। वल्लभाचार्य जी की भक्ति और व्यक्तित्व का लोगों पर इतना विलक्षण प्रभाव पड़ा कि अनेकानेक लोग श्रीकृष्ण के बालस्वरूप के प्रेमी बन गए। उन्होंने भक्तिकाल के कवि सूरदास जी को प्रभु की लीलाओं से परिचित करवाया और लीलागान हेतु प्रेरित किया, जिसके कारण आज हम लीलाधर श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से परिचित हैं। वल्लभाचार्य जी ने अनेक भाष्य, ग्रंथ, नामावलियां, स्तोत्र आदि की रचना की। उनकी प्रमुख 16 रचनाओं को षोडश ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इनके नाम हैं-यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह-मर्यादा भेद, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न स्तोत्र, अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्याश्रय, श्रीकृष्णाश्रय, चतुश्लोकी, भक्तिवर्धिनी, जलभेद, पंचपद्यानि, संन्यास निर्णय, निरोध लक्षण, सेवाफल।

चार मई को है श्री वल्लभाचार्य की जयंती

भारत में भक्ति की अविरल धारा शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, आचार्य निंबार्क और वल्लभाचार्य से लेकर अब तक बहती चली आ रही है। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के वह आधार स्तंभ हैं, जिन्होंने साधना के लिए पुष्टिमार्ग से परिचित करवाया, जिन्होंने सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज बनाया। पुष्टिमार्ग के इस प्रवर्तक ने संपूर्ण समाज को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और मानव जीवन को प्रभु की शरण में लीन करने के लिए मार्गदर्शन किया। वर्तमान समय में जिस तरह मानव में वैचारिक दुष्प्रवृत्तियां पनपी हैं, इसका एकमात्र कारण ईश्वर के बनाए आदर्शों से विमुख होना है।

राष्ट्रीय फलक

मोदी को दुआ दूंगी, क्योंकि उनके कारण हज यात्रा पर जा पा रही हूं : शहनवाज बेगम

हज यात्रा पर जाने वाली अकेली महिलाओं के लिए हज मंजिल में चल रहे प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं के सवालों का जवाब देती दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौशर जहां। चंद्र प्रकाश मिश्र

नेमिष हेमंत ● जागरण

- बिना मेहरम के हज यात्रा पर उड़ान भरेंगी करीब 4300 महिलाएं
- हज मंजिल में महिलाओं को दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण

नई दिल्ली: दिल्ली के एक स्कूल में टीचर हुमा अपनी सास शहनवाज बेगम के लिए डायरी में आवश्यक बातें नोट कर रही हैं। साथ-साथ उन्हें समझा भी रही हैं कि हज यात्रा के दौरान हवाई उड़ान से लेकर सऊदी अरब तक में उन्हें किन-किन बातों का ख्याल रखना है। जबकि, शहनवाज बेगम के चेहरे पर चिंता से अधिक संतुष्टि और खुशी का भाव है। क्योंकि, हज यात्रा पर जाने की उनकी कामना पूर्ण होने वाली है। वह उन 4,300 महिलाओं में शामिल हैं, जो बिना मेहरम (करीबी पुरुष स्वजन) के हज के लिए उड़ान भरेंगी, जो बिना किसी करीबी पारिवारिक सदस्य के हजारों किमी दूर 40 दिन घर से बाहर रहेंगी।

वर्ष 2018 में मोदी सरकार ने महिलाओं की हज यात्रा पर मेहरम की पाबंदी को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इसके बाद इस वर्ष सर्वाधिक 4,300 महिलाएं रवाना होंगी। पिछले वर्ष पूरे देश से करीब 4,000 महिलाएं गईं थीं। इस समूह की अधिकतर महिलाएं बुजुर्ग, विधवा और कम पढ़ी-लिखी हैं। साथ ही उम्र के साथ शरीर में होने वाली परेशानी साथ है, लेकिन यात्रा को लेकर उनका जज्बा व उत्साह देखते ही बन रहा है। क्योंकि, यह एक ऐसी यात्रा है, जिसका इंतजार हर मुस्लिम को पूरी जिंदगी रहता है और खास कर उन जैसी अकेली महिलाओं के लिए, जो अब संभव हो गया है।

शहनवाज कहती हैं कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चलते ही संभव हुआ है। अन्यथा, उनकी हज पर जाने की साध उनकी मौत के साथ दफन हो जाती। वह कहती हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री पर मुस्लिम समाज को लेकर क्या-क्या आरोप लगाए जाते हैं। उनकी बहु हुमा के अनुसार, तीन तलाक व बिना मेहरम के हज यात्रा जैसे कई ऐसे अहम बदलाव हैं, जिसने मुस्लिम महिलाओं के जीवन में प्रत्यक्ष सकारात्मक बदलाव लाया है, जो दिख रहा है। सभी महिलाओं को तुर्कमान गेट स्थित हज मंजिल में विशेष शिविर में यात्रा संबंधित आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं, जिसमें दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां महिलाओं तथा उनके स्वजन को आश्वस्त करती हैं कि यात्रा में हर तरह की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के साथ उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।

> मोदी सरकार से बहुत खुश हूं, क्योंकि उन्होंने हम जैसी महिलाओं का जो अकेली हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा।
> - अनवरी बेगम, इंद्रलोक

> मेरे पति की मौत हो चुकी है। बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब बहुत खुशी है, मन करता है उड़ कर पहुंच जाऊं।
> - शरबती, पूर्वी दिल्ली

सात वर्षों का खानपान ठेका लेंगी कंपनियां, बेस किचन भी बनाएंगी

निशांत यादव ● जागरण

लखनऊ : पिछले दिनों यशवंतपुर-गोरखपुर सुपरफास्ट ट्रेन में रसोई यान न होने की कीमत कई यात्रियों को चुकानी पड़ी। अवैध वेंडरों ने ट्रेन में अंडा करी व अंडा बिरयानी बेची, जिससे तमाम यात्री बीमार हो गए। अब ट्रेनों में अवैध वेंडिंग रोकने व यात्रियों को अच्छा खाना उपलब्ध कराने के लिए रेलवे बोर्ड नई खानपान नीति लागू करने जा रहा है। अब ट्रेनों के रसोई यान का लाइसेंस कंपनियों को सात वर्षों के लिए मिलेगा। इससे कंपनियां अपना बेस किचन भी तैयार करेंगी। जून में चुनाव आचार संहिता हटते ही रसोई यान के लाइसेंस नए नियम के तहत देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

रेलवे में यात्रियों को खानपान सुविधा उपलब्ध कराने की दो तरह की विभागीय व्यवस्था लागू हैं। शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस सहित प्रीमियम ट्रेनों में किराये के साथ ही खानपान चार्ज यात्रियों से जमा कराया जाता है। यह खानपान की प्रीपेड व्यवस्था है। इसके अलावा आइआरसीटीसी के वेंडर चलती ट्रेन में यात्रियों को खाना उपलब्ध कराने के बाद उनसे उसकी कीमत लेते हैं। यह पोस्टपेड सुविधा है। प्रीमियम ट्रेनों का प्रीपेड खाना तो कुछ ठीक भी है, लेकिन शिकायत पोस्टपेड सुविधा वाली ट्रेनों में आ रही हैं। इसके पीछे रेलवे की खानपान नीति की कमी एक मुख्य कारण है। अभी तीन-तीन माह का लाइसेंस वेंडरों को दिया जा रहा है। रेलवे की वर्ष 2017 की खानपान नीति में बेस किचन बनाने का प्रविधान किया गया था, लेकिन लीज पालिसी की बाधा के कारण बेस किचन के लिए जगह का आवंटन फंस गया। **अब होंगे ये बदलाव :** ट्रेनों में खानपान का लाइसेंस लेने वाली कंपनियों को सात वर्ष का ठेका मिला तो ये कंपनियां निवेश भी करेंगी। इन कंपनियों को बड़े रेलवे स्टेशनों के परिसर या उस शहर में आइआरसीटीसी के तय मानकों के तहत खाना तैयार करना होगा। बेस किचन से ही तैयार खाना प्रीमियम और अन्य ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगा।

समिति ने की थी सिफारिश : संसद की लोक लेखा समिति ने इस वर्ष फरवरी में भारतीय रेलवे ने खानपान सेवा नाम से अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2005, 2010 और 2017 में खानपान नीति में हुए बदलाव के कारण ट्रेनों के खानपान में सुधार नहीं हो सका है।

भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए रेलवे बोर्ड ने शुरू की बदलाव की प्रक्रिया। फाइल

> रेलवे यात्रियों को अब बेस किचन से तैयार खाना मिलेगा। यह बेस किचन खानपान का लाइसेंस लेने वाली कंपनियां बनाएंगी। रेलवे बोर्ड स्तर पर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।
> - अजीत कुमार सिन्हा, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, आइआरसीटीसी

अंतरिक्ष मलबे से बचाने को चार सेकेंड की देरी से लांच किया था चंद्रयान-3

नई दिल्ली, प्रेट्र : चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े से बचाने के लिए इसकी लांचिंग में चार सेकेंड की देरी की गई थी। विज्ञानियों ने सूझबूझ दिखाते हुए चार सेकेंड की देरी नहीं की होती तो चंद्रयान-3 अंतरिक्ष मलबे से टकराकर नष्ट हो सकता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा कि टकराव की आशंका से बचने के लिए यह देरी आवश्यक थी। चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण में महज चार सेकेंड की देरी से चंद्रयान-3 ने टकराव के खतरे के बिना चंद्रमा की यात्रा को बिना बाधा पूरा किया। इंडियन सिचुएशनल स्पेस अवेयरनेस रिपोर्ट (आइएसएसएआर) के अनुसार चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को ले जाने वाले राकेट की लांचिंग में चार सेकंड की देरी टक्कर संबंधी आकलन के आधार पर की गई।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार 60 से अधिक वर्षों की अंतरिक्ष गतिविधियों के कारण लगभग 56,450 मलबों को कक्षा में ट्रैक किया गया है, जिनमें से लगभग 28,160 अंतरिक्ष में हैं। यूएस स्पेस सर्विलांस नेटवर्क (यूएसएसएसएन) द्वारा इन्हें नियमित रूप से ट्रैक किया जाता है। बता दें कि चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लांच किया गया था। 23 अगस्त, 2023 को, भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की साफ्ट लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर साफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। आइएसएसएआर-2023 की रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष मलबे से टकराव से बचने के लिए इसरो को पिछले साल सिंगापुर के डीएस-एसएआर उपग्रह के प्रक्षेपण में एक मिनट की देरी करनी पड़ी थी।

चंद्रयान-3। फाइल फोटो

छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित 'ग्रीन नोबल' पुरस्कार

- हसदेव अरण्य को बचाने के लिए किया था आंदोलन का नेतृत्व
- दुनियाभर के छह अन्य लोगों को भी प्रदान किया गया सम्मान

नई दिल्ली, प्रेट्र : छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद् आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रीन नोबल के नाम से विख्यात प्रतिष्ठित पुरस्कार से इस साल आलोक समेत दुनियाभर के सात लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। आलोक ने छत्तीसगढ़ में 21 प्रस्तावित कोयला खदानों से जैव विविधता से समृद्ध 4.45 लाख एकड़ जंगल को बचाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था।

657 वर्ग मील में फैले घने और जैव विविधता वाले हसदेव अरण्य वन भारत के सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से एक हैं। इस वन क्षेत्र में 25 लुप्तप्राय प्रजातियों, 92 पक्षी प्रजातियों और 167 दुर्लभ और औषधीय पौधों की प्रजातियां है। इसके साथ ही तकरीबन 15 हजार आदिवासी अपनी आजीविका, सांस्कृतिक पहचान और भरण-पोषण के लिए हसदेव अरण्य के जंगलों पर निर्भर हैं। हालांकि जंगल में कोयले के अकूत भंडार के मद्देनजर सरकार ने यहां 21 कोयला खदानों को प्रस्तावित करते हुए क्षेत्र में जाना प्रतिबंधित कर दिया। इस पर अंकित ने 2012 में हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर ग्रामीणों के साथ आंदोलन शुरू कर दिया। अंकित व ग्रामीणो के आंदोलन के कारण सरकार को वन क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदानों की नीलामी को जुलाई 2022 में रद करना पड़ा था। **पुरस्कार के लिए ये भी किए गए चयनित :** एपी के अनुसार, इस साल के ग्रीन नोबल पुरस्कार के लिए स्पेन की टेरेसा विसेंट, ब्राजील के मार्सेल गोम्स, आस्ट्रेलिया के मुर्रवाह मारूची जानसन, कैलिफार्निया की एंड्रिया विडौरे, दक्षिण अफ्रीका के नानहले मबुथुमा व सिनेगुगु जुकुलु का भी चयन किया गया है।

पर्यावरणविद् आलोक शुक्ला। नईदुनिया आर्काइव

खाती गांव में पर्यटकों के लिए खुलेगा इंटरप्रिटेशन सेंटर

पिंडारी ग्लेशियर ट्रेकिंग

घनश्याम जोशी ● जागरण

- ट्रेकिंग पर आने वाले पर्यटकों को मिलेगी सुविधा, आपात स्थिति में त्वरित मदद भी

बागेश्वर : उच्च हिमालयी क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग बागेश्वर जिले के प्रथम हिमालयी गांव खाती में इंटरप्रिटेशन सेंटर खोलने जा रहा है। पिंडारी, सुंदरढूंगा और कफनी ग्लेशियर की ट्रेकिंग पर आने वाले पर्यटकों को सेंटर से हर तरह की जानकारी मिलेगी। साथ ही आपात स्थिति में यहां से त्वरित मदद भी उन तक विभाग पहुंचाएगा। बागेश्वर जिले में एडवेंचर टूरिज्म के हिसाब से प्रसिद्ध ग्लेशियर और सुंदर बुग्याल (घास के मैदान) हैं। 15 अप्रैल से पिंडारी, कफनी ग्लेशियर व सुंदरढूंगा बुग्याल की साहसिक यात्रा प्रारंभ हो गई है। इस बार पर्यटन विभाग देश-विदेश से आने वाले ट्रेकरों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए खाती गांव में इंटरप्रिटेशन सेंटर खोल रहा है। जहां से पर्यटकों को हिमालय के रहन-सहन, खान-पान, जैव विविधता, हिमालयी वन्यजीव, ट्रेकिंग रूट, ग्लेशियरों की भौगोलिक स्थिति की सभी जानकारी मिल सकेगी। उच्च हिमालय क्षेत्र में मौसम प्रतिकूल रहने या किसी अन्य आपात स्थिति में फंसने पर पर्यटक सेंटर से संपर्क भी कर सकेंगे। सेंटर में प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात रहेंगे। पिंडारी, कफनी तथा सुंदरढूंगा जाने वाले साहसिक पर्यटक सेंटर पर रुकेंगे। यहां उन्हें हिमालय में ट्रेकिंग करने के लिए जरूरी प्रशिक्षण व जानकारी दी जाएगी। इसके बाद वे आगे की यात्रा कर सकेंगे।

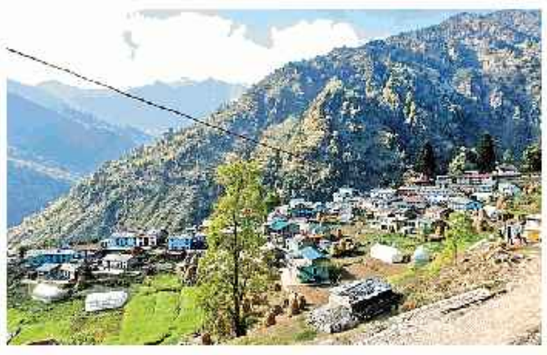

आचार संहिता के बाद प्रभावी होगी व्यवस्था : पर्यटन विभाग को अपना इंटरप्रिटेशन सेंटर खोलने के लिए खाती गांव में भूमि उपलब्ध हो गई है। फिलहाल विभाग किराए के भवन में सेंटर चलाएगा। साहसिक पर्यटन के लिए 15 अप्रैल से 15 जून तथा 15 सितंबर से 15 नवंबर तक ग्लेशियरों की ट्रेकिंग होती है।

अप्रैल में सात दल पहुंचे पिंडारी : 15 अप्रैल के बाद से अब तक सात दल पिंडारी ग्लेशियर पहुंचे हैं। इनमें से छह दल वापस लौट आए हैं। इससे होम स्टे संचालकों, गाइड व पोर्टरों को भी काम मिलने लगा है। जिले में 25 हजार देशी व 190 विदेशी पर्यटक पहुंच चुके हैं।

खाती गांव में इंटरप्रिटेशन सेंटर खोलने की तैयारी है। जागरण

> ग्लेशियरों की ट्रेकिंग पर जाने वाले पर्यटकों के लिए खाती में इंटरप्रिटेशन सेंटर खोला जा रहा है। पर्यटकों के लिए यह सेंटर सुविधा व मदद प्रदान करने वाला होगा।
> - पीके गौतम, जिला पर्यटन अधिकारी

****

दैनिक जागरण
राष्ट्रीय संस्करण
मंगलवार 30 अप्रैल, 2024
आजकल
14
www.jagran.com

दृष्टिबाधित पायलट ने विमान से आधी दुनिया का चक्कर पूरा किया

2007 में आज ही दृष्टिबाधित ब्रिटिश पायलट माइल्स हिल्टन ने एक माइक्रोलाइट विमान से आधी दुनिया का चक्कर पूरा किया था। उन्होंने सात मार्च को लंदन से अपनी यात्रा शुरू की थी। नेविगेशन बताने वाली आडियो डिवाइस की मदद से हिल्टन ने 13,500 मील की दूरी तय की।

अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में जार्ज वाशिंगटन ने ली शपथ

1789 में आज ही न्यूयार्क में जार्ज वाशिंगटन ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वह 1797 तक इस पद पर बने रहे। कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। जार्ज वाशिंगटन ने ही देश की पहली टकसाल की स्थापना कर डालर को मुद्रा की मान्यता दी थी।

संपत्ति बेच दादा साहेब फाल्के ने सीखा था फिल्म निर्माण

भारतीय सिनेमा के जनक माने जाने वाले निर्माता-निर्देशक दादा साहेब फाल्के का जन्म 1870 में आज ही के दिन नासिक में हुआ था। अपना करियर एक फोटोग्राफर के रूप में शुरू किया। 1910 में मूक फिल्म द लाइफ आफ क्राइस्ट देखने के बाद फिल्म बनाने की ठानी। फिर अपनी सारी संपत्ति बेच कर फिल्म निर्माण और सिनेमैटोग्राफी सीखने इंग्लैंड चले गए। 1913 में उन्होंने भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर में उन्होंने पहली बार किसी अभिनेत्री को मौका दिया।

सूर्य के पीछे छिपने जा रहा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति

खगोलीय घटना ▶ 12 वर्ष में बनता है युति का योग, 18 मई से चार सप्ताह तक नजर नहीं आएगा यह ग्रह

रमेश चंद्रा, नैनीताल

हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति (जुपिटर) सूर्य के पीछे छिपने जा रहा है। 18 मई को होने जा रही युति यानी कंजक्शन की इस खगोलीय घटना के दौरान बृहस्पति करीब चार सप्ताह तक यह पृथ्वी से नजर नहीं आने वाला है। इस अवधि में बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर भी रहेगा।

नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के खगोल विज्ञानी डा. शशिभूषण पांडेय के अनुसार बृहस्पति अपने पथ पर अब सूर्य के करीब से गुजरने जा रहा है। इस दौरान बृहस्पति की कक्षा पृथ्वी से सौर मंडल के सुदूर हिस्से में होगी, जो कि सूर्य के बिलकुल पीछे होगी। जिस कारण पृथ्वी से बृहस्पति नजर ही नहीं आएगा। इसके साथ-साथ वह सूर्य के नजदीक होने के कारण उसकी रोशनी में भी खोया रहेगा। यह स्थिति 18 मई से शुरू होकर करीब चार सप्ताह तक रहेगी और बृहस्पति हमारी नजरों से ओझल रहेगा। बृहस्पति पृथ्वी से सर्वाधिक दूर और सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच जाएगा।

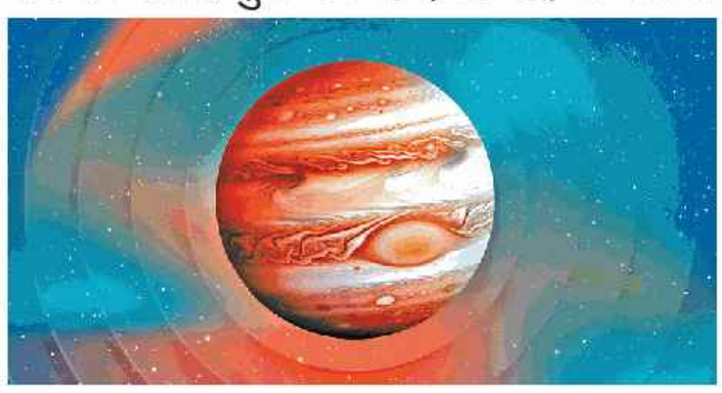

नासा की अंतरिक्ष दूरबीन हबल से ली गई बृहस्पति की तस्वीर। सौ. इंटरनेट मीडिया।

सूर्य व बृहस्पति के बीच आभासीय दूरी मात्र 0.43 डिग्री रह जाएगी। इसी समय बृहस्पति व पृथ्वी की दूरी 6.03 एयू (खगोलीय इकाई) हो जाएगी। एक खगोलीय इकाई 15 करोड़ किमी की होती है। अत्यधिक दूरी के कारण बृहस्पति पृथ्वी से बहुत छोटा व धुंधला नजर आएगा। डा. शशिभूषण पांडेय के अनुसार बृहस्पति व सूर्य की युति यानी कंजक्शन लगभग 12 वर्ष में एक बार होती है। क्योंकि बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। यह गैसीय ग्रह आसमान में नग्न आंखों से देखा जा सकता है।

तारा बनते-बनते रह गया बृहस्पति, गैसीय ग्रह बन रहा गया

नैनीताल: डा शशिभूषण पांडेय के अनुसार हमारे सौर परिवार का पांचवा ग्रह बृहस्पति तारा बनते बनते रह गया और एक गैसीय ग्रह बनकर सूर्य की परिक्रमा करने लगा। कुछ विज्ञानी इसे असफल तारा मानते हैं। दअरसल यह सूर्य की तरह हाइड्रेजन और हीलियम से बना है और ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसके तारा बनने को लेकर कयास अभी भी लगाए जाते हैं, लेकिन यह आसान नही लगता।

बृहस्पति में एक विशाल तूफान सदियों से चला आ रहा है। इस तूफान को ग्रेट रेड स्पॉट नाम दिया गया है। यह पृथ्वी से भी बड़ा है और करीब 16500 किमी चौड़े आकार में फैला हुआ है। बृहस्पति की एक खासियत है कि वह अपनी संरचना के कारण पृथ्वी की रक्षा भी करता है। पृथ्वी की ओर आने वाले कई क्षुद्रग्रहों को गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर खींच लेता है। बृहस्पति आजभी कई रहस्यों से घिरा हुआ है। जिन्हें उजागर करने के लिए नासा का अंतरिक्ष यान जूनो कई बार इसके करीब पहुचकर टोह ले चुका है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से बढ़ती तकनीक के चलते विज्ञानियों को उम्मीद है कि इस ग्रह के राज अधिक समय तक रहस्य नही रहेंगे।

बच्चों को रुलाया जाता है जापान में

जापान में बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य एवं उन्हें बुरी आत्माओं से दूर रखने के लिए प्रतिवर्ष बेबी क्राइंग प्रतियोगिता होती है। इसमें नवजात बच्चों को सूमो पहलवानों को सौंप दिया जाता है और रेफरी उन्हें रुलाने के लिए तेज आवाजें निकालता है। ऐसा करने पर जो बच्चे जोर-जोर से रोने लगते हैं, तो माना जाता है कि उनका स्वास्थ्य उत्तम होगा। राजधानी टोक्यो के सेंसोजी मंदिर में बच्चों को रुलाने की कोशिश करते सूमो पहलवान एवं रेफरी। रायटर

इधर-उधर की

बिल्ली की वजह से लगी 11 लाख रुपये की चपत

बीजिंग, एजेंसी: कुत्ते-बिल्ली जैसे पालतू जानवर के कारण् थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करवा सकती है। चीन के सिचुआन प्रांत की डांडन के साथ ऐसा ही हुआ। डांडन अपनी पालतू बिल्ली को घर पर छोड़कर काम से बाहर गई थीं। कुछ देर बाद उन्हें फोन आया कि उनके फ्लैट में आग लग गई है। फ्लैट पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि आग के पीछे बिल्ली जिम्मेदार है। दरअसल किचन में खेलते-खेलते बिल्ली ने पैर से इंडक्शन कुकर चालू कर दिया था जिससे आग लग गई। अग्निशमन कर्मियों ने बताया कि उन्हें बिल्ली कैबिनेट में छिपी मिली थी। इससे डांडन को 14 हजार डालर यानी करीब 11 लाख रुपये का नुकसान हो गया।

इंडक्शन कुकर चालू कर बिल्ली ने लगा दी आग। इंटरनेट मीडिया

टायरानोसारस टी रेक्स डायनासोर बंदर जितने बुद्धिमान नहीं थे

नई दिल्ली, प्रेट्र : टायरानोसारस रेक्स डायनासोर को लेकर एक शोध में दावा किया गया है कि ये बंदर जितने बुद्धिमान नहीं थे। हालांकि, इससे पहले जनवरी 2023 में प्रकाशित अध्ययन में अमेरिका के वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय की न्यूरोसाइंटिस्ट सुजाना हरकुलानो-हौजेल ने कहा था कि थेरोपोड डायनासोर (इनकी एक प्रजाति टी. रेक्स है) के दिमाग में बंदरों और बबून के दिमाग के बराबर न्यूरान थे।

- नए शोध में विज्ञानियों के सामने पहले से उलट परिणाम सामने आए हैं
- रेक्स डायनसोर सरीसृपों की तरह व्यवहार करते थे

रेक्स डायनासोर। फाइल

नए शोध में विज्ञानियों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने टी. रेक्स सहित डायनासोरों के मस्तिष्क की फिर से जांच की और पाया कि वे सरीसृपों की तरह व्यवहार करते थे। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के स्कूल आफ बायोलाजिकल साइंसेज के अध्ययनकर्ता डेरेन नाइश के अनुसार वे एक बुद्धिमान विशाल मगरमच्छ की तरह थे। टीम ने पाया कि न्यूरान गिनती के साथ-साथ डायनासोर के मस्तिष्क के आकार को भी अधिक अनुमानित किया गया था और दिखाया गया था कि न्यूरान गिनती अनुमानों के आधार पर किसी प्रजाति की बुद्धि का आकलन करना विश्वसनीय नहीं है। यह निष्कर्ष द एनाटोमिकल रिकार्ड जर्नल में प्रकाशित हुए हैं।

स्पेन के विज्ञानी ओरनेला बर्ट्रैंड ने कहा कि बुद्धिमता का सही-सही अनुमान लगाने के लिए न्यूरान की गणना सही नहीं है। खासकर लंबे समय से विलुप्त प्रजातियों में बुद्धिमत्ता की भविष्यवाणी करने के लिए उनका उपयोग करने से अत्यधिक भ्रामक व्याख्याएं हो सकती हैं। लेखकों ने कहा कि यह शोध दशकों के विश्लेषण की तर्ज पर चलता है, जिसमें जीवाश्म विज्ञानियों और जीवविज्ञानियों ने डायनासोर के मस्तिष्क के आकार और शरीर रचना की जांच की है और व्यवहार और जीवनशैली का अनुमान लगाने के लिए इन आंकड़ों का उपयोग किया है। इससे लोगों के सामने नई जानकारी सामने आई है, जिसका फिर से विश्लेषण किया जाएगा।

टिश्यू इमेजिंग करने वाली दुनिया की पहली एंडोस्कोप प्रणाली विकसित

नई दिल्ली, आइएएनएस : जापान के विज्ञानियों ने दुनिया की पहली रिजिड एंडोस्कोप प्रणाली विकसित की है, जो दृश्यमान से लेकर हजारों नैनोमीटर (ओटीएन) छोटे तरंग दैर्ध्य तक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग (एचएसआइ) करने में सक्षम है। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से जानकारी एकत्र व संसाधित करती है। यह नई प्रणाली सर्जरी के दौरान टिश्यू इमेजिंग करने में मददगार साबित होगी।

रिजिड एंडोस्कोप का प्रयोग मुंह, गले, श्वासनली और ग्रासनली की समस्याओं की जांच के लिए किया जाता है। टोक्यो यूनिवर्सिटी आफ साइंस (टीयूएस) की टीम ने कहा है कि भले ही विभिन्न प्रकार के इमेजिंग उपकरण विकसित किए जा चुके हैं। लेकिन हजारों नैनोमीटर छोटे तरंग दैर्ध्य के लिए सामान्य कैमरे अपनी संवेदनशीलता खो देते हैं और केवल कुछ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध लेंस ही इसका विश्लेषण कर पाते हैं।

चार घंटे शारीरिक गतिविधि व आठ घंटे नींद स्वास्थ्य के लिए बेहतर

अनुसंधान

शोधकर्ताओं ने एक ताजा शोध में चार घंटे से अधिक शारीरिक गतिविधि और कम से कम आठ घंटे की नींद को अच्छे स्वास्थ्य के लिए आदर्श स्थिति बताया है। शारीरिक गतिविधि में हल्का, मध्यम या जोदार व्यायाम शामिल है। शोध दल ने कहा कि आदर्श दैनिक दिनचर्या में छह घंटे बैठना और पांच घंटे खड़े रहना भी शामिल होना चाहिए।

शोधकर्ताओं ने कहा कि हल्की-फुल्की गतिविधि घर के काम करने से लेकर रात का खाना बनाने तक हो सकती है, जबकि मध्यम और जोरदार व्यायाम में तेज चलना या जिम वर्कआउट जैसी गतिविधि शामिल होती है। आस्ट्रेलिया के स्विनबर्न यूनिवर्सिटी आफ टेक्नोलाजी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय टीम ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए बैठने, सोने, खड़े होने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने में बिताए गए समय का सही मिश्रण निर्धारित करने के लिए 24 घंटे के भीतर 2,000 से अधिक लोगों के व्यवहार का विश्लेषण किया। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी आफ टेक्नोलाजी के सेंटर फार अर्बन ट्रांजिशन के क्रिश्चियन ब्रैकेनरिज ने कहा कि यह ब्रेकडाउन स्वास्थ्य मार्कर्स की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है।

शोधकर्ताओं का निष्कर्ष डायबेटोलोजिया जर्नल में प्रकाशित हुआ है। प्रमुख लेखक ब्रैकेनरिज ने कहा कि विभिन्न मार्कर्स के लिए कमर की परिधि से लेकर फास्टिंग ग्लूकोज तक हर व्यवहार के लिए अलग-अलग स्तर होंगे। शोध दल ने सुझाव दिया कि व्यायाम की अवधि 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे नींद में कटौती कर नहीं किया जाना चाहिए। दोनों का संतुलन जरूरी है। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

जब चमकीला की पहली पत्नी से डर रहे थे इम्तियाज

फिल्म अमर सिंह चमकीला के निर्देशक हैं इम्तियाज। इस्टाग्राम (@imtiazalioffical)

किसी की जिंदगानी पर जब फिल्म बनाई जाती है, तो कई बार उसे कुछ लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, तो कई बार खूब सराहना भी मिल जाती है। पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला की बायोपिक बना चुके निर्देशक इम्तियाज अली भी डरे हुए थे, जब फिल्म देखने के लिए उनके बगल में ही चमकीला की पहली पत्नी बैठी हुई थीं। यह किस्सा साझा करते हुए इम्तियाज ने एक साक्षात्कार में कहा कि चमकीला का पूरा परिवार फिल्म की स्क्रीनिंग में आया हुआ था। उनकी पहली पत्नी गुरमेल कौर, चमकीला की दूसरी पत्नी अमरजोत कौर का बेटा जैमन चमकीला और उनकी बेटियां सब मौजूद थे। स्क्रीनिंग में गुरमेल कौर मेरे बगल में बैठी थीं। फिल्म में कुछ संवेदनशील सीन भी थे। मुझे लगा कि मैं कहीं उठकर चला जाता हूं, इससे पहले की वह मुझ पर हमला कर दें। लेकिन जब स्क्रीनिंग खत्म हुई, तो उन्होंने मुझे गले लगाया। जिस तरह से चमकीला की जिंदगी को फिल्म में दिखाया गया था, वह उससे खुश थीं। ऐसा नहीं था कि मैंने फिल्म में केवल चमकीला की अच्छी-अच्छी बातों को ही दिखाया है। उनकी जिंदगी में जो जैसा था, मैंने उसे वैसा ही दिखाया है। उनके परिवार को धन्यवाद कहूंगा, जिन्होंने इस बात को समझा। वह सच जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ भी दिखाने से रोका नहीं।

'खेल खेल में' फिल्म में अक्षय कुमार, वाणी कपूर, तापसी पन्नू, आदित्य सील, फरदीन खान, प्रज्ञा जायसवाल और एमी विर्क अहम भूमिकाओं में हैं ● @adityaseal (इस्टाग्राम)

द एम्पायर का दूसरा सीजन बनने की उम्मीद कम

आदित्य ने साल 2021 में प्रदर्शित वेब सीरीज द एम्पायर के दूसरे सीजन को साइन किया था। हालांकि, अब उसके बनने की संभावनाएं कम हैं। वह कहते हैं, 'उस शो को लेकर काफी विवाद हो गया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इसका दूसरा सीजन बनने की कोई संभावनाएं हैं। मेरे लिए वह शो एक बड़ा मौका था। दरअसल, पहले मुझसे उस शो में बाबर की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन तब मैं उसी प्रोडक्शन हाउस के एक अन्य प्रोजेक्ट की शूटिंग में व्यस्त था। फिर निर्माताओं ने मुझे हुमायूं की भूमिका देने का निर्णय लिया। मैंने शो साइन भी उसी चक्कर में किया था कि अगले सीजन में पूरी कहानी हुमायूं के इर्द-गिर्द होगी।'

हनुमैन के निर्देशक प्रशांत वर्मा की फिल्म में राक्षस बनेंगे रणवीर

फिर निगेटिव अंदाज में दिखेंगे रणवीर सिंह ● मिडडे आर्काइव

पिछले दिनों खबरें आई थी कि अभिनेता रणवीर सिंह हनुमैन फिल्म के निर्देशक प्रशांत वर्मा के साथ फिल्म कर सकते हैं। अब फिल्म का नाम भी सामने आ गया है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार प्रशांत के सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनने वाली इस फिल्म का नाम राक्षस होगा। इस यूनिवर्स में जिस तरह से प्रशांत अपनी फिल्मों के किरदारों को साथ लाएंगे, उस कल्पना से ही रणवीर काफी प्रभावित हैं। फिल्म की कहानी और पटकथा तैयार है। अब मेकर्स समय का तालमेल बिठाने में लगे हैं, ताकि शूटिंग शुरू की जा सके। हैदराबाद में प्रशांत और रणवीर ने इस फिल्म के लिए हनुमान जयंती के मौके पर एक पूजा भी की थी। राक्षस पीरियड फिल्म होगी, जिसे स्वतंत्रता से पहले के दौर में सेट किया जाएगा। इसकी पृष्ठभूमि पौराणिक होगी। रणवीर के किरदार में निगेटिव शेड्स होंगे। इस फिल्म के अलावा उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के निर्देशक आदित्य धर के साथ भी एक फिल्म को लेकर रणवीर की बातचीत चल रही है।

कथित ब्वायफ्रेंड राहुल मोदी के साथ फिल्म कर सकती हैं श्रद्धा कपूर

कलाकारों के पेशेवर जीवन की बात हो या निजी जीवन की, इंटरनेट मीडिया के इस दौर में कोई भी बात ज्यादा समय तक छुपाए रख पाना मुश्किल होता है। अब अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की ही बात करें, तो श्रद्धा पिछले कुछ दिनों से लेखक राहुल मोदी के साथ प्रेम प्रसंगों को लेकर काफी चर्चा में हैं। पिछले साल उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग समारोह में जब दोनों साथ देखें गए, तो इस चर्चा को हवा मिल गई। अब खबरें हैं कि दोनों की योजना इस मजबूत जुड़ाव को पेशेवर स्तर पर भी आगे ले जाने की है। दरअसल, श्रद्धा की एक फिल्म को लेकर राहुल से बातचीत चल रही है, जिसे राहुल स्वयं प्रोड्यूस करेंगे। इतना ही नहीं, अगर सभी चीजें सही रहती हैं, तो श्रद्धा बतौर को प्रोड्यूसर इस फिल्म से प्रोडक्शन में कदम रख सकती हैं। चूंकि फिल्म को लेकर बातचीत अभी शुरुआती चरणों में हैं, इसलिए अभी इससे जुड़ी जानकारियों पर रहस्य बरकरार रखा है। हालांकि, श्रद्धा को फिल्म की कहानी पसंद आई है, आगे का निर्णय वह फिल्म की पटकथा तैयार होने के बाद लेंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्मों के चुनाव को लेकर खूब सतर्कता बरतने वाली श्रद्धा राहुल की फिल्म को किन पैमाने पर परखती हैं?

स्त्री 2 होगी श्रद्धा की आगामी फिल्म

मैं कहीं से निकला था, आज कहीं और पहुंच गया : मानव विज

कई कलाकार इंडस्ट्री में ऐसे हैं, जो कला के इस क्षेत्र में आने से पहले कुछ और काम किया करते थे। किस्मत उन्हें अभिनय के पेशे में ले आई। तनाव वेब सीरीज अभिनेता मानव विज भी उन्हीं में शामिल हैं, जो कभी होमियोपैथी डाक्टर हुआ करते थे। मानव का मानना है कि वह अभिनय की पढ़ाई करके नहीं आए हैं, इसलिए उनके काम करने की प्रक्रिया दूसरे कलाकारों से थोड़ी अलग है। दैनिक जागरण से बातचीत में मानव कहते हैं कि मेरी अभिनय करने की प्रक्रिया अलग जरूर है, लेकिन अनोखी नहीं है। मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं हटकर हूं, लेकिन मेरा सोचने का तरीका बाकी कलाकारों से अलग है। मैं अलग राह से यहां तक पहुंचा हूं। मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है, जहां हर बात के लिए शुक्रिया कहना सिखाया गया है। मुझमें असुरक्षा की भावना नहीं है। यह सोच मेरी मम्मी और नाना की रही है, इसलिए मैं भी ऐसा हूं। मैं कहीं से निकला था, आज कहीं और पहुंच गया हूं, तो तरीका अलग तो है। डाक्टरी की पढ़ाई-लिखाई मानव के अब कितना काम आती है? इस पर वह कहते हैं कि पढ़ाई-लिखाई तो व्यक्ति कभी भूलता नहीं है। कभी किसी को कोई जरुरत होती है, तो उसे बता देता हूं कि फलां चीज करके देख लो।

डाक्टर से अभिनेता बने हैं मानव। इस्टाग्राम (@manavvij)

शेड्यूल से पहले ही खत्म हो गई 'खेल खेल में' की शूटिंग

आमतौर पर फिल्मों की शूटिंग तय शेड्यूल से पीछे चलने या विलंब से होने की खबरें आती हैं। मगर जहां, समय के पाबंद माने जाने वाले हिंदी सिनेमा के खिलाड़ी अभिनेता अक्षय कुमार हो, वहां ऐसी संभावनाएं बहुत कम ही देखने को मिलती है। मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी अक्षय की आगामी फिल्म खेल खेल में की शूटिंग के दौरान भी अक्षय ने अपना पेशेवर रवैया दिखाया जिससे फिल्म की शूटिंग तय शेड्यूल से पहले ही खत्म हो गई। छह सितंबर को प्रदर्शित हो रही इस फिल्म में अक्षय के साथ वाणी कपूर, तापसी पन्नू, आदित्य सील, फरदीन खान, प्रज्ञा जायसवाल और एमी विर्क जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म के लेकर दैनिक जागरण से बातचीत में आदित्य बताते हैं, 'हमारी फिल्म जयपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। जैसा कि इस फिल्म का नाम है, वैसे ही हमने खेलते-कूदते हुए इसकी शूटिंग भी की है। फिल्म में सारे कलाकार इतने मंझे हुए और पेशेवर हैं कि हमने फिल्म की शूटिंग बहुत जल्दी खत्म कर ली। मजे की बात यह है कि अक्षय सर ने सेट पर बहुत अच्छा माहौल बना रखा था। सेट पर पूरी मस्ती होती थी, सभी साथ में बैठकर लंच करते थे। यहां तक कि हम शेड्यूल से आगे चल रहे थे, तो हम कभी-कभी सेट पर ही लूडो खेला करते थे।'

संवादों और दृश्यों में अक्षय ने किए कई सुधार: अपने अनुभवों के अनुसार अक्षय कुछ गलत लगने पर फिल्म के संवादों और दृश्यों में सुधार करने में भी पीछे नहीं हटते। आदित्य बताते हैं, 'शूटिंग के दौरान अक्षय सर के अनुभवों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वह सेट पर इंप्रोवाइज (सुधार) करने में इतने माहिर हैं कि उनका कोई जवाब नहीं। वह सिर्फ अपनी पंक्तियां ही नहीं, पूरा सीन इंप्रोवाइज कर देते हैं। उन्होंने मुझे कई बार बताया कि क्या और कैसे करना है।'

अक्षय से पहली मुलाकात: अक्षय से अपनी पहली मुलाकात को लेकर आदित्य बताते हैं, 'अक्षय सर से मेरी पहली फिल्म धड़कन के सेट पर हुई थी। दरअसल मुझे ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट मिला था। मेरी वह तस्वीर एक अखबार में छपी थी। मैंने अक्षय सर को वह तस्वीर दिखाई। उसके बाद अक्षय सर से मुलाकात सीधे इस फिल्म के रिहर्सल के दौरान हुई थी।'

वापसी में इमरान को मिला मामा आमिर का साथ

नौ वर्ष बाद वापसी के लिए तैयार हैं इमरान। इस्टाग्राम (@imrankhan)

साल 2015 में प्रदर्शित फिल्म कट्टी बट्टी की असफलता के निराश होकर अभिनेता इमरान खान ने अभिनय से दूरी बना ली थी। मगर पिछले दो वर्षों से अभिनय में उनकी वापसी की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरीं। अब इमरान दमदार वापसी के लिए कमर कस चुके हैं। खास बात यह है कि वापसी में उन्हें उनके मामा और हिंदी सिनेमा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट अभिनेता आमिर खान का भी साथ मिला है। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, इमरान, वीर दास के निर्देशन में बन रही फिल्म हैप्पी पटेल से वापसी कर रहे हैं। वह फिल्म में शीर्षक भूमिका में होंगे। फिल्म को उनके मामा यानी आमिर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं आमिर इस फिल्म में अभिनय करते भी नजर आएंगे। वह फिल्म में मेहमान भूमिका में होंगे। व्यंगात्मक अंदाज में बन रही इस स्पाई (जासूसी) थ्रिलर फिल्म की कहानी गोवा की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी, जिसमें आमिर डान की मेहमान भूमिका में दिखेंगे। फिल्म की शूटिंग पहले शूरू हो चुकी है और रिपोर्ट्स की मानें तो आमिर इस फिल्म में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी भी कर चुके हैं। इसके अलावा इस फिल्म में शारीब हाशमी, मिथिला पालकर और मोना सिंह जैसे कलाकारों के भी अहम भूमिकाओं में होने की खबरें हैं।

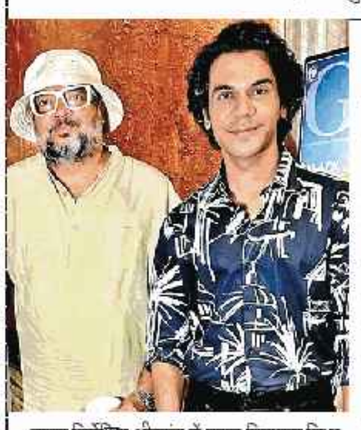

तुषार निर्देशित श्रीकांत में मुख्य किरदार निभा रहे हैं राजकुमार @tusharhiranandani

साल भर लग गए श्रीकांत फिल्म के अधिकार लेने में

निर्देशक तुषार हिरानंदानी को बायोपिक के लिए कहानियों के अधिकार हासिल करने का अच्छा खासा अनुभव हो गया है। सांड की आंख और स्कैम 2003 : द तेलगी स्टोरी के बाद तुषार फिर से बायोपिक फिल्म श्रीकांत - आ रहा है सबकी आंखें खोलने ले आए हैं। यह फिल्म नेत्रहीन उद्योगपति श्रीकांत बोला की जिंदगानी पर बनी है। दैनिक जागरण से बातचीत में तुषार कहते हैं, 'मैं बायोपिक्स इसलिए ज्यादा बनाता हूं, क्योंकि मुझे वह लोग हीरो लगते हैं। दिव्यांगों पर कई कहानियां बनी हैं, लेकिन मुझे श्रीकांत की जिंदगी बहुत प्रेरणादायक लगी। वह खुद को कमजोर या बेचारा नहीं समझते हैं। कई बार मेकर्स ऐसी कहानियों को या तो कामेडी या बहुत ट्रैजिक बना देते हैं। मुझे उन्हें हीरोइक अंदाज में दिखाना था। श्रीकांत से उनकी जिंदगानी पर फिल्म बनाने के अधिकार लेने से लेकर यह फिल्म बनाने तक मुझे पांच साल लगे। पहले उनकी बायोपिक बनाने के राइट्स किसी और के पास थे। वहां से मेरे पास आते-आते ही एक साल लगा। मुझे वास्तविक कहानियों को मसाला फिल्मों के अंदाज में पेश करना पसंद है। श्रीकांत की जिंदगी के अहम मोड़ मैंने फिल्म में जरूर लिए हैं, लेकिन उसके अलावा सब कुछ क्रिएट किया है, क्योंकि इसे डाक्यूमेंट्री नहीं बनानी थी।'

****